

# **भारत का राजपत्र** **The Gazette of India**

प्राधिकार से प्रकाशित  
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 9, 1971/पीष 19, 1892  
 No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 9, 1971/PAUSA 19, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सक ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
 as a separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड—(ii)

### PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर)  
 केन्द्रीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किये गए विधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).

### ELECTION COMMISSION OF INDIA

*New Delhi, the 19th December 1970*

**S.O. 117.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950, the Election Commission, in consultation with the Government of Madhya Pradesh, hereby nominates Shri L. B. Sarje, Special Secretary to Government of Madhya Pradesh, Revenue Department, as the Chief Electoral Officer for the State of Madhya Pradesh with effect from the date he takes over charge and until further orders *vice* Shri M. S. Chaudhary.

[No. F. 154/6/70]

By Order,  
 ROSHAN LAL, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1970

एस० ओ० 117.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श

से, श्री एम० एस० चौधरी के स्थान पर, मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के विशेष सचिव, श्री एल० बी० सरजे को पद का प्रभार संभालने की तारीख से अगले आदेशों तक मध्य प्रदेश राज्य के लिए मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में एतद्द्वारा नाम निर्देशित करता है।

[सं० 154/6/70]

आदेश से,

रोशन लाल,

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

*New Delhi, the 19th December 1970*

**S.O. 118/CP&EO/12/70.**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Emigration Act 1922 (VII of 1922), the Central Government hereby appoints Shri B. V. S. Rao to be Protector of Emigrants, Nagapattinam with effect from the afternoon of 30th November 1970, vice Shri R. Muthuswamy.

[No. F.3(24)V.IV/60.]

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1970

**एस० ओ० 118/सी० पी० एड ई० ओ०/12/70.**—उत्प्रवास अधिनियम 1922 (1922 का VII) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री बी० वी० एस० राव को 30 नवम्बर, 1970 के अपराह्न से, श्री आर० मुद्दुस्वामी के स्थान पर, नागपट्टिनम् में उत्प्रवासी-संरक्षक नियुक्त करती है।

[सं० 3 (24) पी वी IV/69]

*New Delhi, the 22nd December 1970*

**S.O. 119/CP&EO/13/70.**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Emigration Act 1922 (VII of 1922), the Central Government hereby appoints Shri H. Kasim to the Protector of Emigrants, Mandapam Camp and Tuticorin with effect from the forenoon of 3rd December 1970, vice Shri P. N. Nair.

[No. F. 3(178)V.IV/60.]

D. S. KHOSLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1970

**एस० ओ० 119/सी० पी० एड ई० ओ०/13/70.**—उत्प्रवास अधिनियम 1922 (1922 का VII) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एच० कासिम खान को 3 दिसम्बर 1970 के पूर्वान्त्र से श्री पी० एन० नायर के स्थान पर मंडपम केम्प और तूतीकोरिन में उत्प्रवासी-संरक्षक नियुक्त करती है।

[सं० 3 (178) पी० वी० IV/60]

डी० एस० खोसला, अवर सचिव।

*New Delhi, the 23rd December 1970*

**S.O. 120.**—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948, the Central Government hereby authorises Shri Narinder Singh, Asstt., in the Consulate General of India, Muscat, to perform the duties of a Consular Agent, with effect from the 20th December, 1970, until further orders.

[No. F. T. 4330/2/70.]

P. C. BHATTACHARJEE, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1970

**एस० ओ० 120.**—राजनयिक एवं कोंसली (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 के खण्ड 2 धारा (क) के अनुसार, केन्द्र सरकार इसके द्वारा भारत का प्रधान कोंसलावास मस्कत में सहायक श्री नरिन्दर सिंह को 20 दिसम्बर, 1970 से, अगला आदेश होने तक, कोंसली अधिकर्ता का कार्य करने का अधिकार देती है।

[सं० टी० 4330/2/70]

पी० सी० भट्टाचार्य, अधर सचिव।

## MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

*New Delhi, the 29th November 1970*

**S.O. 121.**—In exercise of the powers conferred by Section 147A of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government hereby adds to the Second Schedule to the said Act the following articles, namely:—

Terylene, Terycot, Terywool and Nylon and their fabrics.

[No. TCH/2425/70.]

C. S. PARAMESWARAN, Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1970

**एस० ओ० 121.**—भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9 वां) की धारा 147-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित वस्तुओं के नाम जोड़ती है, अर्थात् :

टेरिलीन, टेरिकोट, टेरिबुल, और नायलान और इनसे बने वस्त्र।

[सं० टी० सी० 11/2425/70]

सी० एस० परमेश्वरन, सचिव।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 21st December 1970

**S.O. 122.**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (6 of 1952), the Central Government hereby extends upto the 30th June, 1971, the period within which the Commission of Inquiry appointed by the Government of India in the Ministry of Home Affairs by Notification No. S.O. 2375, dated the 11th July, 1970 shall make its report to the Central Government.

[No. F. 25/14/70-Pol. II]

R. VASUDEVAN, Dy. Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1970

का० आ० 122.—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने एतद्वारा वह अवधि, जिसमें भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय में अधिसूचना सं० का० आ० 2375 दिनांक 11 जुलाई, 1970 द्वारा नियुक्त जांच आयोग सरकार को अपना प्रतिवेदन देगा, 30 जून, 1971 तक बढ़ा दी जाती है।

[सं० एफ० 25/14/70-पोल० II]

आर० वासुदेवन, उप सचिव।

New Delhi, the 31st December 1970

**S.O. 123.**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 1104 dated the 29th March, 1965, namely:—

In the said notification in paragraph 4 for the figures, letters and words "31st December, 1970" the figures, letters and words "31st March, 1971" shall be substituted.

By Order,

And in the name of the President of India.

[No. 1/3/65-Delhi.]

R. C. GUPTA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1970

सा० आ० 123.—जांच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा० आ०-1104 दिनांक 29 मार्च 1965 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 4 में, अंक, अक्षर और शब्द "31 दिसम्बर, 1970" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 1971" प्रतिस्थापित किये जायेंगे

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उसके नाम में

[सं० 1/3/65-दिल्ली]

आर० सी० गुप्ता, उप सचिव।

New Delhi, the 31st December 1970

S.O. 124.—The following Order made by the President is published for general information:—

ORDER

In exercise of the powers conferred by clause (6) of article 344 of the Constitution, the President hereby directs that the Ministry of Home Affairs may undertake the translation of all manuals and procedural literature other than statutory rules, regulations and orders and makes the following amendment in the Order published with the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, No. S.O. 1090, dated the 27th April, 1960, namely:—

In the said Order, in paragraph 4, for the words "Ministry of Education" the words "Ministry of Home Affairs" shall be substituted.

V. V. GIRI,  
President.

[No. F. 5/62/69-OL.]  
L. P. SINGH, Secy.

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1970

सं० आ० 124.—राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 344 के खण्ड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निदेश देते हैं कि सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों के अतिरिक्त सभी मैन्युअलों और कार्यविधि साहित्य के अनुवाद का काम गृह मंत्रालय अपने हाथ में ले ले और वे भारत सरकार, गृह मंत्रालय की 27 अप्रैल, 1960 की अधिसूचना सं० सां० आ०-1090 में प्रकाशित आदेश में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, पैरा 4 में, "शिक्षा मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर "गृह मंत्रालय" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे

वी० वी० गिरि,  
राष्ट्रपति ।

[सं० 5/62/69-रा० आ०]  
ल० प्र० सिंह, सचिव ।

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 7th December 1970

S.O. 125.—In exercise of the powers conferred by Sub-Clause (1) of Clause 21 C of the Cotton Textiles (Control) Order, 1948, the Central Government hereby specifies:—

- (i) 6 paise per square metre as the rate for the purposes of paragraph (b) of Sub-Clause (1) of Clause 21 C aforesaid; and
  - (ii) 6 paise per square metre for grey dhoti and saree and 4 paise per square metre for other varieties as the rates for the purposes of paragraph (a) of Sub-Clause (1) of Clause 21C aforesaid;
- for the quarter ending with 31st January, 1971.

[No. F. 7/5/70-Tex.A.]  
H. K. BANSAL, Dy. Secy.

## विदेश व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1970

का० प्रा० 125.—सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 के खण्ड 21 ग के उप-खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 31 जनवरी, 1971 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए ;

- (1) उपरोक्त खण्ड 21 ग के उपखण्ड (1) की कंडिका (ख) के प्रयोजन के लिए 6 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर ; तथा
- (2) उपरोक्त खण्ड 21 ग के उपखण्ड (1) की कंडिका (क) के प्रयोजन के लिए कोरी छोती तथा साड़ी हेतु 6 पैसे प्रति वर्ग मीटर और अन्य किस्मों हेतु 4 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दरें, एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है।

[नं० का० 7/5/70-टैक्स-क]

एच० के० बंसल, उप-सचिव।

## CARDAMOM CONTROL

New Delhi, the 31st December 1970

S.O. 126.—In pursuance of sub-section (3) of section 4 of the Cardamom Act, 1965 (42 of 1965), the Central Government hereby appoints Shri K. V. George, Director of Cardamom Development, as the Chairman of the Cardamom Board, for the period beginning from the 4th November, 1969 and ending with the 18th January, 1970 (both days inclusive) vice Dr. K. T. Jacob, retired.

[No. 29(25)Plant(B)/69.]

N. N. MALHAN, Dy. Director.

## इलायची नियंत्रण

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1970

सा० प्रा० 126.—इलायची अधिनियम, 1965 (1965 का 42) की धारा 4 की उप-धारा 3 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, इलायची विकास निदेशक श्री के० वी० जार्ज को, डा० के० टी० जैकब जो सेवा-निवृत्त हो गए हैं, के स्थान पर, 4 नवम्बर, 1969 से प्रारम्भ होकर 18 जनवरी, 1970 तक (दोनों दिन मिलाकर) समाप्त होने वाली अवधि के लिए, इलायची बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० 29(25)-प्लांट (बी) 69]

एन० एन मल्हन, उप-निदेशक।

(Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Exports)

## ORDERS

Calcutta, the 2nd May 1970

SUBJECT:—Order cancelling the Customs Purposes Copy of Licence No. P/E/0144673/C/XX/27/C\$27-28 dated 12th June, 1968 in connection with the issue of duplicate copy of the same.

S.O. 127.—M/s. Marshall, Sons & Co. (I) Ltd., 33/1, Netaji Subhas Road, Calcutta were granted an import licence No. P/E/0144673/C/XX/27/C/27-28, dated 12th June, 1968 for Rs. 2,68,770/-.

They have now applied for a duplicate copy of Customs Purposes of the said licence on the ground that the original Customs Purposes Copy of the above licence has been lost after partly utilised to the extent of Rs. 84,308/- (Rupees eighty-four thousand three hundred and eight only).

In support, the applicant has filed an affidavit to the effect that the original Customs Copy of the above mentioned licence has been lost. I am satisfied that original Customs Copy of the licence has been lost and I have directed that a duplicate copy of the said licence in question should be issued to the applicant. The original Customs Copy of the above licence is cancelled.

[No. 7.]

### संयुक्त मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात का कार्यालय

#### आदेश

कलकत्ता, 2 मई, 1970

**विषय:** लाइसेंस सं० पी/ई/0144673/सी/एक्स एक्स/27/सी/27-28, दिनांक 12-6-68 की सीमा-शुल्क कार्य प्रति को रद्द किया जाना और उसी की अनुलिपि प्रति जारी किए जाने के बारे में आदेश।

**एस० ओ० 127.**—सर्वश्री मार्शल/सन्स एन्ड कम्पनी (इन्डिया) लिमिटेड, 33/1, नेता जी सुभाष रोड, कलकत्ता को 2,68,770 रुपये का एक आयात लाइसेंस संख्या पी/ई/0144673/सी/एक्स एक्स/27/सी/27-28 दिनांक 12-6-68 स्वीकृत किया गया था।

अब उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क कार्य प्रति की अनुलिपि प्रति के लिए आवेदन किया है, इसके लिए उन्होंने यह आधार दिया है कि 84,308 (चौरासी हजार तीन सौ आठ रुपये मात्र) रुपये तक आंशिक उपयोग करने के बाद उक्त लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क कार्य प्रति खो गई है।

अपने समर्थन में, आवेदक ने यह बताते हुए एक शपथ पत्र जमा किया है कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क कार्य प्रति खो गई है। मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि मूल सीमा-शुल्क कार्य प्रति खो गई है और मैंने निवेश किया है कि उक्त लाइसेंस के सम्बन्ध में आवेदक को उसकी अनुलिपि प्रति जारी की जानी चाहिए। उक्त लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रति रद्द की जाती है।

[सं० 7]

*Calcutta, the 11th May, 1970*

**SUB.—Order cancelling the Customs purpose copy of licence No. P/E/0168377/C/XX/31/C/29-30 dated 17th June, 1969 in connection with the issue of duplicate copy of the same.**

**S.O. 128.**—M/s. Queen Stationery Stores Pvt. Ltd., 63E, Radha Bazar Street, Calcutta-1, were granted import licence No. P/E/0168377/C/XX/C/29-30 dated 17th June, 1969 for Slide Rule for Rs. 1,000/- (Rupees one thousand only).

They have now applied for issue of a duplicate of the Customs purpose copy of the said licence on the ground that the original has been lost. It is further stated that the original licence has not been registered with the Customs and has not been utilised.

In support of this contention, the applicant has filed an affidavit. I am satisfied that the original Customs purpose copy of licence No. P/E/0168377/C/XX/31/C/29-30 dated 17th June 1969 has been lost and direct that duplicate of the Customs purpose copy be issued to the applicant. The original Customs purpose copy of the licence is cancelled.

[No. 92(g) (2)-V/4/AM'70/E.I.-I.]

कलकत्ता, 11 मई 1970

विषय: लाइसेंस सं० पी/ई/0168377/सी/एक्स एक्स/31/सी/29-30, दिनांक 17-6-69, को सीमा-शुल्क कार्य प्रति को रद्द किया जाना और उसी की अनुलिपि प्रति जारी किए जाने के बारे में आदेश।

एस० ओ० 128.—सर्वश्री क्वीन स्टेशनरी स्टोर्स प्राइवेट लि०, 63 ई, राधा बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता-1 को 1,000 (एक हजार रुपये मात्र) रुपये स्लाइड रूल के लिए आयात लाइसेंस सं० पी/ई/0168377/सी/एक्स एक्स/31/सी/29-30, दिनांक 17-6-69 स्वीकृत किया गया था।

अब उन्होंने उक्त लाइसेंस को सीमा-शुल्क कार्य प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए आवेदन किया है, इसके लिए उन्होंने यह आधार दिया है कि मूल प्रति खो गई है। आगे यह बताया गया है कि मूल लाइसेंस सीमा-शुल्क कार्यालय में पंजीकृत नहीं किया गया है और न उसका कोई उपयोग ही किया गया है।

अपने तर्कों के समर्थन में, आवेदक ने एक शपथ पत्र जमा किया है। मैं इस बात से सन्तुष्ट हूँ कि लाइसेंस संख्या पी/ई/0168377/सी/एक्स एक्स/31/सी/29-30, दिनांक 17-6-69 की मूल सीमा-शुल्क कार्य प्रति खो गई है और निदेश देता हूँ कि सीमा शुल्क कार्य प्रति की अनुलिपि आवेदक को जारी की जाए। लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क कार्य प्रति रद्द की जाती है।

[संख्या 92(जी)(2)-5/4/ए० एम० 70/ई० आई०-1]

Calcutta, the 8th June, 1970

SUB.—Order Cancelling the customs purposes copy of licence No. P/E/0168679/C/XX/32/C/29-30 dated 16th July, 1969 in connection with issue of duplicate copy of the same.

S.O. 129.—M/s. J. K. Ghosh & Sons, 71, Canning Street, Calcutta-1 were granted import licence No. P/E/0168679/C/XX/32/C/29-30 dated 16th July, 1969 for Medical including surgical instruments, equipment and appliances and parts thereof, not made mainly of rubber and not made mainly of glass for Rs. 1,350/- (Rupees one thousand three hundred and fifty only).

They have now applied for issue of a duplicate of the customs purpose copy of the said licence on the ground that the original has been lost. It is further stated that the original licence has not been utilised.

In support of this contention, the applicant have filed an affidavit. I am satisfied that the original customs purpose copy of licence No. P/E/0168679/C/XX/32/C/29-30 dated 16th July, 1969 has been lost and direct that duplicate of the customs purpose copy be issued to the applicant. The original customs purpose copy of the licence is cancelled.

[No. 93-94(c)-V/44/AM'70/EI-I.]

कलकत्ता, 8 जून, 1970

विषय: लाइसेंस सं० पी/ई/0168679/सी/एक्स एक्स/32/सी/29-30, दिनांक 16-7-69 को सीमा-शुल्क कार्य प्रति को रद्द किए जाने और उसी की अनुलिपि प्रति जारी किए जाने के बारे में आदेश।

एस० ओ० 129.—सर्वश्री जे० के० घोष एन्ड सन्स, 71 कैनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता-1 को मेडीकल तथा शल्य औजार उपस्कर और साधन और उसके पुर्जे सहित जो प्रमुखता से रबड़ के नहीं बने हुए थे और न वे मुख्य रूप से कांच के बने हुए थे, उनके लिए 1,350 (एक हजार तीन सौ पचास रुपये मात्र) रुपये के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी/ई/0168679/सी/एक्स एक्स/32/सी/29-30, दिनांक 16-7-1969 स्वीकृत किया गया था।



अब उन्होंने उक्त लाइसेंस को सीमा शुल्क कार्य प्रति की अनुलिपि प्रति जारी किए जाने के लिए आवेदन किया है, इसके लिए उन्होंने यह आधार दिया है कि मूल प्रति खो गई है। उन्होंने आगे यह भी बताया है कि मूल लाइसेंस का उपयोग नहीं किया गया है।

इस तर्क के समर्थन में, आवेदक ने एक शपथ-पत्र जमा किया है। मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि लाइसेंस सं० पी/ई/0168679/सी/एक्स एक्स/32/सी/29-30, दिनांक 16-7-69 की मूल सीमा-शुल्क कार्य प्रति खो गई है और निदेश देता हूँ कि सीमा-शुल्क कार्य प्रति की अनुलिपि प्रति आवेदक को जारी की जाय / लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क कार्य प्रति रद्द की जाती है।

[संख्या 93-94/ई०)-5/44/ए० एम० 70/ई० आई०-1.]

Calcutta, the 7th July, 1970

**SUBJECT.**—Order cancelling both the Customs purposes copy and the Exchange Control purposes copy of licence No. P/E/0169129/C/XX/32/C/29-30 dated 5th August 1960 issued in favour of M/s. Heatly & Gresham Ltd., 31, Chittaranjan Avenue, Calcutta in connection with the issue of duplicate copies for the same for Rs. 1000 only.

**S.O. 130.**—M/s. Heatly & Gresham Ltd., 31, Chittaranjan Avenue. Calcutta-12 were granted an Import licence No. P/E/0169129/C/XX/32/C/29-30 dated 5th August, 1969 for Rs. 1000/-.

They have now applied for issuance of duplicate copies of both Customs purposes copy and Exchange Control purposes copy of the said licence on the ground that the original customs copy and Exchange Control purposes copy of the above licence have been lost fully unutilised.

In support of the same, the applicant has filed an affidavit to the effect that the original Customs and Exchange Control purposes copy of the above mentioned licence have been lost.

I am satisfied that original Customs and Exchange Control purposes copy of the licence has been lost and I have directed that duplicate copies of both the said licence in question should be issued to the applicant. The Original Customs and exchange Control purposes copy of the above licence is cancelled.

[No. 9. EI-II.]

M. S. PURI,

Deputy Chief Controller of Imports & Exports.  
for Jt. Chief Controller of Imports & Exports.

कलकत्ता, 7 जुलाई, 1970

**विषय:** सर्वश्री हेटली एन्ड ग्राशम लि०, 31 चित्तरंजन एवन्यू, कलकत्ता को 1,000 रुपये माल के लिए जारी किया गया लाइसेंस सं० पी/ई/0169129/सी/एक्सएक्स/32/सी/29-30 दिनांक 5-8-69 की सीमा शुल्क कार्य प्रति और मुद्रा नियंत्रण कार्य प्रति दोनों को रद्द किया जाना और उसी के लिए अनुलिपि प्रतियां जारी किए जाने के बारे में आदेश।

**एस० ओ० 130.**—सर्वश्री हेटली एन्ड ग्राशम लि०, 31 चित्तरंजन एवन्यू कलकत्ता-12 को 1000 रुपये का आयात लाइसेंस सं० पी/ई/0169129/सी/एक्स एक्स/32/सी/29-30 दिनांक 5-8-1969 स्वीकृत किया गया था।

उन्होंने सीमा-शुल्क और मुद्रा नियंत्रण कार्य दोनों की प्रतियों के लिए उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रतियां जारी करने के लिए आवेदन किया है इसके लिए उन्होंने यह आधार दिया है कि सीमा-शुल्क और मुद्रा नियंत्रण कार्य प्रतियां खो गई हैं तथा उनका उपयोग बिल्कुल नहीं किया गया है।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र जमा किया है कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क और मुद्रा नियंत्रण कार्य दोनों प्रतियां खो गई हैं।

मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क और मुद्रा नियंत्रण कार्य दोनों प्रतियां खो गई हैं और निदेश देती हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रतियां आवेदक को जारी की जाएं। उपर्युक्त लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क और मुद्रा नियंत्रण कार्य दोनों प्रतियां रद्द की जाती हैं ॥

[सं० 9 ई० आई०-2]

एम० एस० पुरी,

उप-मुख्यनियंत्रक, आयात-निर्यात,

वास्ते संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात ॥

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 29th September 1970

S.O. 131.—M/s. J. K. Rayon, Kamla Tower, Kanpur, were granted licence No. P/D/2171409/S/AN/32/H/29.30 dated 2nd September, 1969 for Rs. 22,27,000/- under US AID for the import of Rayon Grade Wood Pulp. They have requested for the issue of duplicate Customs copy of the licence on the ground that the original customs purposes copy of the licence has been lost by them. It has been further reported by the licensee that the licence was lost after utilising Rs. 20,27,187.59P. The licence has been registered with Collector of Customs, Calcutta.

In support of their contention the applicant have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original Customs Purposes Copy of the licence No. P/D/2171409 dated 2nd September, 1969 has been lost and directs that a duplicate Customs Copy of the said licence should be issued to them. The original Customs Purposes Copy is cancelled. (A duplicate copy of the licence is being issued separately.)

[No. Rayon/3(2)/69. 70/RM.6]

G. S. SHARMA,

Dy. Chief Controller of Imports and Exports.  
for Chief Controller of Imports & Exports.

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर 1970

एस० ओ० 131.—सर्वश्री जे० के रेयान, कमला टावर, कानपुर को यू० एस० ए० आई० डी० के अन्तर्गत रेयान वर्ग की लुगरी लकड़ी के आयात के लिए 22,27,000 रुपये का आयात लाइसेंस संख्या पी/डी/2171409/एस/ए एन/32/एच/29-30 दिनांक 2-9-1969 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क कार्य संबंधी प्रति के लिए अनुरोध किया है, इस के लिए यह आशंका दी जा रही है कि मूल सीमा-शुल्क कार्य-संबंधी प्रति खो गई है। लाइसेंस-धारी द्वारा आगे यह बताया गया है कि 20,27,187 59 पैसे का उपयोग करने के पश्चात् लाइसेंस खो गया था। लाइसेंस सीमा-शुल्क समाहर्ता, कलकत्ता के पास पंजीकृत किया गया है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र जमा किया है। अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि लाइसेंस सं० पी/डी/2171409 दिनांक 2-9-69 की मूल सीमा-शुल्क कार्य संबंधी

प्रति खो गई है और आवेदक को अनुलिपि सीमा-शुल्क कार्य संबंधी प्रति जारी की जानी चाहिए। मूल सीमा-शुल्क कार्य संबंधी प्रति रद्द की जाती है। (लाइसेंस को अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है)

[संख्या रेयान/3(2)/69-70/आर०एम० 6]

जी० एस० शर्मा,

उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

कृते मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 4th December 1970

**S.O. 132.**—The Distt. Controller of Stores, Diesel Loco. Works, Varanasi was granted an import licence No. R/987585/62/RC/CCI/L. VI dated 23rd November, 1962 for Rs. 38,500/- for the import of Rolls Royce Diesel Engine. He has applied for issue of duplicate copy for Exchange Control Purposes of above-mentioned import licence on the ground that the original Exchange Control Copy of the licence has been misplaced after having been registered with Calcutta Customs and not utilised at all for the purpose of remittance. In support of this contention the applicant has filed an affidavit. I am satisfied that the original Exchange Control Copy of import licence No. R-987585/62/RC/CCI/L. VI dated 23rd November, 1962 has been lost and that duplicate copy thereof should be issued to the applicant.

In exercise of powers conferred by clause 9(CC) of the Import (Control) order No. 17/55 dated 7th December, 1955 as amended from time to time the undersigned cancels the Exchange Control Copy of above-mentioned import licence issued for the import of Rolls Royce Diesel Engine for Rs. 38,500/- under I.T.C. No. 30(C)/II in favour of The Distt. Controller of Stores, Diesel Loco. Works, Varanasi. Duplicate copy of the licence for Exchange Control Purpose is being issued separately.

[No. 51-D/Rly./62-63/GLS/608.]

P. C. VERMA.

Dy. Chief Controller of Imports & Exports.

(मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1970

**एस०ओ० 132**—वि डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर आफ स्टोर्स, डीजल लोको वर्क्स वाराणसी को रोल्ल्स रायस डीजल इंजन के आयात के लिए 38,500 रुपये का आयात लाइसेंस संख्या आर/987585/62/आर सी/सी सी आई/एल-6 दिनांक 23-11-62 प्रदान किया गया था उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रति के लिए आवेदन किया है इसके लिए यह आधार दिया है कि उक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रति कलकत्ता सीमा-शुल्क समाहर्ता के पास पंजीकृत कराने के पश्चात् गलत स्थान पर रख दी गई है और प्रेषण कार्य के लिए इस का उपयोग बिल्कुल नहीं किया है। इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथपत्र जमा किया है। मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि लाइसेंस सं० आर-987585/62/आर सी/सी सी आई/एल-6 दिनांक 23-11-62 की मूल मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है और उस की अनुलिपि प्रति आवेदक को जारी की जानी चाहिए।

अधोहस्ताक्षरी, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 सी सी) के अन्तर्गत समय-समय पर संशोधित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि डिस्ट्रिक्ट कन्ट्रोलर आफ स्टोर्स डीजल लोको वर्क्स, वाराणसी के नाम रोलज रायस के आयात के लिए 38,500 रुपये के लिए जारी किए गए उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रति को रद्द करता है। उक्त लाइसेंस की अनलिपि मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या: 51-डी/रेलवे/62-63/जी एल एस]

पी० सी० वर्मा,

उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-नियंत्रण।

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 9th December 1970

S.O. 133.—M/s. Bharat Earth Movers Ltd., Bangalore were granted licence No I/A/1039987/S/AN/33/H/29-30 dated 21st October, 1969 under US AID (Non Project) Loan No. 386-H-196 for the import of components for Earth Moving equipments valued at Rs. 3,23,00,000/-. They have requested for the issue of duplicate customs purposes copy of the licence on the ground that the original customs copy of the licence has been lost by them. It has further been reported by the party that the licence was utilised for Rs. 2,17,51,300/- and that it has a balance of Rs. 1,05,48,700/-. The licence was registered with collector of customs, Madras.

In support of their contention, the applicant have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original customs copy of the licence No. I/A/1039987/S/AN/33/H/29-30 dated 21st October, 1969 has been lost and directs that a duplicate customs purposes copy of the said licence should be issued to them. The original customs copy is cancelled.

The duplicate customs copy is being issued separately.

[No. UD/17-B/69-70/PLSA]

(मुख्य नियंत्रक, आयात-नियंत्रण का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर 1970

एस०ओ० 133.—सर्वश्री भारत अर्थ मूवर्स लि०, बंगलूर को यू० एस० ए० आई० डी० (नैर परियोजना) ऋण संख्या 386-एच-196 के अन्तर्गत मुद्राही उपकरणों के आयात के लिए 3,23,00,000 रुपये का आयात लाइसेंस संख्या आई/ए/1039987/एस/एन/33/एच/29-30, दिनांक 21-10-69 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनलिपि सीमाशुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि मूल सीमा-शुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति उनके द्वारा खो गई है। पार्टी द्वारा आगे यह बताया गया है कि लाइसेंस के मूल्य में से 2,17,51,300 रुपये का प्रयोग किया गया था और 1,05,48,700 रुपये बाकी बचा है। लाइसेंस, सीमा-शुल्क समाहर्ता, मद्रास के पास पंजीकृत किया गया था।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र जमा किया है। अधोहस्ताक्षरी इससे संतुष्ट है कि लाइसेंस संख्या आई/ए/1039987/एस/एन/33/एच/29-30, दिनांक 12-10-69

की मूल सीमा-शुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति खो गई है और उन्हें उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति जारी की जानी चाहिए। मूल सीमा-शुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति रद्द की जाती है।

अनुलिपि सीमा-शुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या : यूडी/17-बी/69-70/पी०एल०एस०ए०]

*New Delhi, the 19th December 1970*

**S.O. 134.**—The Chief Engineer (Construction), Punjab State Electricity Board, Patiala was granted Import licence No. G/A/1034650 dated 31st January, 1968 from Poland for import of Lightning Arrestors and Surge Counters as per list attached to the licence valued at Rs. 5,960/- only has requested for issue of duplicate copy of the licence (both customs and exchange purposes copies) on the ground that the original licence (both copies with list of goods and Letter of Authority) has been lost/misplaced without having been registered with any customs authority and utilised at all.

In support of this contention the applicant has filed an affidavit. The undersigned is satisfied that both copies of the original licence No. G/A/1034650 dated 31st January, 1968 have been lost and directs that duplicate licences both for customs and exchange control purposes of the said licence may be issued. The original licence in duplicate has been cancelled and duplicate licence (both copies) are being issued separately.

[No. 2/SG/317/67-68/PLS/B.]

S. K. USMANI,

Deputy Chief Controller of Imports & Exports,  
for Jt. Chief Controller of Imports & Exports

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर 1970

**एस० ओ० 134.**—दी चीफ इन्जीनियर, (कन्स्ट्रक्शन), पंजाब स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड, पटियाला को पोलैन्ड से लाइसेंस के साथ संलग्न सूची के अनुसार लाइटनिंग एरेस्टर तथा सर्ज काउंटर्स के आयात के लिए 5,950 रुपये का आयात लाइसेंस सं० जी० ए० 1034650 दिनांक 31-1-68 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने अनुलिपि लाइसेंस (दोनों सीमा-शुल्क तथा मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रतियों) के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि मूल लाइसेंस (मदों की सूची यथा प्राधिकार पत्र के साथ दोनों प्रतियां) बिना किसी सीमा-शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए और बिना उपयोग किए खो गया है/अस्थानस्थ हो गया है।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक घोष-पत्र जमा किया है। अधो-हस्ताक्षरी इससे संतुष्ट हैं कि मूल लाइसेंस सं० जी० ए०/1034650 दिनांक 31-1-68 की दोनों प्रतियां खो गई हैं और निवेश देता है कि उक्त लाइसेंस का अनुलिपि लाइसेंस सीमा-शुल्क तथा मुद्रा विनियम नियंत्रण दोनों प्रतियां आवेदक को जारी किया जाना चाहिए। मूल लाइसेंस दो प्रतियों में रद्द कर दिया गया है और अनुलिपि लाइसेंस (दोनों प्रतियां) अलग से जारी किया जा रहा है।

[सं० 2/एस० जी०/317/67-68/पी०एल०एस०/बी०]

एस० के० उस्मानी,

उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात,  
कले-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

## (Office of the Dy. Chief Controller of Imports and Exports)

## ORDER

New Delhi, the 15th December 1970

**S.O. 135.**—M/s. Consolidated Pneumatic Tool Co. of (India) Ltd., 301/302, Agra Road, Mulund, Bombay-80 were granted Import Licence No. P/RM/2149220/C/XX/22/H/21-22/Machinery, dated 22nd May, 1966 for the import of components worth Rs. 12,000/- from U.K.

2. It has now been reported by the firm that the Exchange control copy has been misplaced after having been Registered with Bombay Customs House and was utilised partly to the extent of Rs. 7,999.20. The firm have now requested this office to issue duplicate Exchange Control copy to enable them to remit the balance amount of Rs. 4,000.80 to their associates in U.K.

3. In support of this request, the applicant has filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the Exchange Control copy of Import Licence No. P/RM/2149220/C/XX/22/H/21-22/Machinery, dated 29th May, 1966 has been misplaced and directs that a Duplicate Exchange Control copy of the licence in question may be issued to them for making outstanding payment of Rs. 4,000.80. The Original Exchange Control is hereby cancelled.

[No. F. Mach-C/6/AM-66/RM-4]

G. D. BAHL,

Dy. Chief Controller of Imports &amp; Exports.

मुख्य निर्यातक आयात निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1970

**एस०ओ० 135.**—सर्वश्री कन्सोलिडेटेड न्यूमेटिक टूल कं० प्रा० (इंडिया) लि० 301/302 आगरा रोड, मुलुन्द, बम्बई-80 को इंग्लैंड से 12,000 रुपये के मूल्य के संघटकों के आयात के लिए आयात लाइसेंस सं० पी/आर एम/2149220/सी/एक्स एक्स/22/एच/21-22 / मशीनरी दिनांक 22-5-66 प्रदान किया गया था।

2 अब फर्म द्वारा यह अभ्यावेदन किया गया है कि बम्बई सीमा शुल्क कार्यालय से पंजीकृत कराई जाने के बाद तथा 7999.20 रुपये तक उपयोग होने के बाद मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रति अस्थानस्थ हो गई है। अब फर्म ने इंग्लैंड में अपने सहयोगियों को शेष धनराशि 4000.80 रुपये का प्रेषण अधिकार प्राप्त करने के लिए मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस कार्यालय से आवेदन किया है।

3 अपने आवेदन की पुष्टि में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस सं० पी/आर एम/2149220/सी/एक्स एक्स/22/एच 21-22/मशीनरी दिनांक 29-5-66 की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता है कि शेष बचे हुए 4000.80 रुपये का भुगतान करने के लिए उनको विषयाधीन लाइसेंस की मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि जारी की जाए। मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

[संख्या:मैक-सी/6/ए०एम-66/आर० एम०-4]

डी० जी० बहल,

उप-मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात।

(Office of the Dy. Chief Controller of Imports and Exports)

New Delhi, the 17th December 1970

**S.O. 136.**—M/s Atic Industries Limited, Atul Post, Western Railway (Distt. Bulsar) were granted Import Licence No. P/D/2171312, dated 29th August, 1969 for import of raw materials valued at Rs. 3,16,553/- from the Rupee Payment Area countries. They have requested for the issue of a duplicate Customs Purposes of the said licence on the ground that the original Customs Purposes copy of the licence was lost/misplaced after utilising Rs. 1,45,110 and that the licence has been registered with the Collector of Customs, Bombay.

2. In support of their statement they filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original Customs Purposes copy of the licence No. P/D/2171312, dated 29th August, 1969 has been lost and directs that a duplicate Customs Purposes copy of the said licence should be issued to them. The original Customs Purposes copy of the licence is cancelled.

[No. Dyes/A-5(6)/A.M. 69/R.M.3/2278.]

मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आवेश

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1970

एस० नो० 136.—सर्वश्री एटिक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, अत्रुल पोस्ट, वेस्टर्न रेलवे (जिला बलसर) को दया भुगतान क्षेत्र देशों से कच्चे माल के आयात के लिए 3,16,553/- रुपये के मूल्य का लाइसेंस संख्या पी/डी/2171312 दिनांक 29-8-69 जारी किया गया था। उन्होंने लाइसेंस की सीमा शुल्क विभाग प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रति 1,45,110/- रुपये का उपयोग होने के बाद खो गई थी/अस्थानस्थ हो गई थी तथा लाइसेंस की सीमाशुल्क समाहर्ता, बम्बई से पंजीकृत कराया गया था।

2. अपने कथन की पुष्टि में उन्होंने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोस्ताधरी संतुष्ट है कि लाइसेंस संख्या पी/डी/2171312 दिनांक 29-8-69 की मूल सीमाशुल्क प्रति खो गई है और निदेश देता है कि उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रति की अनुलिपि उनको जारी की जानी चाहिए। लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रति को रद्द किया जाता है।

[संख्या : डईज/ए. 5(6)/ए० एम० 69/आर० एम० 3/2278)

S.O. 137.—M/s. Mohan Meekin Breweries Limited, Ghaziabad were granted Licence No. P/D/2169248 dated 13th May, 1969 from G.C.A. for import of spares for the machinery for the manufacture of Industrial Bases valued at Rs. 4,000/-. They have requested for the issue of a duplicate Exchange Control purposes copy of the licence on the ground that the original Exchange Control purposes copy of the licence has been lost/misplaced by them. It has been further reported by the licensee that the Exchange Control purposes copy of the licence was lost/misplaced after utilising Rs. 2,328 leaving a balance of Rs. 1,672/- and that the Customs copy of the licence had been registered with the Collector of Customs, Bombay.

2. In support of this statement, the applicant have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original Exchange Control copy of licence No. P/D/2169248 dated 13th May, 1969 has been lost/misplaced and directs that a duplicate Exchange Control copy of the said licence should be issued to them. The original Exchange Control purposes copy of the licence is cancelled.

[No. Ch/M-2(64)/A.M.69/R.M.3./2284.]

एस० नो० 137.—सर्वश्री मोहन मीकिन ब्रुवरीज लि० गाजियाबाद को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से औद्योगिक बेस के निर्माण के लिए मशीनरी के फालतु पुर्जों के आयात के लिए 4 000/- रुपये मूल्य का लाइसेंस संख्या पी/डी/2169248 दिनांक 13-5-69 जारी किया गया था। उन्होंने लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति उन से खो गई है/अस्थानस्थ हो गई है। लाइसेंसधारी द्वारा आगे यह सूचना दी गई है कि लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति 2,328/- रुपये का उपयोग होना तथा 1,672/- रुपये शेष रहने के बाद खो गई थी/अस्थानस्थ हो गई थी और लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रति की सीमा-शुल्क समाहर्ता, बम्बई से पंजीकृत कराया गया था।

2. इस कथन की पुष्टि में आवेदक ने एक शपथ पत्र जमा किया है। अधोहस्ताधरी संतुष्ट है कि लाइसेंस संख्या पी/डी/2169248 दिनांक 13-5-69 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है/अस्थानस्थ हो गई है तथा निदेश देता है कि उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि उनको जारी की जानी चाहिए। लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को रद्द किया जाता है।

[सं० सी० एच/एम-2 (64)/ए० एम० 69/आर० एम० 3/2284]

**S.O. 138.**—M/s. Idco Dyestuffs Private Limited, Delhi were granted licence Nos. (i) P/D/2179837 and (ii) P/D/2179838 both dated 2nd June, 1970, for import of raw materials valued at (i) Rs. 3,17,500/- and (ii) Rs. 40,000/- from (i) R.P.A. countries and (ii) G.C.A. They have requested for the issue of duplicate copies of these licences on the ground that the original Customs and Exchange Control copies of the licence have been lost/misplaced. It has been further reported that these licences were lost/misplaced after utilising Rupees Nil and that these licences have not been registered with any of the Collector of Customs.

2. In support of their contention, the applicant have filed two affidavits. The undersigned is satisfied that the original licences (In duplicate) (i) P/D/2179837 and (ii) P/D/2179838, both dated 2nd June, 1970 have been lost/misplaced and directs that duplicate Customs and Exchange Control copies of the said licences should be issued to them. The original licences (In duplicate) are cancelled.

[No. Dyes-21(1)/A.M.70/R.M 3/228.F

SARDUL SINGH,

Deputy Chief Controller of Imports & Exports.

**एस० नो० 138.**—सर्वश्री ईदको डाईस्टफ्स प्राईवेट लिमिटेड, दिल्ली को (1) रुपया भुगतान देशों तथा (2) सामान्य मुद्रा क्षेत्र से (1) 3,17,500 रुपये तथा (2) 40,000 रुपये के मूल्य के कच्चे माष के आयात के लिए लाइसेंस संख्या (1) पी/डी/2179837, दिनांक 2-6-70 तथा (2) पी/डी/2179838, दिनांक 2-6-70, स्वीकृत किए गए थे। उन्होंने इन लाइसेंसों की अनुलिपियां जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई हैं/अस्थानस्थ हो गई हैं। आगे यह सूचना दी गई है कि ये लाइसेंस बिना उपयोग किए खो गए हैं तथा इन को किसी भी सीमा-शुल्क समाहर्ता से पंजीकृत नहीं कराया गया है।

2. अपने तर्क की पुष्टि में आवेदक ने दो शपथ-पत्र दाखिल किए हैं। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि मूल लाइसेंस (दो प्रतियों में) (1) पी/डी/2179837 तथा (2) पी/डी/2179838, दिनांक 2-6-70 खो गए हैं/अस्थानस्थ हो गए हैं और निदेश देता है कि उक्त लाइसेंसों की सीमा-शुल्क तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों की अनुलिपियां उनको जारी की जानी चाहिए। मूल लाइसेंस (दोनों प्रतियों में) रद्द किए जाते हैं।

[संख्या : डाईज-21/(1)/ए० एम०. 70/आर० एम०-3/2281]

सरदूल सिंह,

उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

## DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(P. & T. Board)

New Delhi, the 29th December 1970

**S.O. 139.**—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434, of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16th January, 1971 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Chaibasa Telephone Exchange, Bihar Circle.

[No. 5-71/70-PHB]

D. R. BAHL, Asstt. Dir. Gen. (PHB).



**संचार विभाग  
(डाक-तार बोर्ड)**

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर 1970

**स्वायी आदेश 139.**—स्वायी आदेश क्रम संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए 1951 के भारतीय तार नियमों के नियम 434 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने चाईबासा टेलीफोन केंद्र में 16-1-1971 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[नं० एक० 5-71/70 पी० एस० बी०]

डी० आर० बहल,

सहायक महानिदेशक (पी० एच० बी०)

**MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE**

**(Department of Industrial Development)**

*New Delhi, the 29th December 1970*

**S.O. 140.**—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) No. S. O. 3763/IDRA/15/70, dated the 17th November, 1970, namely:—

In the said Notification, for item (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Shri G. P. Seth, Deputy Cane Commissioner, Government of Uttar Pradesh . . . . . Member.”

[No. F.9(27)Lic Pol./70.]

**औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय**

**(औद्योगिक विकास विभाग)**

नई दिल्ली 29 दिसम्बर, 1970

**का०आ० 140.**—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या का०आ० 3763 आई० डी० आर० ए० तारीख 17 नवम्बर, 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में मद (2) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“श्री जी०पी० सेठ,

उप गन्ना आयुक्त,

उत्तर प्रदेश सरकार . . . . . सदस्य”

[सं० 9(27) लाईस०पालि०/70]

**S.O. 141.**—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) No. S. O. 3714/IDRA/15/70 dated the 10th November, 1970, namely:—

In the said Notification for item (3), the following shall be substituted, namely:—

“(3) Shri G. P. Seth, Deputy Cane Commissioner, Government of Uttar Pradesh . . . . . Member:”

[No. F.9(28)Lic.Pol./70.]

का० प्रा० 141.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 3714 आई० डी० आर० ए०/15/70 तारीख 10 नवम्बर, 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में मद (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(3) श्री जी० पी० सेठ, उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार . . . सदस्य”

[सं० 9(28)/ल।ईसं० पालि०/70]

*New Delhi, the 30th December 1970*

**S.O. 142/IDRA/15/70.**—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) No. S.O. 3762/IDRA/15/70, dated the 17th November, 1970, namely:—

In the said Notification, for item (3), the following shall be substituted, namely:—

“(3) Shri G. P. Seth, Deputy Cane Commissioner, Government of Uttar Pradesh.—Member.”

[No. F. 9(26)Lic.Pol./70.]

S. GANESPANDIAN, Under Secy.

*नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1970*

का० प्रा० 142.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 3762 आई० डी० आर० ए० तारीख 17 नवम्बर, 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में मद (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(3) श्री जी० पी० सेठ, उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार . . . सदस्य”

[सं० 9(26)/ल।ईसं० पालि०/70]

एस० गनैसपांडियन,

अवर सचिव ।

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 8th December 1970

**S.O. 143/IDRA/6/70.**—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with Rules 5(1) and 8 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints till 9th September, 1972 Shri A. Natarajan in place of Shri A. H. Tobacowala of M/s. Tata Engineering and Locomotive Company Limited, to be a member of the Development Council established by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade No. S.O. 3243-IDRA/6/16 dated the 10th September, 1970 for the scheduled industries engaged in the manufacture or production of Automobiles, Automobile Ancillary Industries, Transport Vehicle Industries, Tractors, Earth Moving Equipment and Internal Combustion Engines and directs that the following amendments shall be made in the said Order, namely:

In the said Order:—

- (i) For the name "Shri A. H. Tobacowala" in entry No. 2, the name "Shri A. Natarajan" shall be substituted.
- (ii) For the name "Shri S. K. Jhawar" in entry No. 13, the name "Shri M. K. Jhawar" shall be read.

[No.1(33)/70-A.E.Ind.(I)]

B. K. VARMA, Dy. Secy.

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1970

**एस० ओ० 143/आई० डी० आर० ए०/6/70.**—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65वा) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्ति यों का प्रयोग करते हुए विकास परिषद (कार्यविधि) नियम, 1952 के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा मैसर्स टाटा इंजनियरिंग तथा लोकोमोटिव कम्पनी लि० के श्री ए० एच० टूबैकौवाला के स्थान पर श्री ए० नटराजन को 9 सितम्बर, 1972 तक मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी सहायक उद्योग, परिवहन सहन उद्योग, ट्रैक्टर, मिट्टी ढोने वाले उपकरण तथा अन्तर दहन इंजिन के उत्पादन में लगे हुए अनुवृत्त उद्योगों के लिए औद्योगिक विभाग तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश मख एस० ओ० 3243-आई० डी० आर० ए०/6/16 दिनांक 10 सितम्बर, 1970 के तहत य विन उद्योगों की विकास परिषद का सदस्य नियुक्त करती है तथा आदेश देती है कि उक्त आदेश में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा, अर्थात् :—

उक्त आदेश में :—

- (i) प्रविष्टि संख्या 2 में श्री ए० एच० "टूबैकौवाला" के नाम के स्थान पर "श्री ए० नटराजन" का नाम प्रतिस्थापित किया जायेगा ;
- (ii) प्रविष्टि संख्या 13 में "श्री एम० के० ज़ावर" के नाम के स्थान पर "श्री एम० के० ज़ावर" का नाम पढ़ा जायेगा ।

[सं० 1(33)/70-ए० ई० आई० (I)]

बी० के० वर्मा,

उप सचिव ।

## (Department of Industrial Development)

## (INDIAN STANDARDS INSTITUTION)

New Delhi, the 21st December, 1970

**S.O. 144.**—In pursuance of the provisions of sub-rule (2) of Rule 3 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution, hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the following schedule, have been established during the quarter ending 30 June, 1970 :—

## THE SCHEDULE

Sl. No.	No. of Indian Standard	Title of the Indian Standards
1	IS : 138-1969	Specification for ready mixed paint, marking for packages and petrol containers, colour as required ( <i>First Revision</i> ).
2	IS : 139-1969	Specification for ready mixed paint, marking, quick drying, for marking with rubber stamps, colour as required ( <i>First Revision</i> ).
3	IS : 200-1969	Method for determination of copper number of cotton textile materials ( <i>First Revision</i> ).
4	IS : 717-1969	Specification for carbon disulphide, technical ( <i>First Revision</i> ).
5	IS : 758-1969	Specification for handloom cotton gauze, absorbent ( <i>First Revision</i> ).
6	IS : 863-1969	Specification for handloom cotton bandage cloth ( <i>First Revision</i> ).
7	IS : 1200 (Pt. XVI)-1969	Method of measurement of building and civil engineering work. Part XVI laying of water and sewer lines including appurtenant items ( <i>Second Revision</i> ).
8	IS : 1200 (Pt. XX)-1969	Method of measurement of building and civil engineering work. Part XX laying of gas and oil pipelines ( <i>Second Revision</i> ).
9	IS : 1233-1969	Recommendation for modular co-ordination of dimensions in the building industry ( <i>First Revision</i> ).
10	IS : 1238-1969	Specification for hurricane lanterns ( <i>Second Revision</i> ).
11	IS : 1515-1969	Specification for beehives ( <i>First Revision</i> ).
12	IS : 2309-1969	Code of practice for the protection of buildings and allied structures against lightning ( <i>First Revision</i> ).
13	IS : 2414-1969	Specification for cycle tyres ( <i>First Revision</i> ).
14	IS : 2415-1969	Specification for cycle rubber tubes ( <i>First Revision</i> ).
15	IS : 2430-1969	Methods for sampling of aggregates for concrete.
16	IS : 2465-1969	Specification for cables for motor vehicles ( <i>First Revision</i> ).
17	IS : 2720 (Pt. II)-1969	Methods of test for soils. Part II Determination of moisture content ( <i>First Revision</i> ).
18	IS : 2873-1969	Specification for packaging of jute products in bales ( <i>First Revision</i> ).
19	IS : 4026-1969	Specification for aluminium ingots (EC GRADE) ( <i>First Revision</i> ).
20	IS : 4101 (Pt. III)-1969	Code of practice for external facing and veneers Part III Wall tiling and mosaics.
21	IS : 4410 (Pt. X)-1969	Glossary of terms relating to river valley projects Part X Civil Works of hydro-electric generation system including water conductor system.
22	IS : 4839 (Pt. III)-1969	Code of practice for maintenance of canals Part III Canal structures, drains, jungle clearance plantation and regulation.
23	IS : 4854 (Pt. I)-1969	Glossary of terms for valves and their parts Part I Screw-down stop, check and gate valves and their parts.

Sl. No.	No. of Indian Standard	Title of the Indian Standards
24	IS : 4910 (Pt. V)-1969	Methods of test for tyre yarns, cords and tyre cord fabrics made from man-made fibres Part V Wet contraction and wet contractile force.
25	IS : 4988 (Pt. II)-1968	Glossary of terms and classification of earth-moving machinery. Part II Dozers.
26	IS : 4988 (Pt. III)-1968	Glossary of terms and classification of earth moving machinery. Part III Motor and towed scrapers.
27	IS : 4988 (Pt. IV)-1968	Glossary of terms and classification of earth-moving machinery. Part IV Excavators.
28	IS : 4988 (Pt V)-1968	Glossary of terms and classification of earth-moving machinery. Part V Motor graders.
29	IS : 4989-1969	Specification for foam compound for producing mechanical foam for fire fighting.
30	IS : 5002-1969	Methods for determination of sample size to estimate the average quality of a lot or process.
31	IS : 5100-1969	Specification for twist drills, parallel shanks, sub series for right hand cutting.
32	IS : 5104-1969	Specification for twist drills, oversize Morse taper shank
33	IS : 5216-1969	Guide for safety procedures and practices in electrical work.
34	IS : 5250-1969	Dimensions for swing clamps.
35	IS : 5252-1969	Dimensions for wide clamps plates.
36	IS : 5258-1969	Determination of particle size of powders by optical microscope method.
37	IS : 5282-1969	Liquid sedimentation methods for determination of particle size of powders.
38	IS : 5285-1969	Method of tests for fibre analysis of paper and board.
39	IS : 5298-1969	Methods for determination of distillation range and of distillation yield.
40	IS : 5311-1969	Code of safety for carbon tetrachloride.
41	IS : 5313-1969	Guide for core drilling observations.
42	IS : 5318-1969	Code of practice for laying of flexible PVC sheet and tile flooring.
43	IS : 5328-1969	Method of test for determination of chemical composition of asbestos fibre.
44	IS : 5329-1969	Code of practice for sanitary pipe work above ground for buildings.
45	IS : 5330-1969	Criteria for design of anchor blocks for penstocks with expansion joints.
46	IS : 5332-1969	Specification for boys' and youths' school shoes.
47	IS : 5333-1969	Specification for leather cricket boots.
48	IS : 5337-1969	Specification for cot, dropside, baby, hospital
49	IS : 5338-1969	Specification for catheter, eustachian.
50	IS : 5341-1969	Specification for benzyl chloride, technical.
51	IS : 5350 (Pt II)-1969	Dimensions of indoor and outdoor porcelain post insulators and post insulator units for systems with nominal voltages greater than 1000 V. Part II Outdoor cylindrical post insulators.
52	IS : 5356-1969	Specification for isopropyl myristate for cosmetic industry.
53	IS : 5361-1969	Specification for polyester film dielectric capacitors for direct current.
54	IS : 5367-1969	Specification for forceps, eye, strabismus, for advancement (Princed's and Worth's Patterns).
55	IS : 5374-1969	Specification for tapes washers for I-beams (ISMB)
56	IS : 5382-1969	Specification for rubber sealing rings for gas mains, water mains and sewers.
57	IS : 5385-1969	Specification for lifeboat accessories.
58	IS : 5386-1969	Specification for general purpose ship's davit.
59	IS : 5390-1969	Code of practice for construction of timber ceilings.
60	IS : 5398-1969	Methods for estimation of thiamine (vitamin B <sub>1</sub> ) in foodstuffs.

Sl. No.	No. of Indian Standard	Title of the Indian Standards
61	IS : 5399-1969	Methods for estimation of riboflavin (vitamin B <sub>2</sub> ) in foodstuffs.
62	IS : 5400-1969	Methods for estimation of nicotinic acid (niacin) in foodstuffs.
63	IS : 5401-1969	Methods for detection and estimation of coliform bacteria in foodstuffs.
64	IS : 5402-1969	Method for plate count of bacteria in foodstuffs.
65	IS : 5404-1969	Code of practice for handling of food samples for microbiological analysis.
66	IS : 5407-1969	Specification for ammonium phosphate sulphate granular (19.5-19.5-0).
67	IS : 5413-1969	Specification for conical fittings for to-and-fro carbon dioxide absorber (Waters Type) for use with gas anaesthetic apparatus.
68	IS : 5416-1969	Methods of test for general purpose wooden chairs.
69	IS : 5420 (Pt.I)-1969	Guide on precision of test methods. Part I Principles and applications.
70	IS : 5425 (Pt.I)-1969	Methods of chemical analysis of misch metal Part I Determination of cerium
71	IS : 5428 (Pt.II)-1969	Specification for gauge glasses for pressure vessels and boilers Part II Protector glasses for tabular gauge glasses.
72	IS : 5429-1969	Dimensions for steel tubes for automotive purposes.
73	IS : 5430-1969	Specification for ammonia preserved concentrated natural rubber latex.
74	IS : 5431-1969	Definition of motion-picture safety films.
75	IS : 5432-1969	Glossary of terms relating to powder metallurgy
76	IS : 5435-1969	Specification for cold asphalt macadam mixing plants.
77	IS : 5436-1969	Method of testing oil-fired rotary dryers for hot mix asphalt and bituminous macadam plants.
78	IS : 5437-1969	Specification for wired and figured glass
79	IS : 5439-1969	Specification for oil pressure switches for automobiles
80	IS : 5452-1969	Specification for dehydrated garlic
81	IS : 5453-1969	Specification for saffron
82	IS : 5454-1969	Methods for sampling of clay building bricks
83	IS : 5463-1969	Methods for sampling of cotton fabrics for chemical tests.
84	IS : 5465-1969	Specification for Small bark
85	IS : 5468-1969	Specification for blanco
86	IS : 5471-1969	Specification for dried shark fins
87	IS : 5472-1969	Specification for fish maws
88	IS : 5473-1969	Specification for double flanged bobbins used in woolen and worsted mills.
89	IS : 5477 (Pt.I)-1969	Methods for fixing the capacities of reservoirs Part I General requirements
90	IS : 5481-1969	Specification for floor polish, liquid
91	IS : 5482-1969	Specification for autoclaved cellular concrete blocks.
92	IS : 5485-1969	Specification for cotton yarn waste.
93	IS : 5487-1969	Specification for metal polish, liquid.
94	IS : 5488-1969	Dimensions for hot rolled steel plates for ship's hull structure.
95	IS : 5495-1969	Sizes and shapes for fixabricks (300 mm and higher series)
96	IS : 5496-1969	Guide for preliminary dimensioning and layout of elbow type draft tubes for surface hydel power stations
97	IS : 5512-1969	Specification for flow table for use in tests of hydraulic cements and pozzolanic materials.
98	IS : 5516-1969	Specification for variable flow type air-permeability apparatus (Blaine Type)
99	IS : 5518-1969	Specification for steels for die blocks for drop forging
100	IS : 5542-1969	Guide for storm analysis.
101	IS : 5544-1970	Specification for hot food cabinets for use with L.P.G.
102	IS : 5553 (Pt.III)-1970	Specification for reactors Part III Neutral earthing reactor and arc suppression coil.

[N. CMD/13:3]  
A. K. GUPTA,  
Deputy Director General.

(औद्योगिक विकास विभाग)

(भारतीय मानक संस्था)

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1970

एस० ओ० 144.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) नियम, 1955 के नियम 3 के उपनियम (2) के अनुसार भारतीय मानक संस्था की ओर से सूचित किया जाता है कि भारतीय मानक जिनके व्योरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, 30 जून 1970 को समाप्त त्रैमासिक अवधि में निर्धारित किए गए हैं।

अनुसूची

क्रमांक	भारतीय मानकों की संख्या	भारतीय मानकों के शीर्षक
1	IS : 138-1969	पैकेजों और पेट्रोल-धारकों पर अंकन के लिए वांछित रंग के तैयार मिश्रित रंग रोगन की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)।
2	IS : 139-1969	रबड़ की मुहरों के लिए प्रयुक्त शीघ्र सूखने वाले वांछित रंग के तैयार मिश्रित रंग रोगन की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)।
3	IS : 200-1969	सूती वस्त्रादि सामग्री में ताम्र संख्या निकालने की पद्धति (पहला पुनरीक्षण)।
4	IS : 717-1969	कार्बन डाईसल्फाइड, तकनीकी, की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)।
5	IS : 758-1969	हथकरघे की शोधक, विरंजित सूती जाली (पहला पुनरीक्षण)।
6	IS : 863-1969	हथकरघे का सूती विरंजित पट्टी का कपड़ा (पहला पुनरीक्षण)।
7	IS : 1200 (भाग 16)-1969	इमारती और सिविल इंजीनियरी कामों की मापन पद्धति भाग 16 उपांगों सहित पानी और सीवर की लाइनें डालना (दूसरा पुनरीक्षण)।
8	IS : 1200 (भाग 20)-1969	इमारती और सिविल इंजीनियरी कामों की मापन पद्धति, भाग 20 गैस और तेल की पाइप लाइनें डालना (दूसरा पुनरीक्षण)।
9	IS : 1233-1969	इमारती उद्योग में मापों के माध्यूलगत समन्वयन की सिफारिशें (पहला पुनरीक्षण)।
10	IS : 1238-1969	लालटेनों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)।
11	IS : 1515-1969	मधु मक्खियों के छत्तों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)।
12	IS : 2309-1969	तड़ित से इमारतों तथा आगारों के बचाव की रीति संहिता (पहला पुनरीक्षण)।

क्रमांक भारतीय मानकों की संख्या

भारतीय मानकों के शीर्षक

13 IS : 2414-1969	साइकिल के टायरों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)
14 IS : 2415-1969	साइकिल के रबड़-ट्यूबों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) ।
15 IS : 2430-1969	कंक्रिट की रोड़ियों की बानगी लेने की पद्धतियाँ ।
16 IS : 2465-1969	मोटर गाड़ियों के लिए केबलों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) ।
17 IS : 2720(भाग 2)-1969	मृत्तिकाओं की परिक्षण पद्धतियाँ, भाग 2, नमी की मात्रा निकालना (पहला पुनरीक्षण) ।
18 IS : 2873-1969	जूट की बनी चीजों की गांठों में बंधाई की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) ।
19 IS : 4026-1969	एल्युमिनियम इंगटों की विशिष्टि (ई सी ग्रेड) (पहला पुनरीक्षण) ।
20 IS : 4101 (भाग 3)-1968	ऊपरी फेंसिंग और बेनियर देने की रीतिसंहिता भाग 3 दीवारों में टाइल लगाना और पक्कीकारी का काम ।
21 IS : 4410(भाग 10)-1969	नदी घाटी योजनाओं से सम्बन्धित शब्दावली, भाग 10 जलचालन प्रणाली सहित पन विजली उत्पादन प्रणाली के सिविल काम ।
22 IS : 4839(भाग 3)-1969	नहरों के रखरखाव की रीतिसंहिता, भाग 3, नहर सम्बन्धी आगार, निकास नालियों, जंगल की सफाई, वन रोपण और नियमन ।
23 IS : 4854(भाग 1)-1969	वाल्खों और उनके पुर्जों से सम्बन्धित शब्दावली, भाग 1 पेंच द्वारा बद करने, नियंत्रण करने और खोलने के (वाल्ख) टॉंटी और पुर्जे ।
24 IS : 4910(भाग 5)-1969	मनुष्य निर्मित रेशों के टायर-धागों डोरियों और टायर-डोरी कपड़ों की परिक्षण पद्धतियाँ, भाग 5 भीगने पर सिकुड़न और भीगने पर सिकुड़न बल ।
25 IS : 4988 (भाग 2)-1968	मिट्टी हटाने वाली मशीनादि सम्बन्धी शब्दावली और वर्गीकरण, भाग 2 डोजर्स ।
26 IS : 4988 (भाग 3)-1968	मिट्टी हटाने वाली मशीनादि सम्बन्धी शब्दावली और वर्गीकरण, भाग 3 मोटर और दोहरे स्क्रैपर्स ।
27 IS : 4988 (भाग 4)-1968	मिट्टी हटाने वाली मशीनादि सम्बन्धी शब्दावली और वर्गीकरण, भाग 4 एक्सकेवेटर्स ।



क्रमांक भारतीय मानकों की संख्या

भारतीय मानकों के शीर्षक

- 28 IS : 4988 (भाग 5)---1968 मिट्टी हटाने वाली मशीनादि सम्बन्धी शब्दावली और वर्गीकरण, भाग 5 मोटर ग्रेडर्स ।
- 29 IS : 4989-1969 आग बुझाने के लिए यांत्रिक फेन उत्पन्न करने वाले फेन यौगिक ।
- 30 IS : 5002--1969 किसी राशि अथवा विधि की औसत किस्म के मूल्यांकन के लिए बानगी का आकार निश्चित करते की पद्धति ।
- 31 IS : 5100---1969 दायें हाथ की कटाई के लिए स्टब सिरीज समांतर शैक वाली टिबस्ट ड्रिल को विशिष्टि ।
- 32 IS : 5104--1969 अतिमापी मोर्स गावहुम एक वाली टिबस्ट ड्रिलों की विशिष्टि ।
- 33 IS : 5216-1969 बिजली के काम के लिए बचाव सम्बन्धी प्रक्रियाओं और रीतियों की निदेशिका ।
- 34 IS : 5250--1969 स्विंग कलम्पों के लिए माप ।
- 35 IS : 5252--1969 चौड़ी क्लैम्प पट्टियों के माप ।
- 36 : 5258--1969 चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी पद्धति द्वारा चूर्णों के कणों का आकार निकालना ।
- 37 IS : 5282--1969 चूर्णों के कणों का आकार निकालने के लिए ब्रव तलछटन पद्धति ।
- 38 IS : 5285--1969 कागज और गत्ते के रेशा विश्लेषण की परीक्षण पद्धतियां ।
- 39 IS : 5298--1969 आसवन परास और आसवन उपलब्धि की मात्रा निकालना ।
- 40 IS : 5311--1969 कार्बन ट्राइक्लोराइड के लिए बचाव संहिता
- 41 IS : 5313--1969 कोर ड्रिलिंग के आंकड़े अंकित करने की निदेशिका ।
- 42 IS : 5318--1969 नाम्य पी बो सी चादर और टाइल का फर्श देने की रीति संहिता ।
- 43 IS : 5328--1969 एस्वेस्टास रेशे की रसायनिक रचना निकालने की परीक्षण पद्धतियां ।
- 44 IS : 5329--1969 इमारतों के लिए जमीन से ऊपर मेनेटरी पाइप कार्य की रीति संहिता ।

क्रमांक	भारतीय मानकों की संख्या	भारतीय मानकों के शीर्षक
45	IS : 5330—1969	प्रसार जोड़ों वाले पेन-स्टाकों के लिए लेजर शलाकों के डिजाइन की कसौटियाँ।
46	IS : 5332—1969	लड़कों और किशोरों के स्कूली जूतों की विशिष्टि।
47	IS : 5333—1969	भूमड़े के क्रिकेट बूटों की विशिष्टि।
48	IS : 5337—1969	शिशुओं की प्रस्पताली द्रापसाइड खाटो की विशिष्टि।
49	IS : 5338—1969	यूसटेको मूत्रनली की विशिष्टि।
50	IS : 5341—1969	बैजिलक्लोराइड, तकनीकी, की विशिष्टि।
51	IS : 5350 (भाग 2)—1969	1000-वोल्ट से अधिक संकेतिक वोल्टता वाली प्रणालियों के लिए भीतर और खुले में लगने वाले पोर्सलैन के पोस्टरोधकों और पोस्टरोधक इकाइयों के माप, भाग 2 खुले में लगाने वाले बल नाकार पोस्टरोधक।
52	IS : 5356—1969	अंगार प्रसाधन उद्योग के लिए ग्राइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट की विशिष्टि।
53	IS : 5361—1969	दृष्टिधारा के लिए पालीएस्टर फिल्म डाइ इलेक्ट्रिक ट्रक कैपिस्टरो की विशिष्टि।
54	IS : 5367—1969	ऐडवान्स्मेन्ट के लिए आंख के स्ट्राबिस्मस फोर्सेप्स (प्रिन्स और वर्थ नमूने के)।
55	IS : 5374—1969	आइनुमा घरानियों के लिए गायदुध बाशरों की विशिष्टि।
56	IS : 5382—1969	गैस के मेन्स, पानी के मेन्स और सीवरों को सील करने के रबड़ के छल्लों की विशिष्टि।
57	IS : 5385—1969	रक्षा नौका के सहायक सामान की विशिष्टि।
58	IS : 5386—1969	सामान्य कार्यों के लिए जलयान के ड्रेजिटों की विशिष्टि।
59	IS : 5390—1969	लकड़ी की छतबंदी तैयार करने की रीति संहिता
60	IS : 5398—1969	खाद्य पदार्थों में थायामिन (विटामिन बी 1) की मात्रा निकालने की पद्धति।
61	IS : 5399—1969	खाद्य पदार्थों में रिबोफ्लेविन (विटामिन बी 2) की मात्रा निकालने की पद्धति।
62	IS : 5400—1969	खाद्य पदार्थों में निकोटिनिक अम्ल की मात्रा निकालने की पद्धति।

क्रमांक	भारतीय मानकों की संख्या	भारतीय मानकों के शीर्षक
63	IS : 5401-1969	खाद्य पदार्थों में कालीफॉर्म बैक्टीरिया की पहचान करने और मात्रा निकालने की पद्धति
64	IS : 5402-1969	खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया की प्लेट-गणना की पद्धति
65	IS : 5404-1969	सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए खरब बानगियों को धरने उठाने की रीतिसंहिता
66	IS : 5407-1969	दानेदार अमोनियम फास्फेटसल्फेट (19.5-19.5-0) की विशिष्टि
67	IS : 5413-1969	गैस संवेदनाहारी उपकरण के साथ प्रयुक्ते गागे पीछे हो सकने वाले कार्बनडाइ आक्साइड शोभक मंत्र (घाटर्स टाइप) के लिए शंकुनुमा क्रिटिंग की विशिष्टि
68	IS : 5416-1969	सामान्य कार्यों में आनेवाली लकड़ी की कुसियों की परीक्षण पद्धतियां
69	IS : 5420 (भाग 1)-1969	परीक्षण पद्धतियों में परिशुद्धता सम्बन्धी निर्देशिका भाग 1 सिद्धान्त और उपयोगिता
70	IS : 5425 (भाग 1)-1969	मिश्रधातु के रसायनिक विश्लेषण की पद्धतियां, भाग 1 सीरियम की मात्रा निकालना
71	IS : 5428 (भाग 2)-1969	दाब पात्रों और व्यायलरों के लिए मापक कांचों की विशिष्टि भाग 2 नलिकाकार मापक कांचों के लिए रक्षक कांच
72	IS : 5429-1969	स्वचल कार्यों के लिए हस्पात की नलियों के माप
73	IS : 5430-1969	अमोनिया परिरक्षित गाढ़ाकृत प्राकृतिक रबड़ लैटेक्स की विशिष्टि
74	IS : 5431-1969	चलचित्र के लिए सुरक्षा फिल्मों की परिभाषा
75	IS : 5432-1969	चूर्ण धातु कर्मिता सम्बन्धी शब्दावली
76	IS : 5435-1969	ऐस्फाल्ट मैकडम के ठंडे मिश्रण संयंत्रों की विशिष्टि
77	IS : 5436-1969	ऐस्फाल्ट और विद्ययूमनी मैकडम के कर्ममिश्रण संयंत्रों के लिए तेल द्वारा तप्त घूमने वाले सूत्रावक यंत्र
78	IS : 5437-1969	ता ठंडे और आकृतिकार कांचों की विशिष्टि
79	IS : 5439-1969	स्नान गाड़ियों के लिए तेल दाब वाले स्प्रिंजों की विशिष्टि
80	IS : 5452-1969	सुखाए गए लहसुन की विशिष्टि

## क्रमांक भारतीय मानकों की संख्या

## भारतीय मानकों के शीर्षक

81	IS : 5453-1969	केशर की विशिष्टि
82	IS : 5454-1969	मिट्टी की इमारती ईंटों की बानगी लेने की पद्धति
83	IS : 5463-1969	रसायनिक परीक्षणों के लिए सूती कपड़ों की बानगी लेने की पद्धतियाँ
84	IS : 5465-1969	अमलतास की छाल की विशिष्टि
85	IS : 5468-1969	ब्लैंको की विशिष्टि
86	IS : 5471-1969	शार्क के सुखाए पंखों की विशिष्टि
87	IS : 5472-1969	मछली के माँ की विशिष्टि
88	IS : 5473-1969	ऊनी और वस्टेंड मिलों में प्रयुक्त दोहरे फलेंज वाली बाबिनी की विशिष्टि
89	IS : 5477(भाग 1)-1969	जलाशयों की समाह्वय निश्चित करने की पद्धतियाँ भाग 1 सामान्य अपेक्षाएँ
90	IS : 5481-1969	फश की तरल पालिश की विशिष्टि
91	IS : 5482-1969	आटोक्लेवकृत कोषीय कंक्रीट ब्लाकों की विशिष्टि
92	IS : 5485-1969	सूती व्यर्थ धागे की विशिष्टि
93	IS : 5487-1969	धातु की तरल पालिश की विशिष्टि
94	IS : 5488-1969	जलयान के ढाँचे की संरचना के लिए गर्भ रोल्ड इस्पात की प्लेटों के माप
95	IS : 5495-1969	अग्नि-ईंटों के आकार और शक्लें (300 मि मी और ऊपर की सीरीज)
96	IS : 5496-1969	जमीन से ऊपर बनने वाले पन बिजली केन्द्रों के लिए कौहनी नुमा कर्षक नलियों के प्रारम्भिक माप निर्धारण और विन्यास की निदेशिका
97	IS : 5512-1969	जलपुष्ट सीमेंटों और पोजोलानीय सामग्रियों में प्रयुक्त फलोटेबल की विशिष्टि
98	IS : 5516-1969	चर बहाव वाले वायु प्रवेश्यता उपकरण (क्लैन टाइप) की विशिष्टि
99	IS : 5518-1969	ड्राप-गढ़ाई के लिए डाइचों के इस्पात की विशिष्टि
100	IS : 5542-1969	प्रभञ्जन-व्यश्लेषण निदेशिका
101	IS : 5544-1969	द्रवित पेट्रोलियम गत्तों से काम करने वाली गर्म खाने की कैबिनेटों की विशिष्टि

क्रमांक । भारतीय मानकों की संख्या

भारतीय मानकों के शीर्षक

102 IS : 5553(भाग 3)-1970

रिऐक्टरों की विशिष्टि, भाग 3 न्यूट्रल ग्रथयोजी  
रिऐक्टर और आर्क-शामक कांयल

[सं० की० एम० डी०/13:3]

ए० के० गुप्ता,

उपमहानिदेशक ।

# MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS

(Department of Petroleum and Chemicals)

New Delhi, the 23rd December 1970

**S.O. 145.**—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission for the transport of petroleum from Well No. BEJ to GGS III in village Pansoli in Kaira District of Gujarat.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the Land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declares its intention to acquire the said right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9;

And further, that every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

## SCHEDULE

*For Laying Pipeline from Well No. BEJ to G.G.S. III*

State : Gujarat

District : Kaira

Taluka: Matar

Village	Survey No.	Hectare	Are.	P. Are.
Pansoli	265	0	10	50
	257	0	03	50
	256/1	0	12	00
	256/2	0	00	75

[No. 11(2)/70-Lab & Legis.]

M. V. S. PRASADA RAU, Under Secy.

## पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय

(पेट्रोलियम तथा रसायन विभाग)

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर 1970

क्रा० धा० सं० 145—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कैर जिला में गांव पन्सोली में कुआं संख्या बी ई जे से जी जी एस III तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुनाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का उक्त अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद् द्वारा घोषित किया है।

बशर्त कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, ————— तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, अवरपुरा रोड, बरौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और आगे ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

कुआं संख्या बी ई जे से जी जी एस III तक पाइप लाईन बिछाने के लिए

राज्य: गुजरात

जिला: कैर

तालुका: मातर

गांव	सर्वेक्षण संख्या	हेक्टर	आर	पी आर
पन्सोली	265	0	10	50
	257	0	03	50
	256/1	0	12	00
	256/2	0	00	75

[संख्या 11(2)/70-लेबर एण्ड लेजिस]

म० वे० शिव प्रसाद राव, अवर सचिव।

(Department of Mines &amp; Metals)

ERRATUM

New Delhi, the 22nd December 1970

S.O. 146.—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Department of Mines and Metals) No. S.O. 2574 dated the 23rd July, 1970, published in Part II section 3 sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 1st August, 1970 at page 3300, in line 23, for "village Gursula" read "village Garsula".

[No. F.C3-1(10)/70.]

K. SUBRAHMANYAN, Under Secy.

(खान तथा धातु विभाग)

आवृत्ति पत्र

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1970

का० आ० 146—भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 1 अगस्त, 1970 के पृष्ठ 3300 में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना में "ट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय (खान तथा धातु विभाग) की सं० का० आ० 2574 तारीख 23 जुलाई, 1970 में,

पंक्ति 23 में "ग्राम गरसुला" के लिये "ग्राम गरसुला" पढ़ा जाए।

[सं० एफ० सी० 3-1(10)/70]

के० सुब्रह्मण्यन, अवर सचिव।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 30th December 1970

S.O. 147.—The Central Government hereby accept the resignation of Shrimati R. Shamanta, from membership of the Advisory Panel of the Central Board of Film Censors, Madras, with immediate effect.

[No. 11/8/70-FC.]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिसम्बर, 1970

एत० आ० 147—केन्द्रीय सरकार ने एतद्वारा श्रीमती आर० शमन्ता का केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के मद्रास सलाहकार पैनल को सदस्यता से त्यागपत्र तत्काल से स्वीकार कर लिया है।

[संख्या 11/8/70-एफ० सी०.]

ORDERS

New Delhi, the 21st December 1970

S. O. 148—In pursuance of the directions issued under the provisions of each of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the film specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in Gujarat to be of the description specified against it in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

- (1) Sub-Section 4 of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).
- (2) Sub-Section (3) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Bombay Act XVII of 1953).
- (3) Sub-Section (4) of Section 5 and Section 9 of the Saurashtra Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Saurashtra Act XVII of 1953).

## THE SECOND SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 30 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film interded for educational purposes or a film dealing with news & current events or a documentary film
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1,	Mahitichitra No. 131	228.56 M	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalya, Ahmedabad.	Film dealing with news & current events (For release in Gujarat Circuit only).	

[No. F. 28/1/70-FP App. 1533]

## आदेश

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1970

एस० श्री० 148—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उप-बन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके गुजराती भाषा के रूपान्तरों सहित जिसका विवरण उसके सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

## प्रथम अनुसूची

- (1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16।
- (2) बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम, 1953 (1953 का 17वां बम्बई अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9।
- (3) सौराष्ट्र सिनेमा (विनियम) अधिनियम, 1953 (1953 का 17वां सौराष्ट्र अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (4) तथा धारा 9।

## द्वितीय अनुसूची

क्रम सं०	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकु-मैन्ट्री फिल्म है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	महितीचित्रा संख्या 131	228.56 मीटर	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार सचिवालय, अहमदाबाद।	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल गुजरात सर्किट के लिये)	

[संख्या फ० 28/1/70-एफ० पी० परिशिष्ट-1533]



New Delhi, the 30th December 1970

**S. O. 149.**—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in all its language versions to be of the description specified against it in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

- (1) Sub-Section (4) of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).
- (2) Sub-Section (3) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Bombay Act XI of 1953).

THE SECOND SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 35mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Maharashtra News No. 222	293.00M	Director of Publicity Govt. of Maharashtra, Film Centre, 68-Tardeo Road, Bombay-34.	Film dealing with news & current events (For release in Maharashtra Circuit only)	

[No. F. 28/1/70-FP App.1536]  
K. K. KHAN Under Secy.

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1970

**एस० ओ० 149.**—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भाषाओं के रूपान्तरों सहित जिसका विवरण उसके सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृति करती है :-

प्रथम अनुसूची

- (1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37 वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16।
- (2) बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1953 (1953 का 11 वां बम्बई अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9।

## द्वितीय अनुसूची

क्रम सं०	फिल्म का नाम	लम्बाई मि० मीटर	35 आबोदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है
1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र समा- चार संख्या 222	293.00 मीटर	समाचारनिदेशक, महाराष्ट्र सरकार, फिल्म सैन्टर, 68, तारवेव रोड, बम्बई-34			समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल महाराष्ट्र सर्किट के लिये)

[संख्या फ० 28/1/70-एक० पो० परिशिष्ट 1536]

क० क० खान, प्रवर सचिव।

## MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 5th June 1970

S.O. 150.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Cold Storage Order, 1964, namely:—

1. This Order may be called the Cold Storage (Amendment) Order, 1970.
2. In this Cold Storage Order, 1964,

(1) for sub-clause (d) of clause 2, the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(d) ‘Licensing Officer’ means the Agricultural Marketing Adviser to the Govt. of India, (Department of Agriculture), Ministry of Food, Agriculture, Community Development and ‘Co-operation, Government of India, and includes any other officer empowered by him in this behalf with the approval of the Central Government.”

- (2) In Form—B,

for the words ‘Department of Food (Food and Nutrition Board)’ the following words shall be substituted, namely:—

“Directorate of Marketing and Inspection.”

[No. 1-15/70-L.A.]

M. K. MUKHARJI, Jt. Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 5 जून, 1970

का०आ० 150.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार शीतागार आदेश, 1964 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

1 यह आदेश शीतागार (संशोधन) आदेश, 1970 कहा जा सकेगा।

2 श्रीतागार आदेश, 1954 में,

(1) खण्ड 2 के उपखंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) ‘अनुज्ञापन अधिकारी’ से भारत सरकार, का कृषि विषयन सलाहकार (कृषि विभाग), खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार अभिप्रेत है और कोई अन्य अधिकारी जिसे उसके द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से इस निमित्त सशक्त किया जाए इसमें सम्मिलित है।

(2) प्रथम-ख में,

‘खाद्य विभाग (खाद्य और पोषण बोर्ड)’ शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“विषयन और निरीक्षण निदेशालय”

[सं० 1-15/70-एल० ए०]

एम० के० मुखर्जी, संयुक्त सचिव ।

#### (Department of Cooperation)

New Delhi, the 19th December 1970

S.O. 151.—In exercise of the powers conferred by Section 5B of the Multi-unit Cooperative Societies Act 1942 (6 of 1942) and in supersession of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Co-operation) Notification No. 7-4/68-Credit, dated 25th March, 1969, the Central Government hereby directs that all the powers or authority exercisable by the Central Registrar of Cooperative Societies under the said Act shall also be exercisable by Shri S. Sen, Additional Registrar of Cooperative Societies, West Bengal, in respect of the multi-unit Cooperative Societies which are or are deemed to be actually registered in the State of West Bengal.

[No. 7-4/68-Credit.]

S. SATYABHAMA, Dy. Secy.

#### (सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर 1970

एस० ओ० 151.—बहु इकाई सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1942 (1942 का 6) की धारा 5 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (सहकारिता विभाग) की अधिसूचना संख्या 7-4/68-क्रेडिट, तारीख 25 मार्च 1969 को अधिकांत करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के अधीन सहकारी सोसाइटी के केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियों या प्राधिकार श्री एस० सेन, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, पश्चिम बंगाल के द्वारा भी बहु इकाई सहकारी सोसाइटी के, जो पश्चिम बंगाल राज्य में वास्तव में रजिस्ट्रीकृत हैं अथवा समझी जाती हैं; संबंध में प्रयोक्तव्य होंगे ।

[सं० 7-4/68-क्रेडिट]

एस० सत्यभामा, उप सचिव ।

**MINISTRY OF FINANCE**  
(Department of Banking)

*New Delhi, the 28th December 1970*

S. O. 152.—Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, as on the 18th December, 1970.

**BANKING DEPARTMENT**

Liabilities	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up . . . . .	5,00,00,000	Notes . . . . .	16,59,64,000
		Rupee Coin . . . . .	2,33,000
Reserve Fund . . . . .	150,00,00,000	Small Coin . . . . .	4,31,000
		Bills Purchased and Discounted:—	
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	172,00,00,000	(a) Internal . . . . .	..
		(b) External . . . . .	..
		(c) Government Treasury Bills . . . . .	29,10,56,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund . . . . .	37,00,00,000	Balances Held Abroad* . . . . .	109,04,36,000
		Investments** . . . . .	97,79,52,000
		Loans and Advances to:—	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund . . . . .	95,00,00,000	(i) Central Government . . . . .	..
		(ii) State Governments @ . . . . .	17,54,38,500
		Loans and Advances to:—	
Deposits:—		(i) Scheduled Commercial Banks† . . . . .	326,18,35,000
(a) Government—		(ii) State Co-operative Banks†† . . . . .	289,53,01,000
(i) Central Government . . . . .	279,50,94,000	(iii) Others ‡ . . . . .	5,18,65,000
(ii) State Governments . . . . .	5,62,62,000		

		Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund —	
(b) Banks		(a) Loans and Advances to:—	
(i) Scheduled Commercial Banks	200,65,33,000	(i) State Governments	34,28,30,000
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	8,16,66,000	(ii) State Co-operative Banks	21,41,78,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	70,65,000	(iii) Central Land Mortgage Banks	..
(iv) Other Banks	28,05,000	(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	9,57,02,000
(c) Others		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund —	
Bills Payable	61,09,69,000	Loans and Advances to State Co-operative Banks	5,30,30,000
Other Liabilities	76,08,40,000	Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund —	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	27,68,71,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
		Other Assets	35,70,82,000
Rupees	1182,91,51,000	Rupees	1182,91,51,000

\*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

\*\*Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

† Includes Rs. 117,85,25,000/- advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

††Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 23rd day of December, 1970.

An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 18th day of December 1970

ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	16,59,64,000		Gold Coin and Bullion:—		
			(a) Held in India . . . .	182,53,11,000	
Notes in circulation . . . .	4036,23,87,000		(b) Held outside India . . . .	..	
Total Notes issued . . . .		4052,83,51,000	Foreign Securities . . . .	311,42,00,000	
			TOTAL . . . .		493,95,11,000
			Rupee Coin . . . .		56,55,90,000
			Government of India Rupee Securities		3502,32,50,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper . . . .		..
TOTAL LIABILITIES . . . .		4052,83,51,000	TOTAL ASSETS . . . .		4052,83,51,000

Dated the 23rd day of December, 1970.

S. JAGANNATHAN,  
Governor.

[No. F.3(3)-BC/70.]

K. YESURATHNAM, Under Secy.

वित्त मंत्रालय  
(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1970

एस० ओ० 152.—18 दिसम्बर, 1970 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	भास्तियां	रुपये
चुकता पूंजी . . . . .	5,00,00,000	नोट . . . . .	16,59,64,000
भारक्षित निधि . . . . .	150,00,00,000	रुपये का सिक्का . . . . .	2,33,000
		छोटा सिक्का . . . . .	4,31,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि . . . . .	172,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल :—	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि . . . . .	37,00,00,000	(क) देशी . . . . .	..
		(ख) विदेशी . . . . .	..
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घ कालीन क्रियाएं) निधि . . . . .	95,00,00,000	(ग) सरकारी खजाना बिल . . . . .	29,10,56,000
जमा राशियां :—		विदेशों में रखा हुआ बकाया* . . . . .	109,04,36,000
(क) सरकारी		निवेश** . . . . .	97,79,52,000
(i) केन्द्रीय सरकार . . . . .	279,50,94,000	ऋण और अग्रिम :—	
(ii) राज्य सरकारें . . . . .	5,62,62,000	(i) केन्द्रीय सरकार को . . . . .	..
		(ii) राज्य सरकारों को@ . . . . .	175,43,85,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम :—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक . . . . .	200,65,33,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को† . . . . .	326,18,35,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक . . . . .	8,16,66,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को†† . . . . .	289,53,01,000
		(iii) दूसरों को . . . . .	5,18,65,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
(क) ऋण और अग्रिम :—			
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक . . . . .	70,65,000	(i) राज्य सरकारों को . . . . .	34,28,30,000
(iv) अन्य बैंक . . . . .	28,05,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को . . . . .	21,41,78,000
(ग) अन्य . . . . .	91,79,17,000	(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को . . . . .	..
देय बिल . . . . .	61,09,69,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबचरों में निवेश राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम :—	9,57,02,000
अन्य देयताएं . . . . .	76,08,40,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश :—	5,30,30,000
		(क) विकास बक को ऋण और अग्रिम . . . . .	27,68,71,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश अन्य आस्तियां . . . . .	35,70,82,000
	रुपये 1182,91,51,000		रुपये 1182,91,51,000

\*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

\*\*राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों के अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

†रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 (4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मियादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 117,85,25,000 रु० शामिल हैं।

††राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

तारीख : 23 दिसम्बर, 1970



रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में दिसम्बर, 1970 की 18 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिये लेखा  
इस विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए			सोने का सिक्का और बुलियन :—		
नोट . . . . .	16,59,64,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,53,11,000	
संचलन में नोट . . . . .	4036,23,87,000		(ख) भारत के बाहर रखा हुआ . . . . .	..	
जारी किए गए कुल नोट		4052,83,51,000	विदेशी प्रतिभूतियां	311,42,00,000	
			जोड़ . . . . .		493,95,11,000
			रुपये का सिक्का		56,55,90,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां . . . . .		3502,32,50,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र . . . . .		..
कुल देयताएं . . . . .		4052,83,51,000	कुल आस्तियां . . . . .		4052,83,51,000

[सं० एफ० 3(3)-बी० सी०/70]

तारीख: 23 दिसम्बर, 1970

एस० जगन्नाथन,  
मवर्नर ।  
केनम, अव्वर सचिव ।

## (Department of Revenue and Insurance)

## INCOME-Tax

New Delhi, the 12th November 1970

**S.O. 153.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies Shri Athmanathaswamy Temple, Avadayarkoil, Arantangi Taluk, Thanjavur Dist. to be of archaeological and artistic importance for the purposes of the said section.

[No. 179—F. No. 176/49/70-IT(AI).]

B. MADHAVAN, Under Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

आयकर

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1970

**एस० नो० 153:**—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80G की उप-धारा (2) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री अत्मानाथ स्वामी मन्दिर, भवडायारकोइल, अरंतंगी तालुक, थंजावूर जिल, को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए पुरातत्विक और कलात्मक महत्व का घोषित करती है ।

[सं० 179—फा० सं० 176/49/70 आई० टी० (ए० 1)]

बी० माधवन, अवर सचिव ।

## (Department of Revenue and Insurance)

New Delhi, the 23rd December, 1970

**S.O. 154.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), I, Jasjit Singh, the Administrator, hereby direct that the following further amendments shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S. O. 4304, dated the 2nd December, 1968, namely :—

In the said notification, in the Table,—

after serial number 9, the following shall be inserted, namely :—

Serial No.	Officers	Provisions of the Gold (Control) Act, 1968	Extent of power
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Collector of Central Excise or Customs.	Sub-section (1) of section 103.	to issue a licence to an heir or legatee for carrying on business as a dealer on transmission of such business by succession, intestate or testamentary.

[No.F.2/3/70-GCII]

JASJIT SINGH,

Gold Control Administration

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1970

का० आ० नि० 154:-- स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 4 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं जसजीत सिंह, प्रशासक, एतद्वारा निदेश देता हूँ कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 4304 तारीख, 2 दिसम्बर, 1968 में और आगे निम्नलिखित संशोधन किया जाये, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 9 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

क्रम संख्या	अधिकारी	स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1968 के उपबन्ध	शक्ति का विस्तार
1	2	3	4
10	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क कलक्टर	धारा 103 की उपधारा 1	उत्तराधिकार, निर्वसीयत या बसीयत द्वारा ऐस कारबार के परिषण पर उत्तराधिकारी या बसीयत दार को ब्यौहारी के रूप में कारबार चलाने के लिए अनुमति जारी करना।

[सं० का० 2/3/70-स्वर्ण नियंत्रण II]

जस जीत सिंह,

स्वर्ण नियंत्रण प्रशासक।

(Department of Revenue and Insurance)

INCOME-TAX

New Delhi, the 26th November 1970

S.O. 155.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorise Shri K. N. Bajaj who is a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This notification shall come into force with effect from 2nd December, 1970.

3. The appointment of Shri B. S. Agarwal made in notification No. 64, dated 7th June, 1969 (F. No. 16/118/69-ITCC) is cancelled with effect from 2nd December, 1970.

[No. 189 (F. No. 404/104/70-ITCC).]

R. D. SAXENA, Dy. Secy.

## (राजस्व और श्री विभाग)

आयकर

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1970

एस० श्री० 155:— आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री के० एन० बजाज को, जो केन्द्र सरकार का राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना 2 दिसम्बर, 1970 को प्रवृत्त होगी।

3. अधिसूचना सं० 64, तारीख 7 जन 1969 (फा० सं० 16/118/69 आई टी० सी०/सी०) द्वारा की गई श्री बी० एस० अग्रवाल की नियुक्ति को 2 दिसम्बर, 1970 से रद्द किया जाता है।

[सं० 189 (फा० सं० 404/104/70-आई०टी०सी०)]

आर० डी० सक्सेना, उप सचिव।

## MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 18th December 1970

S.O.156—In exercise of the Powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government having regard to the location of the factories specified in column (4) of the schedule annexed hereto in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force and specified in column (3) of the said Schedule in the States of Punjab, Haryana and Chandigarh, hereby exempts the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette or until the enforcement of provisions of Chapter V of that Act in those areas, whichever is earlier.

## SCHEDULE

Sl. No.	Name of District	Name of Area	Name of Factories
1	2	3	4
1	Ambala	Pinjore (Abdulapur) Ramgarh	Messrs Khosla Sales (India) Private Limited (Automobile Division) Village Abdulapur Messrs Terminal Ballistics Research Laboratory.
2	Bhatinda	Kot Kapura	1. Messrs Sunit Engineering Industrial Corporation. 2. Messrs Shiv Engineering Works.
3	Hoshiarpur	Talwara	Messrs Sarving Shop Dam Site Division.
4	Karnal	Kaithal Karnal	Messrs National Steel Industries. Messrs Tosh Metal and Alloys Industries Private Limited.
5	Mandi	Pandeh Haza Bagh Slapper	Messrs Compressor House Messrs Bit Shot Messrs Oxygen Plant.

1	2	3	4
6	Patigla . . . Hassanpur Prohitan	Messrs Government Aircraft Aero Engine Overhauling Workshop, Aerodrom. Messrs Auto Valves Industries.	
7	Rupar . . . Rupat	Messrs Cooperative Cement Pipes Plant.	
8	Simla . . . Bisoti	Messrs Kilmia Plastics Private Limitd.	
9	Sonepat . . . Behalgarh	Messrs Moonlight Glue Industries. Messrs Laxmi Glue Manufacturing Company.	

[ No. F602 (7)70-HI ]

(श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय)

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1970

का० आ० 156:—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) को धारा 73च द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों को ऐसे क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त है और जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट तथा राजाज, हरियाणा राज्यों और चंडीगढ़ में हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए या तब तक के लिए जब तक कि इस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, एतद्वारा छूट देती है।

अनुसूची

क्रम सं०	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखानों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अम्बाला	पिन्जोर (अम्बुल्लापुर)	मेजर्स खोसला सेल्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड (आटोमोबाइल डिब्रीजिंग ग्राम अम्बुल्लापुर)
		रामगढ़	मेसर्स टर्मिनल बैलास्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी
2	भटिण्डा	कोटकपुरा	(1) मेसर्स सुनीत इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन (2) मेसर्स शिव इंजीनियरिंग वर्क्स डिब्रीजिंग
3	होशियारपुर	तलवाड़ा	मेसर्स सर्बिंग सीप डेम साइट

1	2	3	4
4	करनाल . . .	कैथल करनाल	मैसर्स नेशनल स्टील इण्डस्ट्रीज मैसर्स तोष मेटल एण्ड अलायज इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
5	मण्डी . . .	पंडोह . हरबाग . स्लाम्पर .	मैसर्स कम्प्रेसर हाउस मैसर्स बिट शाप मैसर्स ग्राफसोजन प्लांट
6	पटियाला . . .	हसनपुर .  प्रोहितन .	मैसर्स सरकारी वायुयान विमान इंजिन ओवरहाल-करण कर्मशाला हवाई अड्डा मैसर्स आटोवाल्वज इंडस्ट्रीज
7	रोपड़ . . .	रोपड़ .	मैसर्स कोप्रापरेटिव सिमेंट पाइप्स, प्लांट
8	शिमला . . .	बरोटी .	मैसर्स कलिमा प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
9	सोनोपत . . .	बहलगढ़ .	मैसर्स मूनलाइट ग्लू इंडस्ट्रीज मैसर्स लक्ष्मी ग्लू मैपूकैफोरिंग कम्पनी ।

[सं० फा० 602(7)/70-एच० आई०]

**S. O. 157.**—In exercise of the powers conferred by section 73P of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed, in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Maharashtra in which the provisions of Chapters IV and V of the Act are in force, hereby exempts the said factories from the payment of employers' special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

## SCHEDULE

Sl. No.	Name of District	Name of Area	Name of the factory
1	2	3	4
1	East Khandesh	Chopda	Messrs. Maharashtra State Road Transport Depot, Workshop, Chopda.
2	Sangli	Kupwad	Messrs. Bharat Cement Works.
3	West Khandesh	Shirpur	Messrs. Maharashtra State Transport Corporation.

[No. P. 602(27)/70-HL.]

का० प्र० 157.—हर्मचारी राज्य बोमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73 च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों की उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट महाराष्ट्र राज्य के क्षेत्रों

में, जिनमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के प्रयोजन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष आदेश के तत्त्व से इन प्रविष्टियों के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए, तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी रहें हैं, एतद्वारा छूट देना है ।

### अनुसूची

क्रमसं०	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पूर्वी खानदेश .	चौपदा .	मैसर्स महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन डिपो, कर्मशाला, चौपदा
2	सांगली .	कुपवाड .	मैसर्स भारत सिमेंट वर्क्स
3	पश्चिमी खानदेश .	शिरपुर .	मैसर्स महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम

[सं० फा० 602(27)/70-एच० आई०]

**S. O. 158.**—In exercise of the powers conferred by section 73 F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas, specified in column (3) of the said Schedule in the State of Bihar in which the provisions of Chapter IV and V of the Act are in force, hereby exempts the said factories from the payment of employers' special contribution payable under Chapter VA of the said Act for a period of one year with effect from the 31st May 1970 till the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

### SCHEDULE

Serial No.	Name of District	Name of Area.	Name of the factory.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bhagalpur	Barahgama Sultanganj	Messrs Ajanta Stone Works at Barahgama, Amarpur. Messrs Bihar Khadi Gramodhog Sang, Saranjan Karayalaya.
2	Champaran	Sagauli	Messrs Bijnan Saw Mill, Post Sagauli.
3	Dhanbad	Govindpur Mohuda	Messrs Laxmi Steel Industries Post Office Govindpur. Messrs Bihar Cement Products.
4	Hazaribagh	Hirodih	Messrs Gayday Iron Steel Company Limited, Post Office Hirodih.

(1)	(2)	(3)	(4)
5	Monghyr	Sheikhpura	Messrs Chandni Biddaban Stone Works, Station Road.
6	Patna	Bikram Biharsharif	Messrs Foot Wear Factory, Post Office, Bikram. Messrs Vividh Engg. Works.
7	Shahbad	Mohania	Messrs Agarwal and Co.

[No. F. 602 (31)/70-HI]

का० प्रा० 158:—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73 च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों की उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट बिहार राज्य के क्षेत्रों में जिनमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध में प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से 31 मई, 1970 से एक वर्ष की कालावधि के लिए या उन क्षेत्रों में उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध प्रवृत्त होने तक, जो भी पहले हो, एतद्वारा छूट देती है।

## अनुसूची

क्रम संख्या	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	भागलपुर	दड़गामा	मैसर्स अजन्ता स्टोन वर्क्स, बड़गामा, अमरपुर
		सुलनातन गंज	मैसर्स बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ, सारंजन कार्यालय
2	चम्पारन	सगोली	मैसर्स बजरंग सा मिल, डाकघर सगोली
3	धनबाद	गोविन्दपुर	मैसर्स लक्ष्मी स्टील इण्डस्ट्रीज, डाकघर गोविन्दपुर
		मोहुदा	मैसर्स बिहार सिमेन्ट प्रोडक्ट्स
4	हजारी बग	हिरोडिह	मैसर्स गेडे आयरन स्टील कम्पनी लिमिटेड, डाकघर हिरोडिह
5	मुंगेर	शेखपुरा	मैसर्स चांदी बिदाबिन स्टोन वर्क्स, स्टेशन रोड
6	पटना	बिक्रम	मैसर्स फुट वियर फैक्टरी, डाकघर बिक्रम
		बिहारशरीफ	मैसर्स विविध इंजीनियरिंग वर्क्स
7	शाहबाद	मोहनिया	मैसर्स अन्नवाल एण्ड कम्पनी



New Delhi, the 21st December 1970

**S.O. 159.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri V. K. Srivatsan to be an Inspector for the whole of the Union territory of Delhi for the purposes of the said Act and of any Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government, or in relation to an establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oil-field or a controlled industry.

[No. 21(5)/68-PF.I.]

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1970

**क्र० आ० 159.**—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री वी० के० श्रीवलसन को उक्त अधिनियम और उसके अधीन विरचित किसी स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के सम्बन्ध में या किसी रेल कम्पनी महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से सम्बन्धित किसी स्थापन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है।

[संख्या 21(5) 68-पी० एफ०-1]

**S.O. 160.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Sarvashri Sudhendu Bhadra and Mihir Kiran Pathak to be Inspectors for the whole of the State of West Bengal, Union territory of Tripura and Andaman and Nicobar Islands for the purposes of the said Act and of any Scheme framed thereunder, in relation to any establishments belonging to, or under the control of the Central Government and in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oil Field or a controlled industry.

[No. 21(6)/68-PF-I.]

**क्र० आ० 160.**—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सर्वश्री सुधेन्दु भद्र और मिहिर किरण पाठक को उक्त अधिनियम और उसके अधीन विरचित किसी स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन स्थापनों के सम्बन्ध में और किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से सम्बन्धित किसी स्थापन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण पश्चिमी बंगाल राज्य, त्रिपुरा और अंदमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निरीक्षण नियुक्त करती है।

[संख्या 21(6)/68-पी० एफ०-1]

दलजीत सिंह, अवर सचिव

# CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th December 1970

**S.O. 161.**—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation (Department of Labour & Employment) No. S.O. 3367, dated the 30th September, 1970 published at page 4719, of the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 17th October, 1970 in line 17, for "Numkhedi" read "Nimkhedi".

[No. F.604/(2)/70-HI.]

DALJIT SINGH, Under Secy.

## (Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 24th December 1970

**S.O. 162.**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (2 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri Badal Gangopaddhyaya as a member of the Calcutta Dock Labour Board vice Shri Niharendu Dutt Mazumdar resigned and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Employment (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1322, dated the 7th April, 1967, namely:—

In the said notification, under the heading "Members representing the dock workers", in item (1) for the entry "Niharendu Dutt Mazumdar", the entry "Shri Badal Gangopaddhyaya" shall be substituted.

[No. 53/23/67-Fac.II/P&amp;D.]

U. MAHABALA RAO, Dy. Secy.

(श्री और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1970

का० प्रा० 162.— डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5-क की उपधारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री बादल गंगोपाध्याय को श्री निहारेन्द्र दत्त मजुमदार के स्थान पर, जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है, कलकत्ता डाक श्रम बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 1322, तारीख 7 अप्रैल, 1967 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "डाक श्रमिकों के प्रतिनिधि सदस्य" शीर्षक के अन्तर्गत मद्द

(1) में "निहारेन्द्र दत्त मजुमदार" प्रविष्टि के लिए "श्री बादल गंगोपाध्याय"

प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

[स० 53/23/67-फै क० 2/ पी०एन्ड डी०]

(यू० महाबला राव, उपसचिव।)

## (Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 30th December 1970

**S.O. 163.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the matter of an application under Section 33A of the said Act, from S/Shri D. D. Mitra, J. J. Mukherjee and T. K. Biswas, Telephone Clerks, Equitable Coal Company Limited, Post Office Dishergharh, District Burdwan, which was received by the Central Government on 19th December, 1970.

## CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Misc. APPLICATION No. 21 OF 1970

## PARTIES:

1. Sri D. D. Mitra, Telephone clerk
  2. Sri J. J. Mukherjee, do
  3. Sri T. K. Biswas, do
- C/o. Equitable Coal Co. Limited, P. O. Dishergharh, Burdwan—Applicants

versus

1. Sri A. K. Mathur, Administrative Officer.
  2. Col. S. P. Sharma, Superintendent Administration,
- C/o. Equitable Coal Co. Ltd, P. O. Dishergharh, Burdwan—Opp. parties.

## PRESENT:

Mr. B. N. Banerjee, Presiding Officer.

**APPEARANCES:**

*On behalf of Applicants.*—Sri P. K. Acharya, Joint Secretary, Equitable Coal Co. Ltd.'s Employees Union.

*On behalf of Opp. Parties.*—Sri A. K. Mathur, Administrative Officer.

**STATE:** West Bengal.

**INDUSTRY:** Coal Mines.

**AWARD**

This is an application under Section 33A of the Industrial Disputes Act, by three telephone clerks of the names of D. D. Mitra, J. J. Mukherjee and T. K. Biswas. They say that pending Reference No. 34 of 1970 before this Tribunal, the workmen were not allowed to work on four paid holidays, namely 2nd, the 7th, the 8th and the 9th October, 1970. The relevant paragraphs in this context are set out below:

"4. That on 2nd October, 1970 (Gandhi's Birth Day) the Complainants were stopped virtually from doing duty. The Complainant No. 1 was out of station and came to his duty at his schedule time at Night and found that the Telephone Room was under lock and key and learnt from the Office Guard that nobody was allowed to do duty on the said date. By opening the Telephone Room by the Guard the Complainant No. 1 tried to connect the Administrative Officer over phone but he was not available. After contacting the Superintendent Administration it was learnt by Compt. No. 1 that nobody was allowed to do duty on that date. The Superintendent Administration advised the Compt. No. 1 to leave the office as the Management would not pay wages for doing duty on the said date.

"5. That in the Dishergarh Office 7th, 8th and 9th October, 1970 were paid holidays. On the said dates the existing duty Roster were changed without any notice and duty hours were changed arbitrarily and a new shift was introduced from 10 A.M. to 6 P.M. Only one shift was run by the Management. On the 7th October, D. D. Mitra was allowed to do work. On the 8th October, Sri J. J. Mukherjee was allowed to do work. On the 9th October, Sri T. K. Biswas was allowed to do work."

Their grievance is that by changing the duty Roster arbitrarily the management changed the condition of service and thereby deprived the concerned workmen of their earnings and privileges.

2. Now, it was not proved to my satisfaction that these three workmen and none else had the right to work on all holidays, by virtue of their service condition. Reliance, however, was placed on a duty roster (marked Ex. 1 by consent), which I set out below:

"In clarification of 'DUTY ROSTER' issued on 10/3/51 the following order is issued:

1. All half days festival leave will be treated as Saturday and duties will be allowed to D.P.L., J.M. & S.M.P. accordingly.
2. Telephone duties during full days festival leave will be manned by D.P.L., J.M. & S.P.M. @ 8 hours each."

Now, the duty roster cannot be, without more, a part of anybody's service condition. Rosters are made and unmade according to the requirements of the employers. In this case, however, Mr. Acharya, Joint Secretary of the Equitable Coal Company Ltd's Employees Union, who appeared for the three workmen, submitted that this was done with the object of victimising the three workmen and of depriving them for ever of the benefit of working and earning on holidays. Mr. Mathur, Administrative Officer of the employer Company deposed before this Court and stated:

"Because the 2nd, the 7th, the 8th and the 9th October, 1970 were declared holidays, we did not require all the concerned workmen to man the telephone on these days. It is not our intention to debar the three concerned workmen from working on all festival or other holidays. It is our intention to allow one or more of them to work on the telephone on holidays according to our requirements."

This being the position, I find that there is no substance, at present, in the allegation of victimisation of the workmen.

3. I, therefore, dismiss the application under Section 33A of the Industrial Disputes Act, with this clarification that if, in future, these three workmen, be totally excluded from working on any festival holidays, that may be a cause of action for them to approach the appropriate authority with an appropriate application.

This is my award.

(Sd.) B. N. BANERJEE,  
Presiding Officer.  
[No. 8/220/70-LRII.]

Dated December 14, 1970

**S.O. 164.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the matter of an application under Section 33A of the said Act, from Shri Sahab Pathak, Night Guard of Equitable Coal Company Limited, Post Office Dishergarh District Burdwan, which was received by the Central Government on the 18th December, 1970.

# CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

MISC. APPLICATION NO. 19 OF 1970

## **PARTIES:**

Sri Sahab Pathak, Night Guard, Equitable Coal Co. Ltd., Dishergarh Office, P.I. Dishergarh, Burdwan—*Applicant*.

*versus*

1. Equitable Coal Company Ltd., 1/2, Lord Sinha Road, Calcutta-16 and 9 others—*Opp. parties*.

## **PRESIDENT:**

Mr. B. N. Banerjee, Presiding Officer.

## **APPEARANCES:**

*On behalf of Applicant*—Sri P. K. Acharya, Joint Secretary, E.C.C. Ltd.'s Employees Union.

*On behalf of opp. Parties*—Sri H. R. Das Gupta, Personnel Officer, M/s. Equitable Coal Company Limited.

**STATE:** West Bengal.

**INDUSTRY:** Coal Mines.

## **AWARD**

This is an application purporting to be under Section 33A of the Industrial Disputes Act, 1947.

2. Strangely enough, it is nowhere indicated in the application whether the concerned workman was dismissed during the pendency of any proceedings before a Labour Court, Industrial Tribunal or National Tribunal. In the absence of such pleading, the provisions of Section 33A are not attracted to the order of dismissal, even if it was as wrongfully made as pleaded.

3. Feeling this difficulty, Mr. P. K. Acharya, Joint Secretary of the Equitable Coal Company Limited's Employees Union, who was appearing for the workman, filed an application praying for withdrawal of the present petition with liberty to raise a fresh dispute under the provisions of the Industrial Disputes Act.

4. In my opinion, this is a fit case where such prayer should be granted. I, therefore, allow the present application to be withdrawn. Nothing contained in this order of withdrawal shall prevent the workman from taking recourse to such remedy as may be open to him under the Industrial Disputes Act and from approaching this Tribunal on the same cause of action.

This is my award.

(Sd.) B. N. BANERJEE,  
Presiding Officer.

Dated, December 14, 1970.

[No. 6/57/70-LRII.]

**S.O. 165.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 3) Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Shampur Badjna Colliery of Messrs. D. Mondal and Company, Post Office Nirsachatti (Dhanbad) and their workmen, which was received by the Central Government on the 22nd December, 1970.

**CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 3), DHANBAD**

REFERENCE NO. 39 OF 1969

**PRESENT:**

Shri Sachidanand Sinha, M.A.M.L., Presiding Officer.

**PARTIES:**

Employers in relation to the Sampur Badjna Colliery.

*Vs.*

Their workmen.

**APPEARANCES:**

*For employers.*—S/Sri S. S. Mukherjee and B. Joshi, Advocates.

*For workmen.*—1. Sri K. K. Mukherjee, General Secretary and

2. Sri Phulu Ram, concerned workman.

**INDUSTRY:** Coal.

**STATE:** Bihar.

*Dhanbad, dated the 14th of December, 1970*

**AWARD**

1. The Central Government, being of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Sampur Badjna Colliery of Messrs. D. Mondal and Company, Post Office Nirshachatti, District-Dhanbad and their workmen by its order No. 2/72/69-LRII, dated the 6th of June, 1969 referred under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication the dispute in respect of the matters specified in the Schedule annexed thereto. The Schedule is extracted below:

**SCHEDULE**

- (a) Whether Shri Fulu Ram, Driver was the workman of Shampur Badjna Colliery; and
- (b) Whether the action of the management of Shampur Badjna Colliery in stopping Shri Fulu Ram, Driver was justified; if not, to what relief is the workman entitled?"

2. The parties have filed their written statements but it is unnecessary to state the respective cases of the parties because the dispute has been amicably settled. The parties have filed a joint petition of compromise which has been verified by Sri B. Joshi, Advocate on behalf of the Employers and by Sri K. K. Mukherjee, General Secretary of the Union and Sri Fulu Ram, the concerned workman.

3. According to the terms of the memorandum of settlement the employers have paid the workman Rs. 700/- (Rupees Seven hundred only) towards the full and final settlement of all dues and claims of the concerned workman named Sri Phulu Ram, and the concerned workman has acknowledged the above payment and has no further claim with the employers.

4. The terms of settlement are fair and reasonable and the same are accepted. Accordingly an award is made in terms of the memorandum of settlement (annexure 'A'), a copy of which is enclosed with the award.

5. It may now be submitted to the Central Government under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

(Sd.) SACHIDANAND SINHA,  
Presiding Officer.

ANNEXURE "A"

BEFORE THE PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 3 AT DHANBAD.

REFERENCE No. 39 OF 1969.

Employers in relation to Sampur Badjna Colliery

AND

Their workmen.

*Petition of Compromise*

The humble petition on behalf of the Employers and Workman above named, Most respectfully sheweth,—

(1) That the parties have arrived at amicable settlement of the above dispute on the following terms;—

(a) The Employers have paid the workman Rs. 700—(Rupees seven hundred only) towards the full and final settlement of all dues and claims of the concerned workman named Sri Phuluram.

(b) The concerned workman hereby acknowledges the above payment and states that he has no further claim with the employers.

(2) That in view of the above settlement no dispute exists between the parties for further adjudication.

It is humbly prayed that the Honourable Tribunal be graciously pleased to pass an award in terms of the above settlement.

*For the Workman*

(SHRI K. K. MUKHERJEE)

*For the Employers*

Sd/- Illegible (Advocate)  
14-12-70.

Sd/- PHULURAM

(Phuluram the concerned workman).

[No. 2/72/69-LR.II.]

S.O. 166.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhowra Colliery of Messrs Karamchand Thapar and Brothers (Private) Limited, Post Office Bhowra, Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 22nd December, 1970.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT:

Shri Nandagiri Venkata Rao, Presiding Officer.

REFERENCE No. 2 OF 1969

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

PARTIES:

Employers in relation to the Bhowra Colliery of Messrs Karamchand Thapar and Brothers (Private) Limited, Post Office Bhowra, District Dhanbad.

AND

Their workmen.

APPEARANCES:

On behalf of the employers—Shri K. C. Nandkeolyar, Deputy Chief Personnel Officer.

On behalf of the workmen—Shri P. K. Bose, Advocate.

STATE: Bihar.

INDUSTRY: Coal.

Dhanbad, 17th December, 1970

AWARD

The Central Government, being of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bhowra Colliery of Messrs Karamchand

Thapar and Brothers (Private) Limited, Post Office Bhowra, District Dhanbad and their workmen, by its order No. 2/184/68-LRII, dated 12th December, 1968 referred to this Tribunal under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication the dispute in respect of the matters specified in the schedule annexed thereto. The schedule is extracted below.—

#### SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bhowra Colliery of Messrs Karamchand Thapar and Brothers (Private) Limited, Post Office Bhowra, Dhanbad in altering the designation of the following six senior Overmen and showing them as Overmen in the Paysheets commencing with the book for October, 1967 and in refusing to pay them wages in the pay scale provided for Senior Overman by the Central Wage Board for Coal Mining Industry was justified?"

1. Shri N. K. Lal.
2. Shri N. S. Sodhi.
3. Shri N. Khawas.
4. Shri B. P. Verma.
5. Shri S. J. N. Sharma.
6. Shri J. N. Seal.

If not, to what relief are the workmen entitled?"

2. Employers as well as the workmen filed their statement of demands.

3. The six affected workmen named in the schedule of the reference are workmen of Bhowra colliery of the employers. Bhowra Colliery comprises of Bhowra (North) Colliery and Bhowra (South) Colliery. Prior to 15th August, 1967 the wages and emoluments of the workmen in the coal mining industry were governed by the Award of the All India Industrial Tribunal (Colliery Disputes), (Majumdar Award) read with the Award of the Labour Appellate Tribunal and Das Gupta Award. Among the various categories of workmen working in the coal mining industry there was and still is a category known as overmen. Among the overmen there are a few overman-in-charge or senior overman or head overman in the same collieries. As pointed out in para 12 at page 60 of Das Gupta Award "The Senior Overman who is also called overman-in-charge or head overman is, as observed by the Majumdar Tribunal in para 558, 'an important subordinate official who helps the Manager to discharge his ultimate responsibilities. He has under him Overman and Mining Sirdars'. The functions and qualifications of Mining Sirdars and Overmen are similar except where a mine has both overmen and mining sirdars, the mining sirdars work under the overmen and are in-charge of smaller areas while the jurisdiction of a overman extends over a wide area covering 2 or 3 mining sirdars. All collieries do not have senior overmen." According to Majumdar Award as modified the scale of pay of overmen is Rs. 75-5-105-6-111. Having taken into consideration the scales of pay available in the collieries where they were available, Das Gupta Award has revised the scale of pay of Senior Overmen as Rs. 85-5-150-3-200. Thus, before the recommendations of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry came to be implemented the scales of pay of Overmen and Senior Overmen were respectively Rs. 75-5-105-6-111 and Rs. 85-5-150-5-200. The Central Wage Board for the Coal Mining Industry has recommended (Chapter VIII para 2 at page 78, Vol. I) for the existing designations of Head overman, Senior Overman and Overman-in-charge a common scale of consolidated basic pay of Rs. 305-15-395-20-575 in Grade B and for a Overman Rs. 245-10-305-15-440 in Grade C. The employers have implemented the recommendations of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry with effect from 15th August, 1967. These facts are admitted and are not in dispute.

4. The case of the workmen is that the six affected workmen were working as Senior Overmen in Bhowra (North) Colliery and Bhowra (South) Colliery before the employers implemented the recommendations of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry, but though they are working even now as senior overmen, the employers, instead of placing them in Grade B and paying them the basic pay in the scale of Rs. 305-15-395-20-575 placed them in Grade C and are paying them their basic pay in the scale of Rs. 245-10-305-15-440. Their further complaint is that the employers have changed designation of these affected workmen from that of senior overmen to overman presumably to justify to their action in giving them grade C under the recommendations of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry. Hence their claim is that the six affected workmen should be placed in Grade B and be paid their basic pay in the scale of Rs. 305-15-395-20-575 with retrospective effect from 15th August, 1967, from which

date the employers have implemented the recommendations of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry. The defence pleaded by the employers is that the six affected workmen were working only as overmen and not as senior overmen before 15th August, 1967, that even now they are working only as overmen and that they are properly placed in Grade C and paid in the scale of Rs. 245—10—305—15—440 as recommended by the Central Wage Board for the Coal Mining Industry. They have also pleaded a settlement dated 1st March, 1968 as a bar to the present claim relating to the six affected workmen. Thus, the only points left for considerations are—(a) what is the effect of the settlement dated 1st March, 1968 and (b) were the six affected workmen working as senior overmen in the grade of Rs. 85—5—150—5—200 before the employers implemented the recommendations of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry. The workmen were represented by Shri P. K. Bose, Advocate and the employers by Shri K. C. Nandkeolyar, Deputy Chief Personnel Officer. On admission by the employers Exts. W.1 to W.4 were marked for the workmen. On behalf of the workmen 7 witnesses were examined and Exts. W.5 to W.22 and Exts. M.1 to M.39 and M.48 were marked. The employers examined 4 witnesses and marked Exts. M.40 and M.49 to M.53.

5. The settlement dated 1st March, 1968 pleaded by the employers as a bar to the present reference, is Ext. M.45. It requires to be read along with Ext. M.2 letter of the Secretary, Colliery Mazdoor Sangh, Branch Bhowra Colliery addressed to the Agent, Bhowra Colliery. Ext. M.2 letter is accompanied by a detailed list of grievances covering 9 pages. On page 1 grievance No. 3 mentioned was "all overmen holding overman's certificate should be placed in the senior grade, Appendix II". In Appendix II at pages 6 & 7 names of the overmen are mentioned. Affected workmen 1 to 4 are shown in the Appendix as overmen of Bhowra (South) Colliery and affected workmen 5 & 6 as of Bhowra (North) Colliery. Term 3 of the settlement, Ext. M.45 says, "the persons concerned have been given proper grades at the instance of the union the matter will be further discussed at a later date." Ext. M.2 is proved by WW.1 and Ext. M.45 by MW.1. WW.1 has not spoken truth when he denied his signature on Ext. M.45. Based upon these two documents the contention of the employers is two fold, firstly, the six affected workmen were given proper grades at the instance of their union and, secondly the six affected workmen were described in Ext. M.2 by their union itself as "overmen" and as such the same union cannot contend that the six affected workmen were "senior overmen" or that they were not already given proper grades. This argument of the employers does not appeal to me. As per Ext. M.2 the demand of the workmen was that all overmen, inclusive of the six affected workmen, should be placed in the senior grade. As far as overmen are concerned the only senior grade is that of a senior overman, head overman or overman-in-charge and this senior grade under the recommendations of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry is available only to those overmen who were senior overman prior to implementation of the recommendations. It is correct that in Ext. M.2 the word used is "overman" in describing the affected workmen and not "senior overmen." But in the same breath the demand was to place them in the senior grade of overmen. It follows, therefore, that in Ext. M.2 the word "Overman" is used in its general meaning and the workmen cannot be debarred from contending now that the affected workmen were "senior overmen" among the "overmen". The employers contend that at the instance of the union the overmen, inclusive of the affected workmen were given proper grades as per term No. 3 of Ext. M.45, and, as such they cannot put forth the same demand once again. But the term also says, "the matter will be further discussed at a later date." If the interpretation of the term as suggested by the employers is accepted, there could be no meaning to the words "the matter will be further discussed at a later date." From a simple reading of the term it emerges that the employers consider that the persons concerned had been given proper grades, but it was agreed that at the instance of the union the matter would be discussed at a later date. In this view I find that nothing was settled and the question of giving proper grade to the affected workmen was left open. Thus, the objection of the employers has no substance.

6. Now, it is to be considered whether the six affected workmen were only overmen or senior overmen prior to 15th August, 1967, the date from which the recommendations of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry (hereinafter referred to as the recommendations) were implemented in the colliery by the employers. It is not in dispute that the employers have implemented the recommendations with effect from 15th August, 1967 in pursuance of the settlement, Ext. W.4. By a resolution dated 10th August, 1967 the Government of India in the Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation set up a Central Wage Board for the Coal Mining Industry and the Wage Board submitted the recommendations,



which were accepted and announced by the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation by their resolution dated 21st July, 1967. But several of the employers, inclusive of the employers in the present case, did not implement the recommendations. As a result the union, Colliery Mazdoor Sangh served a strike notice dated 8th September, 1967 on Bhowra and other collieries of the employers stating that the workmen would go on token strike for one day on 3rd October, 1967 if the recommendations were not implemented with effect from 15th August, 1967. The matter was taken up in conciliation by the Regional Labour Commissioner (C) Dhanbad. During the conciliation proceedings the union and the employers arrived at the settlement, Ext. W.4 on 29th September, 1967, the employers agreeing to implement the recommendations with effect from 15th August, 1967. While implementing the recommendations the employers did not place the workmen in proper grades. On the intervention of the union they gave proper grades to some of the workmen. This fact is conceded even by a witness of the employers, MW.2, who says that when the recommendations were implemented he was given Grade II instead of grade I and it was corrected after he complained to his union and his union took up the matter with the management. MW.1 also has spoken to the same effect. Admittedly, the six affected workmen are not given the pay scale of Rs. 305-15-395-20-575 in Grade B but are given the pay scale of Rs. 245-10-305-15-440 in Grade C of the recommendations. It is also not disputed that if the affected workmen were senior overmen in the pay scale of Rs. 85-5-150-5-200 prior to implementation of the recommendations they were to get the pay scale of Rs. 305-15-395-20-575. All the six affected workmen examined themselves in support of their case that they were senior overmen before the implementation of the recommendations. Under Regulation 36 of the Coal Mines Regulation, 1957 it is the duty of every Manager on taking over charge of a mine to countersign the authorisations or issue fresh authorisations to the competent persons, in which category overmen are included. Ext. W.5 is such authorisation issued to the affected workman No. 1, N. K. Lal. WW.1 has proved the signature of R. K. Yeshroy as Manager on it. It is dated 9th February, 1967. This authorisation says that the affected workman No. 1, N. K. Lal was authorised thereby as a senior overman in Bhowra (South) Colliery. Ext. W.7 is a certificate dated 25th June, 1968 under the signature of S. K. Juneja, Manager as proved by WW.1, certifying that affected workman No. 1 worked as a head overman (incharge) in Bhowra (South) Colliery under the aforesaid Manager. Ext. W.3 leave application form, an admitted document, describes affected workman No. 1 as senior overman. Ext. W.12 is the authorisation dated 1st February 1963 relating to affected workman No. 2, N. S. Sodhi. The evidence of WW.3 is that the original of Ext. W.2 was given to the Personnel Officer of the colliery. Ext. M.13 is the appointment letter of the affected workman No. 2 and WW.3 has proved the signature of Indar Mohan Thapper on it. According to WW.3 Indar Mohan Thapper is at present Director-in-Charge of the opposite party, M/S Karam Chand Thapper. It is dated 26th December, 1944. It says that affected workman No. 2 was appointed as an incharge for New and West Badjna collieries of the opposite party, M/S Karam Chand Thapper. Ext. W.14 is a certificate describing affected workman No. 2 as a senior overman. WW.3 has proved the signature of B. K. Talwar as Manager on it. It is dated 30th April, 1962. Ext. W.15 is a certificate dated 31st May, 1969, describing affected workman No. 2 as a head overman of Bhowra (South) Colliery. WW.3 has proved the signature of S. K. Juneja on it as the Manager. Ext. W.16 is the authorisation dated 13th November, 1962 describing affected workman No. 3, N. Khawas as a senior overman. WW.4 has proved the signature of R. K. Yeshroy as Manager on it. Ext. W.17 is a certificate dated 20th May, 1969, describing affected workman No. 3 as a senior overman. WW.4 has proved the signature of S. K. Juneja as Additional Manager of Bhowra (South) Colliery on it. Ext. W.21 is the authorisation relating to affected workman No. 4, B. P. Verma. WW.6 has identified the signature of R. K. Yeshroy as Manager on it. This authorisation mentions affected workman No. 4 as a senior overman. Ext. W.9 is an authorisation dated 1st January, 1963 authorising the affected workman No. 5 S. J. N. Sharma as a senior overman. WW.2 has proved the signature of R. P. Mehra as Manager on it. Ext. W.10 is the overman's daily report book. WW.2 has proved the signature of G. S. Singh, the then Assistant Manager on its first sheet. On the book and on its each sheet it is mentioned that it is a senior overman's daily report and the book relates to affected workman No. 5. Ext. W.11 is the muster roll. WW.2 has proved the signatures of B. S. Ramdas, Assistant Manager and Khanna, Manager on the sheet relating to January, 1968. Similarly the witness has proved the sheets relating to February, March and July, 1968. According to WW.2 the sheet for July was signed by R. P. Mehra, the Manager. The book, Ext. W.11 starts from January, 1968 and ends with December, 1969. In all the sheets the affected workman No. 5 is described as senior overman. Ext. W.11

Is the authorisation relating to affected workman No. 6, J. N. Seal. WW.5 states that he had given the original of Ext. W.18 to the Labour Officer, N. B. Jha. Ext. W.19 is the leave application form relating to affected workman No. 6. WW.5 has identified the signature of A. K. Khanna, Manager on it. In this leave application form affected workman No. 6 is described as a senior overman. A carbon copy of the monthly salary sheet for July, 1967 is Ext. W.8. WW.1 has proved the signatures of the Agent, S. N. Mukherjee, Manager, R. P. Mehra and another Manager R. K. Yeshroy on it. In this sheet names of workmen of North and South Bhowra Collieries are shown separately. Names of the affected workmen Nos. 5 & 6, S. J. N. Sharma and J. N. Seal respectively are at Serial Nos. 9 & 8 and of the remaining 4 affected workmen at Serial Nos. 21 to 24 and all of them are described as senior overmen. Ext. M.47 are original pay sheets and the pay sheet for the month of July 1967 is at pages 10 & 11. MW.1 the Personnel Officer of North & South Bhowra Collieries of the employers who is examined as MW.1 has admitted that in the original pay sheets for July, 1967, in Ext. M.47 at Serial No. 8 the designation of affected workman No. 6, J. N. Seal is struck off and added that it was done subsequently. The witness has shown that designation of affected workman No. 6, J. N. Seal in the pay sheet for January and February, 1967 is senior overman. In the pay sheet for the month of March, 1967, Ext. M.9 the name of affected workman No. 6 J. N. Seal is mentioned at Serial No. 75. The witness, MW.1 has admitted that there is over-writing in the column of designation. There is no suggestion that the workmen have forged any document to suit their convenience. On the other hand, MW.1 himself has pointed out that in some pay sheets designations of these affected workmen are over-written subsequently. Obviously, it is done to suit the defence pleaded by the employers. No doubt, in some of the pay sheets, Exts. M.7 to M.12, leave applications M.17 to M.19, M.31, M.32, M.33, M.38, M.39 and M.53 and other papers, Exts. M.3, M.4, M.23, M.41, M.43 and M.44, bonus registers Exts. M.5, M.25, M.15, M.30, M.36 and M.37 in Ext. M.49, Exts. M.6, M.14 and M.16 in Ext. M.50, in overman's daily report books Exts. M.27 and M.28, Form B register, M.29, the affected workmen are described only as overmen. But in Ext. M.13 in Ext. M.49 bonus register affected workman No. 5 is described as a senior overman. Out of the Exhibits marked for the workmen authorisations issued to the affected workmen are of considerable importance, inasmuch as they are mandatory to be issued under Regulation 36 of the Coal Mines Regulations, 1957. The counterfoil books containing Exts. M.22, M.24 and M.26 relate to the years 1961 and 1962, whereas the authorisations filed on behalf of the workmen are for 1962 onwards. The employers have not chosen to file the counter-foil authorisation books for the period for which the workmen have filed. For this reason the Tribunal is deprived of the opportunity to see if in the relevant counter-foils the affected workmen are described or not as senior overmen. The authorisation letters issued to the affected workmen 1 to 4 are signed by R. K. Yeshroy, Manager and to affected workmen 5 and 6 by R. P. Mehra, Manager. The employers did not choose to examine either of the two persons. There is no evidence either that these two persons are not available to give evidence. There is the evidence of WW.5 that R. P. Mehra is the Manager of Bhowra (North) Colliery. The Managers who had issued certificates to the affected workmen describing them as senior overmen, also are not examined. No evidence is led in respect of them also that they are not available. If not in all, in many of the documents of the employers the affected workmen are shown as senior overmen prior to 15th August, 1967, the date from which the recommendations are implemented and even thereafter. If the affected workmen were not designated by the employers as senior overman there is no explanation how their designations as senior overmen could appear in the documents of the employers and in particular the statutory authorisations issued to them.

7. Now, I propose to see if prior to 15th August, 1967, the date from which the employers have implemented the recommendations, the six affected workmen were drawing their pays as overmen or senior overmen. As I have already pointed out, before the recommendations came to be implemented the scales of pay of overmen and senior overmen were respectively Rs. 75—5—105—6—111 and Rs. 85—5—150—5—200. Ext. M.43 is an office order issued by the Chief Agent of the employers and it is dated 25/30th November, 1963, stating that with effect from 1st October, 1963 an increment of Rs. 10 was sanctioned in respect of affected workmen Nos. 2, 3 and 6 raising their basic pay to Rs. 121 per month. No reason is mentioned in this office order why the employers had given the increment. They did not even say that it was *ex-gratia* or *ad-hoc*. Rs. 121 per month is the basic pay beyond the maximum of the pay scale of overman and within the pay scale of senior overman. Without probing further into pay sheets and other documents let me advert to the admitted case of the employers. As I have already pointed out with reference to Ext. M.43, the employers have admitted in para 2(c) of their written statement that affected workmen Nos. 2, 3 and 6 started getting their

basic pay of Rs. 121 per month with effect from 1st October, 1963. In the same para the employers have stated that affected workman No. 1 was promoted as overman after August, 1965 and having earned annual increments he had reached the basic pay of Rs. 90 on 14th August, 1967. If affected workman No. 1 was promoted as overman from September, 1965, by 14th August, 1967 he could earn only one increment of Rs. 5 bringing his basic pay to Rs. 80 and not Rs. 90 as pleaded by the employers. It is not the case of the employers that he was given any increment when he was promoted as an overman. It is not even their case that they had given Rs. 10 increment to this affected workman also. Admittedly, no increment was given to any overman after 1963 to 1967. This is borne out by the fact that by Ext. M.43 increment of Rs. 10 was granted to affected workmen Nos. 2, 3 and 6 bringing their pays to Rs. 121 per month on 1st October, 1963 and as per the para of the written statement they were drawing the same pay till 14th August, 1967. Hence, the case of the employers is inconsistent and unbelievable. Regarding affected workman No. 4 the case of the employers is that he was working as a deputy overman till May 1963 getting a pay of Rs. 80 per month in the deputy overman's scale of Rs. 65—5—95, that he was promoted to work as a overman in June 1963 on a basic pay of Rs. 85 per month in the overman's scale and that in the same pay scale he was drawing Rs. 100 on 14th August, 1967 as his basic pay per month. In Mazumdar Award, Labour Appellate Tribunal Decision or Das Gupta Award there is neither a designation of a deputy overman nor a pay scale for the post. As per Das Gupta Award there were only 2 scales of pay, one for the overmen and the other for the senior overmen. That apart, it is not understood how he could draw Rs. 100 per month as basic on 14th August, 1967 if he was promoted as a overman from June, 1963 on a basic salary of Rs. 85 per month, because in the pay scale of a overman of Rs. 75—5—105—6—111 affected workman No. 4 could have earned only 4 increments from June 1963 to August, 1967 and each increment could be of only Rs. 5 per year. At that rate he could have drawn Rs. 105 as his basic pay and not Rs. 100 as pleaded by the employers. Consequently, in this case also the employers cannot be believed. The case of the employers as regards affected workman No. 5 is more unconvincing. The employers stated that affected workman No. 5 had reached the maximum of overman's scale and that the employers on generous ground gave him an increase in his basic pay raising it to Rs. 115 from November, 1966. In this case no particulars are given when the affected workman had reached the maximum of the pay scale as a overman and by what office order what increment was given raising his basic pay to Rs. 115 from November, 1966. In the pay scale of a overman the increment after Rs. 105 is only Rs. 6 and the maximum is Rs. 111. It is not explained how affected workman No. 5 was allowed to go beyond the maximum of the pay scale. Therefore, the explanation of the employers is unconvincing. The inference is irresistible that all the affected workmen were working as senior overmen in the pay scale of Rs. 85—5—150—5—200, inasmuch as all of them were drawing more than Rs. 111 and below Rs. 200, except affected workman No. 1, but in his respect also the case put forth by the employers is not convincing and as such cannot be believed.

8. Regarding the nature of work turned out by the six affected workmen there is no documentary evidence and as such, it must be inferred from the oral evidence led by the parties. All the six affected workmen, WW.1 to WW.6 have deposed that prior to implementation of the recommendations all of them were discharging duties of senior overmen and even after implementation of the recommendations they are performing the same duties. WW.7 is working at present as general in-charge in Bhowra (South) Colliery. It is in his evidence that immediately before the recommendations were implemented in the colliery all the six affected workmen were senior overmen. He has clarified that affected workmen at Serial Nos. 1 to 4 were working in Bhowra (South) Colliery and at Serial Nos. 5 & 6 in Bhowra (North) Colliery and that all of them are performing the same duties now which they were performing as senior overmen before implementation of the recommendations. In the cross-examination he has also pointed out the inclines which are in charge of the affected workmen. There is no rebuttal to his evidence. Among the four witnesses examined by the employers, MW.1 was the Welfare Officer of Bhowra (South) Colliery from 1959 to 1968 and since then he is the Personnel Officer of Bhowra (North) and Bhowra (South) Collieries. In such capacities he had rare occasions to go underground. MW.2 is in-charge of bonus and provident fund section of Bhowra (North) and (South) Collieries. He has conceded that he has no field work and his work is confined to his room. He has further admitted that he does not know actually what duties are performed by each of the six affected workmen. MW.4 is a clerk of leave section in-charge of Bhowra (North) and Bhowra (South) Collieries since 1961. Obviously, he has no means to know what work is actually turned out by each of the affected workmen. Thus, there remains the evidence of only MW.3 who is a 1st Class

Manager of Bhowra (North) Colliery. He has deposed that all the six affected workmen are working in general shift as overmen, that they do not work in the 2nd or 3rd shifts (4 P.M. to 12 midnight and 12 midnight to 8 A.M.) and that there are other overmen to work in these two shifts. He has further stated that the responsibility to confer with the 2nd class Asstt. Manager and arrange for materials and things for all the 3 shifts is only of the overmen working in the general shift. As I have already pointed out, the witness had deposed that all the six affected workmen work only in the general shift and as such, it was their responsibility to confer with the 2nd class Asstt. Manager and arrange for materials and things for all the 3 shifts. The witness has conceded in categorical terms that in the above sense the overmen working in the general shift have some extra responsibility over the responsibility of the overmen working in the other two shifts. It, therefore, follows that the duties performed by the six affected workmen were different and something more than the duties performed by overmen. By implication it supports the case of the workmen that the six affected workmen were and are working as senior overmen and not as simply overmen as pleaded by the employers.

9. Thus, from their designations found in the records of the employers, from the pays drawn and from the nature of duties performed by them it emerges that the six affected workmen were working as senior overmen before the recommendations were implemented and are continuing to discharge the same duties even thereafter. As I have pointed out earlier, by the memorandum of settlement dated 29th September 1967, Ext. W.4 the employers agreed to implement the recommendations with retrospective effect from 15th August 1967. It emerges from the evidence of WW.1 that all the six affected workmen submitted a joint representation to the Agent through a letter complaining that in implementation of the recommendations their designations of senior overman had been changed forcibly to overman although they had been working as senior overman since a long time. The letter is Ext. W.6. The evidence of WW.1 is that he himself had handed over the letter to the Agent, S. N. Mukherjee and a copy of it to the Regional Labour Commissioner. No attempt is made to contradict the evidence by examining the Agent, S. N. Mukherjee. The letter is dated 15th November 1967 and it says that a copy thereof was forwarded to the Regional Labour Commissioner (C) Dhanbad. It is in the evidence of WW.1, which is also an admitted position that the Regional Labour Commissioner (C) Dhanbad forwarded the copy of the letter, Ext. W.6 to the Labour Enforcement Officer for enquiry. The letter of the Labour Enforcement Officer dated 9th/10th April 1968 addressed to the employers under copy to the Regional Labour Commissioner (C) Dhanbad for information is Ext. W.2. It is an admitted document. Through the letter, Ext. W.2 the Labour Enforcement Officer says that on his enquiry into the above matter he found that the six affected workmen had been designated as senior overmen before the implementation of the recommendations. I also find from the failure report accompanying the order of Reference that during the conciliation proceedings before the Assistant Labour Commissioner (C) Dhanbad O. P. Lamba, Assistant Chief Personnel Officer representing the employers had stated that the six affected workmen "were authorised to act as senior overmen for a short period before the recommendations were implemented." This statement further supports my inference that the six affected workmen were senior overmen before the recommendations were implemented, for however a short period that might be. In this view I have no hesitation to hold that the six affected workmen were senior overmen before the implementation of the recommendations and they are continuing to be so even thereafter.

10. I, therefore, find that the action of the management of Bhowra Colliery of Messrs Karamchand Thapar and Brothers (Private) Limited, Post Office Bhowra, Dhanbad in altering the designation of the following six senior overmen and showing them as overmen in the pay sheets commencing with the book for October, 1967 and refusing to pay them wages in the pay scale provided for senior overman by the Central Wage Board for the Coal Mining Industry was not justified and, consequently, they are entitled to be designated as senior overmen with effect from 15th August 1967 and be paid their wages and all other emoluments in accordance with the recommendations of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry:

1. Shri N. K. Lal.
2. Shri N. S. Sodhi.
3. Shri N. Khawas.
4. Shri B. P. Verma.
5. Shri S. J. N. Sharma.
6. Shri J. N. Seal.

The award is made accordingly and submitted under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

(Sd.) N. VENKATA RAO,  
Presiding Officer,  
Central Govt. Industrial Tribunal,  
(No. 2) Dhanbad.  
[No. 2/184/68-LR.II.]

S.O. 167.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of Shri O. Venkatachalam, Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi, Arbitrator in the industrial dispute between the employers in relation to the National Coal Development Corporation Limited, Darbhanga House, Ranchi and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th December, 1970.

In the matter of Arbitration of an industrial dispute between the management of M/S. N.C.D.C. Ltd., Ranchi and their workmen represented by the Colliery Mazdoor Sangh, Madhya Pradesh Colliery Workers Federation and State Collieries Mazdoor Union.

**SHRI O. VENKATACHALAM, CHIEF LABOUR COMMISSIONER (CENTRAL) & ARBITRATOR**

**PRESENT:**

*Representing the Management:—*

1. Shri R. S. Murthi, Additional CPO, M/s. NCDC Ltd., Ranchi and others.

*Representing the workmen:—*

1. Shri Bindeswar Dube, M.L.A, General Secretary, Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad.
2. Shri Damodar Pande, Organising Secretary, Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad and others.
3. Shri B. N. P. Sinha, Organising Secretary, M.P. Colliery Workers Federation.
4. Shri H. R. Gulati for NCDC Workers Association, South Balanda (Orissa).

By an agreement dated 14th January, 1970 the Management of M/s. NCDC Ltd., Ranchi on the one hand and the representatives of the Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad and the Madhya Pradesh Colliery Workers' Federation, Chirimiri on the other, agreed to refer the industrial dispute between them for my arbitration under Section 10A of the I.D. Act with the following term of reference:—

- "Whether the claim of the Unions that the workmen of NCDC are entitled to get increment in their Wage Board scale of pay w.e.f. 1st October, 1967, is justified; if so, in what way the increment agreed to by the management with effect from 15th August, 1969 should be adjusted; or
- (ii) Whether the workmen are entitled to the benefit of increment in their basic wages accruing upto 14th August, 1967, for the purpose of computation of their wages in the Wage Board scale w.e.f. 15th August, 1967; if so, in what way the increment agreed to by the management with effect from 15th August, 1969 should be adjusted."

2. By another agreement dated 17th March, 1970 the Management of M/s. NCDC and the representatives of the State Collieries Mazdoor Union, Bermo agreed to refer the industrial dispute between them for my arbitration under Section 10A of the I.D. Act, 1947 with the same terms of reference as mentioned above. In both the cases, the parties agreed to be bound by my decision but they desired that I should make my award within a period of six months from the date on which the agreement was published in the Gazette of India or within such further time as may be extended by mutual consent.

3. The two arbitration agreements referred to above were published by the Ministry of Labour and Rehabilitation in the Gazette of India dated 28th February, 1970 and 23rd May, 1970 respectively.

4. Subsequently in the Gazette of India dated 1st August, 1970, the Ministry of Labour and Rehabilitation issued a notification under Sub-Section (3A) of Section 10A of the I.D. Act, 1947 read with Rule 8A of the I.D. (Central) Rules, 1957 notifying the first mentioned arbitration agreement between the Management

of NCDC and the Colliery Mazdoor Sangh and the Madhya Pradesh Colliery Workers' Federation for the information of the employers and the workmen who were not parties to the said agreement but who were concerned in the said dispute, stating that the persons making the said reference for my arbitration represented the majority of each party. The said Notification of the Ministry was forwarded among others to the State Collieries Mazdoor Union, Coal Workers' Union, South Karanpura Coal Miners Union, the Indian Government Railway Coal Department Employees Association, the National Coal Organisation Employees Association, the Dera Colliery Labour Union, the Deulbera Colliery Labour Union, the National Coal Development Workers' Association, the Madhya Pradesh Koyala Mazdoor Panchayat, the Khadan Mazdoor Union, the Surguja Koyala Khadan Karamchhari Sangh, the Betul Zilla Rashtriya Khadan Karamchhari Sangh, the Colliery Mazdoor Union, the Maharashtra Pradesh Rashtriya Koyala Khadan Kamgar Sangh, the Jamuna-Kalari Mazdoor Sangh, the Koyala Shramik Sangathan and the Indian National Mine Overmen, Sirdars and Shot Firers Association, none of which was a party to the said arbitration agreement. In the circumstances, the period of six months agreed to between the parties for making my Award in this case would count from 1st August, 1970 i.e., it will end on 1st February, 1971. However, the representatives of the Colliery Mazdoor Sangh who unfailingly attended the hearings in this case specifically agreed to the extension of the time-limit till 15th January, 1971 for making my Award.

5. In response to my communication addressed to all the parties concerned for submission of their respective statements of the case, the Management of NCDC, the Colliery Mazdoor Sangh and the State Colliery Mazdoor Union submitted their statements of the case, but only the Management and the Colliery Mazdoor Sangh submitted their rejoinders to each other's statement of the case. Thereafter, the case was taken up for hearing on 8th August, 1970 at Ranchi and on 29th September 1970 at Varanasi but hardly any progress was made in this case on those dates due to the preoccupation of the Arbitrator and the parties with two other arbitration cases. The case was later taken up for full and final hearing at Delhi on the 10th and 11th December, 1970. The representatives of the Colliery Mazdoor Sangh took part in these hearings, although Shri H. R. Gulati also attended the hearing at Delhi on 10th December, afternoon on behalf of the NCDC Workers' Association, South Balanda. With the exception of Shri Gulati's attendance, none of the trade unions which were impleaded in this case by the Ministry's Notification under Section 10A(3A) of the Act responded to any of the Notices issued to them for all the hearings of the case. Likewise, the State Collieries Mazdoor Union which was a party to the arbitration agreement dated 17th March, 1970 attended none of the hearings held by me in this case. However, the issue in both the arbitration agreements being identical, I shall dispose of the two references together in this Award.

6. The contentions of the parties have been set out quite elaborately in their statements of the case, and in the rejoinders to each others statement, and it is needless for me to reproduce them in extenso in this award. It is enough if I set out briefly the relevant facts of the case and contentions of the parties as per their statements and the oral submissions made by them during the hearings before me. Before I do so, I must mention that out of nearly 67000 total employees of N.C.D.C. Ltd., the issue under arbitration concerns about 45000 workmen.

7. The wage board for coal mining industry was set up by the Government of India in August 1962 and it submitted its report to the Government in February, 1967. In Section F Chapter III of its report, the wage board recommended that the total emoluments of the workmen as on 1st October, 1966 should form the basis for adjustment of their pay in the revised scales of pay recommended by the board. It was also recommended by the majority of the members of the Board (employers' representatives dissenting) that its recommendations should be implemented from 1st January, 1967. The Board further recommended that after fitment of the individual workmen in the revised pay scales, they should be granted service increments at the rate of one for every three completed years of service but the number of increments should not in any case exceed three. The Board's report is, however, not clear as to the date upto which the past service was to count for the grant of service increments. Likewise, the Board did not make any specific recommendation as to the grant of annual increments in the revised pay scales recommended by it. The Government, however, while accepting some of the recommendations of the Board including the new pay scales, directed the employers in coal industry to implement the accepted recommendations with effect from 15th August, 1967, but the Government's Resolution was silent on the question of annual increments. Most of the large employers including N.C.D.C. had implemented the Board's recommendations including the revised

scales of pay from 15th August, 1967 taking the total emoluments of individual workmen as on 1st October, 1966 for adjustment of their pay in the new pay scales. They also started granting annual increments in the revised scales on 15th August, 1968 and on the 15th August of each succeeding year. Some of the employers including N.C.D.C. had also counted the total service put in by individual workmen till 14th August, 1967 for granting them service increments but they did not take into account the increments earned by the workmen in their old scales between the dates 1st October, 1966 and 14th August, 1970.

8. Subsequently in about September 1969 some of the trade unions including the Colliery Mazdoor Sangh and the State Collieries Workers' Union who are parties to the two arbitration agreements in question had started agitation for grant of annual increments in the revised pay scales on 1st October, 1967 and on the 1st October of each year thereafter. This demand of the workmen was met only by two employers in the industry, fully by Messrs. Tata Iron & Steel Company and partly by Messrs. N.C.D.C. Ltd., the latter having granted an additional increment to the workmen on the 15th August, 1969 i.e. the workmen in their case were given two annual increments in the revised scales on 15th August, 1969. The management of N.C.D.C. had also granted to the workmen who joined their service after 1st October, 1966 the benefit of future increments in the revised scales on the anniversary dates of their joining. Likewise, the workmen of the Corporation who were promoted to higher posts after 1st January, 1967 had been given the benefit of annual increments to coincide with the anniversary dates of their promotion. Not satisfied with these concessions, the Colliery Mazdoor Sangh and the State Collieries Workers' Union reiterated their demand for increments in the revised scales. As the wage board's report as well as the Government's Resolution accepting the Board's recommendations were silent on the matter, the management of M/s. N.C.D.C. Ltd. and the two unions concerned entered into the two arbitration agreements mentioned earlier referring the issue in its two parts for my arbitration.

9. According to the demand of the unions in this case, the workmen should have been granted one annual increment on 1st October, 1967, another on 1st October, 1968, the third on 1st October, 1969 and so on, but the management of N.C.D.C. Ltd. granted in common with other employers in the industry (with the exception of M/s. Tata Iron & Steel Co.) first increment on 15th August, 1968, the second on 15th August, 1969 and the third (special) increment again on 15th August 1969. The result is that while the first two increments were postponed, according to the unions, by  $10\frac{1}{2}$  months in each case, the third increment was accelerated by  $1\frac{1}{2}$  months. It was, therefore, argued on behalf of the workmen that the management should pay the workmen concerned arrears of increment for  $19\frac{1}{2}$  months (twice the time lag of  $10\frac{1}{2}$  months minus  $1\frac{1}{2}$  months). On this net result of the workmen's demand, the representative of the management pointed out that the acceleration of the third increment by  $1\frac{1}{2}$  months would accrue to the workmen in a recurring manner for the rest of their service and as such should more than compensate them for the  $19\frac{1}{2}$  months' arrears of increment which has been asked for by the workmen. He also referred to the various other concessions which the management of N.C.D.C. Ltd. had granted to the workmen while implementing the wage board's recommendations and in particular to the concessions granted to the new entrants after 1st October 1966 to earn their increments on the anniversary dates of their joining the Corporation's service and to the promotees after 1st January 1967 to earn their increments in promotion grades on the anniversary dates of their promotion. While appreciating these concessions, it was pointed out on behalf of the workmen that they gave rise to further anomalies in that some of the senior employees have been getting lower pay on their fitment in the wage board's scales than their juniors in the same grades. At this stage the management's representative, Shri R. S. Murthy invited my attention to their Circular O.M. No. PD/WB/Imp/Monthly Staff/68-Pt III dated 1st August, 1970 which sought to remove these anomalies on the basis of the Government of India's decisions under F.R. 22-C. To this Shri Damodar Pandey, representative of the Colliery Mazdoor Sangh reached by complaining that the said office memorandum of the management has not been properly implemented. Thereupon, the management's representative promised to look into the matter and see that the memo is fully implemented. I hope he would do so without delay.

10. On the demand of the Unions for grant of annual increments in the revised scale on 1st October, 1967 and on the anniversary date in each succeeding year on the ground that the individual workmen were fitted in the revised scales on

the basis of their total emoluments on 1st October, 1966, the management's representative argued that as the new scales were implemented from 15th August, 1967 they were fully justified in granting annual increments on the anniversary date of each succeeding year, particularly as the wage board's report and the Central Government's Resolution accepting the Board's recommendations were both silent on this question. In support of his contention, he invited attention to the practice adopted by the coal industry while granting increments to the monthly-rated employees under the Mazumdar Award and to the daily-rated employees under the arbitration award of Shri Das Gupta who specifically recommended that the workmen would earn their annual increments in the scales recommended by him on the anniversary date of implementation (1st June, 1959) of those scales. Attention was also invited by the management's representative to the recommendations of the wage boards for limestone and dolomite and iron ore industries which were implemented from 1st January, 1969 where the Boards had specifically recommended that the annual increments should be granted in the new scales on the anniversary of the date of implementation. All these are important considerations which are quite weighty in favour of the management's case.

11. The second part of the issue referred for my arbitration suggests that the workmen should have been allowed the benefit of increment in their old scales accruing between 1st October, 1966 and 14th August, 1967 for the purpose of computation of their total emoluments for fixation of their pay in the new scales with effect from 15th August, 1967. On this question the management's representative referred to the fact that both under the award of the Mazumdar Tribunal which came into force in May 1956 and the arbitration award of Shri Das Gupta which came into force from 1st June, 1959, most of the workmen had reached the maximum of their respective pay scales much earlier than 1966 and that as such they would not have earned any increment immediately before or after October, 1966. He also invited attention to the fact that in terms of the wage board's recommendations, the workmen were guaranteed minimum increase of 10 per cent in their existing emoluments while fixing their pay in the new scales and they were fully compensated for the rise in the cost of living between 1st October, 1966 and 15th August, 1967 by means of variable dearness allowance in accordance with the wage board's formula. He accordingly pointed out that no hardship at all was caused to the workmen by taking their total emoluments as on 1st October, 1966 for the fixation of their pay in the new scales with effect from 15th August, 1967 in terms of the Government's Resolution. The observations of the Wage Board in Paragraphs 13 and 14 of Chapter VIII of its report show that the Board itself had visualised the possibility of its recommendations being brought into force even after 1st April, 1967. It was further pointed out on behalf of the management that they had also counted the service of individual workmen upto 14th August, 1967 for granting them service increments in terms of the wage board's report. Their representative also referred to the fact that as against the minimum annual increment of three paise per day (78 paise per month) for a daily-rated workmen under the Das Gupta Award and Re. 1 per month for monthly-rated workmen under the Mazumdar Award, the corresponding rates of increments under the wage board's scales of pay are ten paise per day (Rs. 2.60 per month) for daily-rated workmen and Rs. 3 per month for monthly-rated workmen. These rates of increment under the wage board's recommendations being substantially more than the rates under the earlier awards applicable to the coal industry, the workmen should not complain of any hardship on account of the principle adopted by the management of N.C.D.C., in common with other employers in the industry, of granting their workmen annual increments on each anniversary date from 15th August, 1967. I see no reason to disagree with the management or to minimize the weight of their arguments in support of their action in granting increments on the 15th August, 1968 and on the anniversary dates thereafter. By granting an additional increment on 15th August, 1969 at a recurring cost of Rs. 40 lakhs per annum, they had already gone ahead of all other employers in the industry with the exception of TISCO Ltd. Any further liberalisation in regard to annual increments by this Corporation would entail further strain on its finances which, on the basis of the facts and figures produced by its representative during the final hearing of the case on 11th December, 1970, are not too bright. Any such liberalisation would also have wide repercussions on the entire private sector of the coal industry as also on the other public sector company viz. M/s. Singareni Colliery Co. Ltd., who have all been struggling hard due to the keen competition in the industry consequent on the removal of controls on coal since the middle of 1967. The only employer who has granted the annual increments from 1st October 1967 and on the anniversary dates thereafter is M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd. whose collieries being captive mines of the steel



industry, could afford to do so because they have not to compete with other employers in the industry for their survival.

12. In the circumstances, I accept the contentions of the management of N.C.D.C. Ltd. and hold that the claim of the Unions that the workmen of the Corporation are entitled to get increment in their wage board's scales of pay with effect from 1st October, 1967 is not justified. Consequently, the workmen are not entitled to any relief under this Award. The reference to me stands disposed of accordingly.

(Sd ) O. VENKATACHALAM.

Chief Labour Commissioner (Central)  
and  
Arbitrator.

[No. 8/19/70-LR-II.]

**S.O. 168.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Banalee Colliery, Post Office Nandi, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 22nd December, 1970.

# CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

REFERENCE No. 38 OF 1970

## PARTIES:

Employers in relation to the management of Balalee Colliery.

AND

Their workmen.

## PRESENT:

Mr. B. N. Banerjee.—Presiding Officer.

## APPEARANCES:

*On behalf of Employers.*—Mr. K. P. Mukherjee, Advocate, with Mr. J. D. Mukherjee, Advocate.

*On behalf of Workmen.*—Mr. Sunil Sen, Organising Secretary, Colliery Mazdoor Sabha (AITUC), Asansol.

STATE: West Bengal.

INDUSTRY: Coal Mines.

## AWARD

By order No. 6/48/70-LR-II, dated August 27, 1970, the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), referred the following industrial dispute between the employers in relation to the management of Banalee Colliery and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely:—

“Whether the retrenchment of the following workmen made by the management of Balalee Colliery, Post Office Nandi, District Burdwan with effect from the 1st August, 1970, was justified and legal? If not, to what relief are they entitled?”

Sl. No.	Name	Designation
1.	Sri Hablal Joyswara	Loader
2.	Sri Jainath Bhar	do
3.	Sri Sarwan Bhar	do
4.	Sri Parsotem Kewat	do
5.	Sri Babu Pashi	do
6.	Sri Ganga Ram Kahar	do
7.	Sri Ram Lakhan Hartjan	do
8.	Sri Ramadhar Joyswara	do
9.	Sri Barkhu Kolri	do
10.	Sri Harichand Bhar	do

S. No.	Name	Designation
11. Sri Saudagar Gope		Loader
12. Sri Degree Kurmi		do
13. Sri Kishen Pd. Roy		do
14. Sri Gogrup Kurmi No. 2		do
15. Sri Tajai Jaiswara		do
16. Sri Hira Lal Koiri		do
17. Sri Sheo Sankar Bind		do
18. Sri Degree Jaiswara		do
19. Ssi Ch. Ram Khelowan Pasi		do
20. Sri Sanchar Singh		do
21. Sri Mewala Jaiswara		do
22. Sri Bhageloo Jaiswara		do
23. Sri Budhu Jaiswara		do
24. Sri Tasildar Jaiswara		do
25. Sri Karmani Das		do
26. Sri Rajdeo Gope		do
27. Sri Ram Surat Harijan		do
28. Sri Lautoo Jaiswara		do
29. Sri Ramrathan Jaiswara		do
30. Sri Nauhar Kurmi		do
31. Sri Sukh Nandan Pasi		do
32. Sri Amir Das		do
33. Sri Rajmon Kewat		do
34. Sri Budhiram Bind		do
35. Sri Abdul Mia		do
36. Sri Jaikaran Jaiswara		do
37. Sri Chhota Pasi		do
38. Sri Kesho Harijan		do
39. Sri Jokho Gope		do
40. Sri Suprallal Bhar		do
41. Sri Mathuri Kumhar		do
42. Sri Hublal Kumhar		do
43. Sri Ram Nath Kurmi		do
44. Sri Sukhram Kurmi		do
45. Sri Jagrup Kurmi		do
46. Sri Beharilal Kurmi		do
47. Sri Muner Gope		do
48. Sri Srinath Bind		do
49. Sri Babulal Harijan		do
50. Sri Ram Garib Kewat		do
51. Sri Mukundi Jaiswara		do
52. Sri Sheonath Bhar		do
53. Sri Shankar Bhar		do
54. Sri Deosaran Mahato		do
55. Sri Terash Bhar		do
56. Sri Nandlal Jaiswara		do
57. Sri Rameswar Pasi		do
58. Sri Shri Kishan Harijan		do
59. Sri Ramlakhan Kurmi		do
60. Sri Lahori Pasi		Pick-miner.
61. Sri Bhagbat Harijan		do
62. Sri Chaitar Shaw		do"

2. The employers in relation to the management of Banalee Colliery is an incorporated body of the name of Nimcha Coal Company Limited. The employer Company filed a written statement. By way of justification of the order of retrenchment, they pleaded uneconomic working since the beginning of the year 1970 and trade Union rivalry and gross indiscipline amongst the workmen further contributing to the uneconomic workings, which compelled them at first to retrench a large number of workmen and thereafter to close down the colliery completely with effect from August 29, 1970. In paragraph 5 of the written statement they also pleaded:

"\* \* \* the financial losses relating to the running of the Banalee Colliery continued in an aggravated form. Further, on account of depletion of the working reserve in Bogra Seam and the shortage of working faces at Satgram Seam of the Banalee Colliery the Company had in employment large number of surplus hands but was unable to take

necessary steps to retrench some of such surplus hands on account of the continued unlawful and subversive activities at colliery as well as in the neighbourhood of the colliery and/or apprehensions of further troubles at the colliery. Such continuance of the employment of large number of surplus hands at the Benalee Colliery further adversely affected the working and raising at the colliery and continued financial losses to the company. In this view of the matter the Company was compelled to take a final decision to retrench some of such surplus hands in order to avoid further financial losses to the Company. Such decision of the Company was and is bona fide and justified for the reasons amongst others to save further deterioration of the critical financial position of the Company."

Since the present cause of action arose prior to the closure of business, the same does not fall outside the scope of industrial adjudication.

3. By a notice dated July, 21, 1970, the employer Company at first retrenched 71 workmen with effect from July 27, 1970. The list of workmen retrenched under the first notice was amended and on July 22, 1970 there was a second notice issued retrenching 71 workmen on the basis of "last come first go" principle taken categorywise. The Regional Labour Commissioner (C), Asansol, immediately took up Conciliation proceedings in the matter and called upon the management to postpone the date of retrenchment. Thereupon the management shifted the date of retrenchment and made it effective from August 1, 1970. The conciliation, however, failed. The management takes up the stand that they were justified in retrenching the workmen for reasons stated above.

4. The cause of the workmen was taken up by a trade Union of the name of Colliery Mazdoor Sabha. In the written statement filed by the said trade Union, there is a sizeable history given of unfair labour practice said to have been adopted by the management for a long time. I am not, however, concerned with that history in the present reference. In paragraphs 12 to 16 of the said written statement it is pleaded as follows:

- "(12) That in any event, the management did not give effect to its notice dated 21st July, 1970, at Annexure B to its statement. The workmen concerned continued to work and to be marked present till 31st July, 1970. But when they reported for duty on 1st August, 1970 they were told that they had been retrenched with effect from 1st August, 1970.
- "(13) That Union emphatically states that no notice whatsoever was received by any of the workmen of the management decision to retrench them from 1st August, 1970.
- "(14) That the union submit that the notice dated 21st July, 1970, having lapsed through non-implementation, the purported retrenchment with effect from 1st August, 1970, without any notice whatsoever is illegal.
- "(15) That when pursuant to the notice dated 21st July, 1970 the workmen concerned went to collect their dues, including those under section 25F of the I.D. Act, they were not offered anything.
- "(16) That the junior workmen to those purportedly retrenched and doing similar work were in service at the Colliery at the date of retrenchment."

I am not concerned with the rest of the written statement, regard being had to the limited scope of the arguments advanced by the parties.

5. Mr. Sunil Sen, who appeared on behalf of the trade Union, took three points for my consideration, namely, (a) that the notice of retrenchment was too short, (b) retrenchment compensation was not paid to the workmen at the time of retrenchment and (c) in retrenching the workmen the principle of last come first go was not observed.

6. Before I take up the first two points, I desire to dispose of the last point, because that may be very shortly done. Only one witness was examined on behalf of the workmen, namely, Shankar Rajbhar, himself a retrenched workman, who is S. L. No. 53 in the order of Reference, under the name of Shankar Bhar. In answer to a question put by the Tribunal, he replied:

"I do not know if anybody amongst the loaders or pick-miners junior to those in service were retained in service and senior men were retrenched."

It appears from the order of reference itself that the workmen who had been retrenched all belong to the category of loaders or pick-miners. Therefore, there is no evidence to show that categorywise the principle of "last come first go" was not followed in making the order of retrenchment.

7. I now turn to the first taken, namely that the retrenchment notice was too short. Under Section 25F of the Industrial Disputes Act, it is stated:

"25F. No. workman employed in any industry who has been in continuous service for not less than one year under employer shall be retrenched by that employer until—

- (a) the workman has been given *one month's notice in writing* indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired, or the workman has been paid in lieu of such notice wages for the period of the notice;

Provided that no such notice shall be necessary if the retrenchment is under an agreement which species a date for the termination of service;

- (b) \*\*\*

- (c) \*\*\*" (Underlined by me)

It is nobody's case that the workmen who were retrenched in the instant reference had put in less than one year's service or that the retrenchment was made under the agreement specifying the date for termination of service. The two notices of retrenchment given in this case were both exhibited in this Reference. The notice of retrenchment, dated 21st July, 1970, is Ex. 9 and is set out below:

#### *"Notice of Retrenchment*

Attention of all workmen is drawn to the continued uneconomic working of the mines, gradual exhaustion of the Bogra Seam non-availability of sufficient jobs relating to the working of the Bogra Seam in particular and other mining operations in general. Workmen concerned are further aware of the non-availability of working areas in connection with the Satgram Seam and the possibilities of further development/depillaring, etc. of the said Satgram Seam, which would take sufficient time. In the circumstances stated above it is difficult for the Company to provide employment to large number of surplus hands as it has adversely affected the financial position of the Company by recurring losses relating to the running of the Colliery.

In the circumstances stated above, the Company after due consideration of the matters referred to above as well as other relevant factors has decided to retrench at this stage, workmen whose names are stated in the Annexure 'A' to this Notice and such workmen concerned are notified that for the reasons stated above, are hereby retrenched with effect from the 27th July, 1970 on the principle of "last come first go" in the categorywise basis and such workmen are required to collect immediately the amount payable in terms of section 25F of the Industrial Disputes Act, if eligible, and in case any workman fails to collect the same, such amount of money would be kept ready for disbursement and shall be treated as valid tender to the workmen notified by this Notice. The retrenched workmen concerned would be paid their legal dues in due course.

The workmen concerned hereby retrenched are also notified individually by letters which are being sent under Registered A/D and Certificate of Posting to expedite their acceptance of payment referred to above on account of retrenchment. Such retrenched workmen are required to notify in writing to the Company their respective addresses so that correspondence if any, may be made in future. (Underlined by me).

Enclo: Annexure "A" as stated in the Notice.

(Sd.) S. BAGCHI,  
Manager,  
21-7-70  
Banalee-Colliery,  
P. O. Nandi,  
Buxdwan".

The notice, dated 22nd July, 1970, is Ex. 10 and is also set out below:

*"Re: Notice of retrenchment"*

In continuation of this office notice dated 21-7-70, I hereby notify that the annexure to the said notice has been revised and an amended list is annexed herewith showing the names of workmen who shall be retrenched with effect from 27-7-1970. The previous annexure to notice dated 21-7-1970 stands cancelled.

(Sd.) Illegible,  
27-7-70

Manager,

P. O. Nandi, Burdwan."

The effective notice of retrenchment must, therefore, be the notice of July 22, 1970 because that contained the final list of workmen retrenched. The date from which the retrenchment took place was August 1, 1970. Thus whether counted from July 21, or from July 22 one month's notice in writing was not given to the workmen. Therefore, the notice, as issued, was on the face of it too short and violated one of the conditions present to an order of retrenchment.

8. Mr. K. P. Mukherjee, learned Counsel for the management, however, tried to salvage the position with the argument that even if the first part of Section 25F(a) was not satisfied, the order of retrenchment should not be interfered with because the workmen were offered in lieu of such notice wages for the period of the notice. I am not satisfied with this argument. The law on this point has been laid down by the Supreme Court several times and I am referring one of them, namely, the case of *Bombay Union of Journalists vs. State of Bombay*, (1964) 1 LLJ 351 at 357, (per Gajendragadkar J, as he then was):

"Similarly, Cl. (b) provides that the workman has to be paid, *at the time of retrenchment*, compensation which shall be equivalent to fifteen days' average pay for every completed year of service, or any part thereof in excess of six months. It would be noticed that this payment has to be made at the time of retrenchment, and this requirement again provides a safeguard, in the interests of the workman; *he must be given one month's notice or wages in lieu thereof and he must get retrenchment compensation as prescribed by Cl. (b)*. The object which the legislature had in mind in making these two conditions obligatory and in constituting them into conditions precedent is obvious. These provisions have to be satisfied before a workman can be retrenched." (Underlined by me).

In the instant case, the workmen were retrenched under notice and under offer of retrenchment compensation. When one reads Exts. 9 and 10, he does not feel that the retrenchment was being made by payment of wages for the period of notice, in lieu of notice. Assuming for the sake of argument, that in a case where the notice is otherwise bad the same can be salvaged if, by chance, the workmen have been paid at the time of service of notice a month's wages apart from what is due to him by way of compensation under Cl. (b) of Section 25F, even then, there is nothing to indicate that such an amount was paid to the workmen at the time of retrenchment. The notice, merely required the workmen to "collect immediately the amount payable in terms of Section 25F of the Industrial Disputes Act, if eligible, and in case any workman fails to collect the same, such amount of money would be kept ready for disbursement and shall be treated as valid tender to the workmen notified by the Notice". The notice further says that the retrenched workmen concerned would be paid their legal dues in due course. In my reading the first requirement calling upon them to collect the amount referred to compensation payable under Cl. (b) of Section 25F or else there would not have been any question of keeping the same ready for disbursement in case of immediate non-collection and the second requirement about payment of legal dues referred to arrears of wages, bonus, Provident fund, etc. if any due and has nothing to do with payment in lieu of notice envisaged under Section 25F(a).

9. Mr. K. P. Mukherjee made further attempt to by-pass this provision by placing reliance upon a judgment of a single Judge of the Calcutta High Court in *National Iron & Steel Company Ltd. vs. Third Industrial Tribunal, West Bengal*, (1964) 1 LLJ. 525 at 527. He particularly relied upon the following passage:

"That the conditions in S. 25F are conditions precedent are beyond dispute. But still then the question remains whether an offer for payment of

wages and compensation is equivalent to payment itself and whether by offering such payment, in the letter of retrenchment, the conditions precedent should be deemed to have been complied with Section 25F no doubt says that no workman shall be retrenched "until" he has been given either one month's notice or has been paid, in lieu of such notice wages for the period of notice and that such workman has been paid compensation calculated under s. 25F (b). But it may be difficult to make a workman accept payment if he will not himself do that. Therefore, an unconditional offer for payment, preceding retrenchment may be equivalent payment."

In my reading the above judgment was little concerned to payment under Cl. (a) of Section 25F. It was concerned with payment under Cl. (b) of the Section. It is safer to serve a notice and then to retrench but those who will not even wait for one month must be careful, before they can avoid service notice, to pay and then retrench, that is to say, to do that simultaneously or one after the other. Mere offer for payment will not do. I therefore, hold that the first point that the notice was too short is a point of substance and should be upheld.

10. I turn now to the second point, namely, the compensation was not paid. There is nothing to show that compensation under Clause (b) of Section 25F was paid and collected by the workmen. But since in the notice there was an unconditional offer for payment and since the workmen were at liberty to collect the compensation before they were retrenched, I do not uphold this point.

11. In the view that I take, I hold that the retrenchment of 62 workmen named in the order of Reference, by the management of Benalle Colliery with effect from August 1, 1970 was not justified and legal. As such, they shall be treated as to have never been retrenched from service. Consequently, they will be entitled to their wages for their period of forced unemployment.

This is my award.

Dated December 16, 1970.

(Sd.) B. N. BANERJEE,  
Presiding Officer.  
[No. 6/48/70-LRIL.]

S.O. 169.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 3), Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jealgora Colliery of Messrs East Indian Coal Company Limited, Post Office Jealgora, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 22nd December, 1970.

THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 3) DHANBAD  
REFERENCE No. 9 OF 1970

PRESENT:

Shri Sachidanand Sinha, M.A., M.L., Presiding Officer.

PARTIES:

Employers in relation to the Jealgora Colliery of M/s. East Indian Coal Co. Ltd.

Vs.

Their workmen.

APPEARANCES:

For employers—1. Sri S. S. Mukherjee, Advocate.

2. Sri J. N. P. Sahi, Labour Adviser.

For workmen—Sri S. Das Gupta, Secretary, Colliery Mazdoor Sangh.

INDUSTRY: Coal.

STATE: Bihar.

Dhanbad, dated the 15th of December, 1970

AWARD

1. The Central Government, being of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Jealgora Colliery of

Messrs East Indian Coal Company Limited, Post Office Jealgora, District Dhanbad, and their workmen by its order No. 2/196/69-LR11, dated the 17th of January, 1970 referred under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication the dispute in respect of the matters specified in the Schedule annexed thereto. The Schedule is extracted below:—

**SCHEDULE**

‘Whether the action of the management of Jealgora Colliery of Messrs East Indian Coal Company Limited, Post Office Jealgora, District Dhanbad in not placing Sarvashri Pashupati Prasad and Jahar Roy, stowing Clerks in clerical Grade—II in the scale of Rs. 205—7—275—10—325 as per recommendations of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry is justified? If not, to what relief are these two workmen entitled?’

2. The parties have filed their written statements but it is unnecessary to state the respective cases of the parties because the dispute has been amicably settled. The parties have filed a joint petition of compromise which has been verified by S/Sri J. N. P. Sahl, Labour Adviser and S. S. Mukherjee, Advocate (Executive Committee Member, Raniganj Chamber of Commerce) on behalf of the employers and by S/Sri S. Das Gupta, Secretary of the Union, Pashupati Prasad and Johar Roy, the concerned workmen.

3. According to the terms of the memorandum of settlement it has been agreed that S/Sri Pashupati Prasad and Jahar Roy, the concerned workmen, will be placed in Clerical Grade II in the Scale of Rs. 205—7—275—10—325 as per recommendations of the Central Wage Board (for Coal Mining Industry) with effect from the 15th August, 1967 and the concerned workmen will be given one increment in the above mentioned scales and thus they will be given starting salary of Rs. 212 per month with effect from the 15th August, 1967 in the afore-said Clerical Grade—II.

4. The difference in wages from the 15th August, 1967 to the date of settlement will be paid to the concerned workmen within one month from the date of publication of the Award of the Tribunal and the above mentioned terms will be made effective as soon as a copy of the Award will be received by the employers.

5. The terms of settlement are fair and reasonable and the same are accepted. Accordingly an award is made in terms of the memorandum of settlement (annexure ‘A’), a copy of which is enclosed with the award.

6. It may now be submitted to the Central Government under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

(Sd.) SACHIDANAND SINHA,  
Presiding Officer.

**BEFORE THE HON’BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 3) AT DHANBAD**

In the matter of

REFERENCE No. 9 OF 1970

**PARTIES :**

Employers in relation to Jealgora Colliery of M/s. East Indian Coal Co.,  
Ltd., P. O. Jealgora, District Dhanbad.

**AND**

**The Workmen.**

Both Parties most respectfully beg to submit as follows:—

(1) That without prejudice to the respective contentions of the parties, the above Reference has been amicably settled on the following terms:—

- (a) That Sarvashree Pashupati Prasad and Jahar Roy, the concerned workmen, will be placed in Clerical Grade II in the Scale of Rs. 205—7—275—10—325 as per recommendations of the Central Wage Board (for Coal Mining Industry) with effect from the 15th August, 1967.
- (b) That the concerned workmen will be given one increment in the above mentioned scale and thus they will be given starting salary of Rs. 212/- (Rupees two hundred and twelve only) per month

with effect from the 15th August, 1967 in the aforesaid Clerical Grade—II.

- (c) That the difference in wages from the 15th August, 1967 to the date of Settlement will be paid to the concerned workmen within one month from the date of publication the Award of the Hon'ble Tribunal and the above-mentioned terms [clause (a) & (b)] will be made effective as soon as a copy of the Award will be received by the Employers above-named.

(2) That the above terms finally resolve the dispute between both the parties concerning the present Reference.

It is, therefore, humbly prayed that this compromise may kindly be recorded and an Award passed in terms thereof.

*For the Workmen:*

- (1) S. DAS GUPTA, Secy.  
Colliery Mazdoor Sangh  
P. O. Dhanbad (Dhanbad).  
(2) PASHUPATI PRASAD,  
Concerned workman.  
Jealgora Colliery.  
(3) JAHAR ROY,  
(Concerned Workman)  
Jealgora Colliery.  
P. O. Jealgora, District, Dhanbad.

*For the Employers:*

- (1) J. N. P. SAHI, Labour Adviser,  
East Indian Coal Co. Ltd.,  
P. O. Jealgora (Dhanbad).  
S. S. MUKHERJEE,  
Executive Committee, Member,  
Ranigunj Chamber of Commerce.

[No. 2/196/69-LR.II.]

Dated the 14th December, 1970.

### ORDERS

New Delhi, the 19th December 1970

**S.O. 170.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Coal Washing Plant Jamadoba of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Jamadoba, Post Office Jealgora, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

### SCHEDULE

"Whether the action of the management of Coal Washing Plant Jamadoba of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Jamadoba, Post Office Jealgora, District Dhanbad in refusing employment to Shri Rajendra Prasad Sinha, Clerk Grade-III, with effect from the 17th June, 1969 is justified? If not to what relief the workman is entitled?"

[No. 2/124/70-LR.II.]

### आदेश

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1970

का० आ० 170.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड, जमदोबा, डाकघर जयलगाड़ा जिला धनबाद के कोल वाशिंग प्लांट जमदोबा से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;



और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं० 2) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

### अनुसूची

"क्या मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, जमदोबा, डाकघर जियलगोड़ा, जिला धनबाद के कोल वार्शिग प्लांट जमदोबा के प्रबन्धतंत्र की श्री राजेन्द्र प्रसाद सिन्हा, लिपिक ग्रेड 3 को 17 जून, 1969 से नियोजित करने से इन्कार, करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० 2/124/70-एल० ग्रा० 2]

S.O. 171.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Dhansar Colliery of Messrs Dhansar Coal Company Limited, Post Office Dhansar, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

### SCHEDULE

"Whether the action of the management of Dhansar Colliery of Messrs Dhansar Coal Company Limited, Post Office Dhansar, District Dhanbad, in terminating the services of Shri Diloo Gope, Line Mistry, with effect from the 19th March, 1970 was justified? If not, to what relief is the workman entitled?

[No. 2/144/70-LRII.]

का० ग्रा० 171.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स धनसर कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर धनसर, जिला धनबाद की धनसर कोयला खान से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं० 2), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

## अनुबन्ध

“क्या मैसर्स धनसर कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर धनसर, जिला धनबाद की धनसर कोयलाखान, के प्रबन्धतंत्र की श्री दिलू गोप, लाइन मिस्त्री की सेवाओं को 19 मार्च, 1970 से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित थी ? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० 2/144/70-एल० प्रार० 2]

**S.O. 172.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Kustore Colliery of Messrs Raneegunge Coal Association Limited, Post Office Kustore, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

## SCHEDULE

1. “Whether the action of the management of Kustore Colliery of Messrs Raneegunge Coal Association Limited, Post Office Kustore, District Dhanbad in terminating the services of the following workmen with effect from the 19th February, 1970 is justified? To what relief, if any, are the said workmen entitled?

S. No.	Name of the workmen	Designation
1.	Shri Bhairo Singh	Tyndel Mazdoor.
2.	Shri Jogeshwar Singh	-do-
3.	Shri Chandradeo Singh	-do-
4.	Shri Bindeswar Singh	-do-
5.	Shri Bhuneswar Singh	-do-
6.	Shri Ram Kallash Singh	-do-
7.	Md. Sultan	-do-
8.	Md. Ismail	-do-
9.	Md. Hanif	-do-
10.	Md. Usman Ali	-do-

2. “Whether the action of the management of Kustore Colliery of Messrs Raneegunge Coal Association Limited, Post Office Kustore, District Dhanbad, in not allowing Shri Misri Harijan, Loader on work with effect from the 19th February, 1970 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?

3. Whether the action of the management of Kustore Colliery of Messrs Raneegunge Coal Association Limited, Post Office Kustore, District Dhanbad, in rendering the following workmen idle for the period mentioned against each is justified? If not, to what relief are the workmen entitled?”

S. No.	Name and Designation	Period of idleness
1.	Shri Ganga Ahir, Trammer.	5.2.1970 to 31.3.1970
2.	Shri Radha Kishun Ahir, Trammer.	5.2.1970 to 3.4.1970

[No. 2/100/70-LRII.]

का० आ० 172.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनि-  
दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स रानीगंज कोल एसोसिएशन लिमिटेड, डाकघर, कुस्तोर, जिला धन-  
बाद की कुस्तोर कोयलाखान के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक  
औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछ-  
नीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की  
उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा  
उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधि-  
करण (सं० 2) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

#### अनुसूची

1. क्या मैसर्स रानीगंज कोल एसोसिएशन लिमिटेड, डाकघर कुस्तोर जिला धनबाद की  
कुस्तोर कोयलाखान के प्रबन्धतंत्र की निम्नलिखित कर्मकारों की सेवाओं को 19 फरवरी, 1970  
से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? उक्त कर्मकार किस अनुतोष के, यदि कोई हो,  
हकदार हैं ?

क्रम सं०	कर्मकार का नाम	पदनाम
1.	श्री भैरों सिंह	टिडल मजदूर
2.	„ जोगेश्वर सिंह	—यथोक्त—
3.	„ चन्द्रदेव सिंह	—यथोक्त—
4.	„ बिन्देश्वर सिंह	—यथोक्त—
5.	„ भुनेश्वर सिंह	—यथोक्त—
6.	„ राम कैलाश सिंह	—यथोक्त—
7.	„ मो० सुलतान	—यथोक्त—
8.	„ मो० इस्माइल	—यथोक्त—
9.	„ मो० हनीफ	—यथोक्त—
10.	„ मो० उस्मान अली	—यथोक्त—

2. क्या मैसर्स रानीगंज कोल एसोसिएशन लिमिटेड, डाकघर कुस्तोर, जिला धनबाद,  
की कुस्तोर कोयलाखान के प्रबन्धतंत्र की श्री मिसरी हरिजन, लोडर, को 19 फरवरी, 1970 से  
काम न देने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

3. क्या मैसर्स रानीगंज कोल एसोसिएशन लिमिटेड, डाकघर कुस्तोर, जिला धनबाद की  
कुस्तोर कोयला खान के प्रबन्धतंत्र की निम्नलिखित कर्मकारों को प्रत्येक के सामने वर्णित काला-  
वधि के लिए बेकार रखने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के  
हकदार है ?

क्रम सं०	नाम और पदनाम	बेकारी की कालावधि
1.	श्री गंगा अहीर, ट्रैमर	5-2-70 से 31-3-70 तक
2.	श्री राधा किशुन अहीर, ट्रैमर	5-2-70 से 3-4-70 तक

**S.O. 173.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Madhuband Colliery of Messrs Oriental Coal Company Limited, Post Office Nudkharkee, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

#### SCHEDULE

“Whether the action of the management of Madhuband Colliery of Messrs Oriental Coal Company Limited, Post Office Nudkharkee, District Dhanbad, in stopping Shri Md. Ismail, Coal Cutting Machine Driver from work with effect from the 7th September, 1969 is justified? If not, to what relief he is entitled?”

[No. 2/129/70-LRII.]

का० आ० 173.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मेसर्स ओरियण्टल कोल कंपनी लिमिटेड, डाकघर नुदखुर्की, जिला धनबाद की मधुबन्द कोयलाखान के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एवम्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं० 2), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

#### अनुसूची

“क्या मेसर्स ओरियण्टल कोल कंपनी लिमिटेड, डाकघर नुदखुर्की, जिला धनबाद को मधुबन्द कोयलाखान के प्रबन्धतंत्र की श्री मौ० इस्माईल, कोयला कर्तन मशीन चालक को 7 सितम्बर, 1969 से काम से रोकने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो वह किसी अनुतोष का हकदार है ?”

[सं० 2/129/70-एस० आर० 2]

**S.O. 174.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bon-Jamihari Colliery, Post Office Salanpur, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

#### SCHEDULE

“Whether the management of Bon-Jamihari Colliery, Post Office Salanpur, District Burdwan was justified in stopping Shri Biswanath Roy, an employee of the colliery from work with effect from the 4th November, 1969? If not, to what relief is the workman entitled?”

[No. 6/34/70-LRII.]

का० प्रा० 174.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बॉन-जमिहारी कोयलाखान, डाकघर सालनपुर जिला वर्दवान के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

#### अनुसूची

“क्या बॉन-जमिहारी कोयला खान, डाकघर सालनपुर जिला वर्दवान के प्रबन्धतंत्र का विश्वनाथ राय, कोयलाखान के कर्मचारी को 4 नवम्बर, 1969 से काम से रोकना न्यायोचित था? यदि नहीं, तो कमकार किस अनुतोष का हकदार है?”

[सं० 6/34/70-एल०आर० 2]

S.O. 175.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Singareni Collieries Company Limited, Post Office Kothagudium Collieries (Andhra Pradesh) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri T. Chandrasekhara Reddy, as Presiding Officer with headquarters at Afzal Lodge, Tilak Road, Ramkote, Hyderabad-1, and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

#### SCHEDULE

“Whether the demand of the union for deletion of Rule 5(2)(i) of Gratuity Rules of the Singareni Collieries Company Limited, Kothagudium is justified? If so, to what relief are the workmen entitled?”

[No. 7/8/70-LRII.]

KARNAIL SINGH, Under Secy.

का० प्रा० 175.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में दी सिंग्रेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, डाकघर कोठगुडियम कोलियरीज (आन्ध्र प्रदेश) के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० चन्द्रशेखर रेड्डी होंगे जिनका मुद्र्यालय अफजल लॉज, तिलक रोड, राम

कौट, हैदराबाद होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

### अनुसूची

“क्या दि सिप्रेती कॉलियरीज कंपनी लिमिटेड, कौठागुडियम के उपदान नियमों के नियम 5(2)(1) को निकाल देने की संघ की मांग न्यायोचित है? यदि हां तो कर्मकार किस अनुवीष के हकदार है?

[सं० 7/8/70-एल० आर० II]

करनैल सिंह, अधिवक्ता (एल) ।

### (Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 31st December 1970

S.O. 176.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the Hongkong and Shanghai Banking Corporation and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd December, 1970.

### CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA.

REFERENCE NO. 45 OF 1970

#### PARTIES:

Employers in relation to the Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Calcutta,

AND

Their workmen.

#### PRESENT:

Mr. B. N. Banerjee—Presiding Officer.

#### APPEARANCES.

On behalf of Employers.—Sri S. Sen, Advocate with Sri S. Sarkar, Advocate.

On behalf of Workmen.—Sri Bankim Chandra Roy, Advocate.

STATE: West Bengal.

INDUSTRY: Banking.

### AWARD

By Order No. 23/85/70-LR-III, dated August 13, 1970, the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), referred the following industrial dispute between the employers in relation to the Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Calcutta, and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely:—

“Whether the action of the management of Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Calcutta-1, in terminating the services of Shri Laxmidhar Pandab, a sub-staff with effect from the 21st April, 1970 is justified? If not, to what relief is he entitled and from what date?”

2. There is no dispute as to the following points, (a) that the concerned workman was a member of the subordinate staff of the Bank and was appointed as such on April 1, 1950; (b) that he went on privilege leave for 16 days with effect from March 24, 1970; (c) that he applied for extension of leave on the ground that his wife was seriously ill with chicken pox and that he was unable to leave her alone and proceed to join his duties; (d) that the application for extension of leave on the ground of his wife's illness was not considered as sufficient reason and his prayer was refused; (e) that he was informed by the Bank that if he did not join his duties on April 16, 1970 his services would be terminated; (f) that he did not

rejoin as directed and thereupon the employer Bank terminated his services and arranged for payment of his dues.

3. The cause of the concerned workman was taken up by a trade Union of the name of Hongkong & Shanghai Banking Corporation (Calcutta Branch) Employees Union. In the written statement filed on behalf of the trade Union, it was pleaded that the termination of service in the aforesaid circumstances was illegal, unjust, arbitrary and without jurisdiction on the grounds, firstly, that over-staying sanctioned leave constituted merely a minor misconduct and the offender deserved to be warned or censured or to have an adverse remark entered against him or to have his increment stopped for a period of not more than six months, under the provisions of Chapter XIX, Paragraph 19.8 of the Settlement arrived at between the Banks' managements and their workmen, on the 19th October, 1966, (hereinafter referred to as the bipartite agreement), secondly, that the procedure prescribed for taking disciplinary action had not been complied with, as required by the bipartite agreement, thirdly, that in view of the infectious nature of the disease of the wife of the workman, the management should have granted an extension of leave to the concerned workman as provided in Chapter XIII, Paragraph 13.41 of the bipartite agreement, fourthly, that the allegation of "previous irregularities" did not entitle the employer Bank to terminate his services, fifthly that the impugned order of termination of service was motivated and was inflicted on the ground that the concerned workman happened to be an active member of a particular trade union and sixthly, that the purported order of termination of service of the workman was made in violation of the principles of natural justice.

4. There was a written statement filed on behalf of the employer Bank. In paragraphs 4 to 20 of the said written statement there was a catalogue of leave applications, applications for extension of leave and over-staying of leave by the workman given in great detail. It was stated in paragraphs 21 and 22 of the said written statement:—

"21. \*\*\*The concerned workman within the period of twenty years service with the Bank has (a) overstayed his leave for not less than 18 times without proper sanction from the Management, (b) warned and censured several times including a warning in 1968 that he will be dismissed if he repeated the offence of unauthorised overstay of sanctioned leave, and (c) repeated the same offence in 1969 and 1970 without paying any heed to the lawful direction of the Management. The above acts are gross misconducts [vide 19.5(e)(f) and 19.6 of the Settlement dated 19th October, 1966.]

22. The Management submits that it had no alternative but to terminate his employment keeping in view the past record of habitual absence and overstay of leave as stated hereinabove and for the gravity of the offence committed regularly by the Workman with scant regard for the rules of discipline and code of conduct coupled with deliberate non-compliance with the lawful and reasonable directions of the Management."

5. It is true that in paragraphs 19.7(a) of the bipartite agreement expression "minor misconduct" covers "absence without leave or over-staying sanctioned leave without sufficient grounds". Paragraph 19.8 of the said agreement is couched in the following language:—

"19.8. An employee found guilty of minor misconduct may:—

- (a) be warned or censured; or
- (b) have an adverse remark entered against him; or
- (c) have his increment stopped for a period not longer than six months."

It appears from the uncontroverted evidence of Mr. Uttley and also from management's exhibits nos. 1 to 45 that in the past the workman seldom returned from leave without over-staying the same, on pretexts more than one, usually on the ground of illness of his family members.

6. According to the pleading of the management, as in paragraphs 21 and 22 of the written statement, the workman was not dismissed for mere absence without leave or over-staying of sanctioned leave without sufficient grounds, as in paragraph 19.7(a) of the bipartite agreement but for gross misconduct under paragraph 19.5(e) and (f) of the said agreement, which are set out below:

"19.5. By the expression "gross misconduct" shall be meant any of the following acts and omissions on the part of an employee:

- (e) wilful insubordination or disobedience of any lawful and reasonable order of the management or of a superior;

- (f) habitual doing of any act which amounts to "minor misconduct" as defined below, "habitual" meaning a course of action taken or persisted in notwithstanding that at least on three previous occasions censure or warnings have been administered or an adverse remark has been entered against him;"

This argument was made on two-fold basis. My attention was invited by the learned Counsel for the management to Ex. 50 which is couched in the following language:

"Please note that the illness of your wife is not considered sufficient reason for you to absent yourself from your duties and your late request for an extension of leave is refused.

As you know you have an appalling record of absence without leave having received 5 adverse remarks already.

It appears that since you are not on duty you no longer wish to retain your employment with us. Accordingly if you are not on duty by 16th April, 1970, your services with Bank will be terminated."

and it was argued that the last paragraph of the said letter referred to gross misconduct under paragraph 19.5(f) of the agreement and the second paragraph drew the mischief of 19.5(e) in case of disobedience. My attention was also invited to Ex.53, the service card of the concerned workman, in which the following remarks appear:

*"Disciplinary action:*

5th July, 1955: Overstayed sanctioned casual leave from 21st June, to 28 June, 1955 without leave or permission. Adverse remarks.

14th May, 1965: Adverse remark—overstayed leave from 15th March 1965 to 13th April, 1965 without leave or permission. He should be severely reprimanded.

14th June, 1966: Adverse remark—overstayed leave from 26th March 1966 to 18th May, 1966 without leave or permission.

1st December, 1966: Charged with overstaying sanctioned leave. Charge for your misconduct dropped, L.W.O.P."

The learned Counsel argued that the conduct of the workman was such as more than sufficiently satisfied the requirements of misconduct under 19.5(e) and (f). Admittedly, the workman did not rejoin by April 16, 1970, inspite of order, rejoined on a later date. As such, it was contended, the workman was guilty of gross misconduct on two grounds, namely, disobedience and repetition of absence without leave, and there was no substance in the point that the workman had committed merely a minor misconduct and should not have been penalised by termination of service. In my opinion, this argument cannot be ignored. The conduct of the workman was such that he was habitually committing the minor misconduct of overstaying of leave without permission and had disobeyed the order to rejoin on a particular date on refusal of his application for extension of leave.

7. I shall deal with the second argument about procedural defect later on in this award.

8. The third argument based on paragraph 13.41 of the bipartite agreement is also misconceived. The said paragraph reads as follows:—

*"Quarantine Leave*

13.41. In case an employee is absent from duty on account of quarantine, the bank, may, at the request of the employee, treat such absence upto a maximum of three months as privilege or sick leave if such leave is otherwise permissible."

The workman was not ill with chicken pox. His wife was. There is no evidence that he also contacted the infection from her. Moreover, the grant of quarantine leave is to the discretion of the Bank and the Bank did not exercise this discretion in favour of the workman. Therefore, the said paragraph has no application to the facts of the instant case and has been uselessly invoked.

9. The fourth argument was that the alleged previous irregularities of the said workman did not entitle the employer Bank to terminate his services. I have already dealt with this. There is a complete answer to this argument contained in paragraph 19.5(f) of the agreement, because the workman had repeated this type



of minor misconduct in spite of warnings, and that was invoked against the workman.

10. The fifth argument advanced on behalf of the workman, namely that the termination of service for overstaying sanctioned leave was made on the ground that he happened to be an active member of a particular trade union is based on very little evidence. The workman in his evidence stated:

*"To Tribunal*

\*\*\*\*There are two trade Unions in the Bank's office. There is rivalry between the two unions.

*Exam. in chief.*

The trade union of which I am a member, is known as Hongkong and Shanghai Banking Corporation Calcutta Branch Employees Union. The other Trade Union is known as Hongkong and Shanghai Banking Corporation Calcutta Branch Indian Staff Union. The first named trade union is a later organised trade union. About 15 members of our trade Union were charged with misconduct. All of them overstayed leave. I can name only four or five of them. I do not remember the names of others. Kumar Nayak of our Union overstayed leave. Proceedings against him are pending. Abdul Rahim Khan also overstayed and he was charged with misconduct."

There is not a word of victimisation for trade union activities in his evidence. I therefore, cannot make much of this argument.

11. I now turn to the second and the sixth arguments advanced on behalf of the workman, namely, that the procedural requirements were not observed and the rules of natural justice were not followed in terminating his services. If I proceed on the premises, as contended for on behalf of the employer Bank, that the services of the workman were terminated under paragraph 19.5(e) and (f) for gross misconduct, and not for minor misconduct of absenteeism as under 19.7(a) of the agreement, then the agreement required observance of the procedure prescribed under paragraphs 19.10, 19.11 and 19.12 which are couched in the following language:—

"19.10. In all cases in which action under clauses 19.4, 19.6 or 19.8 may be taken, the proceedings held shall be entered in a book kept specially for the purpose, in which the date on which the proceedings are held, the name of the employee proceeded against the charge or the evidence, if any, tendered by the said employee, the finding or findings with the grounds on which they are based and the order passed shall be recorded with sufficient fullness, as clearly as possible and such record of the proceedings shall be signed by the officer who holds them, after which a copy of such record shall be furnished to the employee concerned if so requested by him in writing.

19.11. When it is decided to take any disciplinary action against an employee such decision shall be communicated to him within three days thereof.

19.12. The procedure in such cases shall be as follows:—

(a) An employee against whom disciplinary action is proposed or likely to be taken shall be given a charge-sheet clearly setting forth the circumstances appearing against him and a date shall be fixed for enquiry, sufficient time being given to him to enable him to prepare and give his explanation as also to produce any evidence that he may wish to tender in his defence. He shall be permitted to appear before the Officer conducting the enquiry, to cross-examine any witness on whose evidence the charge rests and to examine witness and produce other evidence in his defence. He shall also be permitted to be defended—

(i) (x) by a representative of a registered trade union of bank employees of which he is a member on the date first notified for commencement of the enquiry;

(y) where the employee is not a member of any trade union of bank employees on the aforesaid date, by a representative of a registered trade union of employees of the bank in which he is employed; or

(ii) at the request of the said union by a representative of the state federation or all-India Organisation to which such union is affiliated or

(iii) with the Bank's permission, by a lawyer.

He shall also be given a hearing as regards the nature of the proposed punishment in case any charge is established against him.

(b) \* \* \*

(c) \* \* \*

(d) \* \* \*

(e) An enquiry need not be held if—

(i) the misconduct is such that even if proved the bank does not intend to award the punishment of discharge or dismissal; and

(ii) the bank has issued a show cause notice to the employee advising him of the misconduct and the punishment for which he may be liable for such misconduct; and

(iii) the employee makes a voluntary admission of his guilt in his reply to the aforesaid show cause notice.

However, if the employee concerned requests a hearing regarding the nature of punishment, such a hearing shall be given."

Also, it is now well known, that the rules of natural justice must be observed in every domestic enquiry. The principle of natural justice, in its journey through the century, has shed much of its glories and is now crystalised into four principles of justice, namely:

(i) opportunity for both contesting parties to be heard;

(ii) hearing before an impartial Tribunal so that no man can be a judge of his own case;

(iii) decision made in good faith; and

(iv) orderly course of procedure.

Apart from this no other principle of natural justice is known in modern jurisprudence. In the instant case, admittedly there was no enquiry held. Michael John Uttley, the sole witness for the management, in answer to a question put by the Tribunal, said:

"The workman was not charged in writing for absenteeism or for having wilfully disobeying the order to rejoin on a particular date. There was no enquiry held into his misconduct. After the workman had come back he was not given any opportunity to explain his misconduct."

Thus, in taking action against the workman for gross misconduct on two counts, the management violated the procedural requirements and the rules of natural justice.

12. The learned Counsel for the management attempted to get rid of this difficulty with the argument that no penal measure was taken against the workman. He was not dismissed or discharged but merely his services were terminated. In my opinion, this argument has no substance. Action was being taken against the workman for blameworthiness. That abundantly appears from Ex. 50 (which I have already hereinbefore set out) and Ex. 52 which I now set out below:—

"We are in receipt of your letter dated 15th April, 1970, and regret to note that your wife is again affected with pox.

You have no further leave due and were directed to report on 16th April, 1970, and failure to report would result in termination of your employment.

As you are aware, you have been warned on a number of occasions not to overstay leave.

In the circumstances we have no alternative but to terminate your services from the date of this letter.

We are arranging to pay your dues to your address given above."

Thus, although the management might have inflicted the same penalty on the workman on the same charge, their present action should not be sustained because in

taking the action they violated the requirements of procedure and also the rules of natural justice. Merely on this ground, the action of the management against the concerned workman can be held to be unjustified.

13. In the view that I take, I hold that the action of the management of Hong-kong and Shanghai Banking Corporation, Calcutta-1, in terminating the service of Laxmidhar Pandab, a sub-staff with effect from the 21st April, 1970 is not justified. I am now left with the question of what relief is the workman entitled to.

14. The Supreme Court has now restated the law about the powers of the Tribunal concerning dismissal of a workman and the relief of the workman against wrongful dismissal, in the case of *Hindustan Steels, Ltd., Rourkela vs. A. K. Roy*, (1970) 1 L.L.J. 228 (Shelat J. speaking for the Court). The Supreme Court observed that right of an employer to discharge and dismiss an employee was no longer absolute. In cases of both termination of service and dismissal, industrial adjudication was competent to grant relief, in the former case on the ground that exercise of powers was *mala fide* or colourable, in the latter case, if it amounted to victimisation or unfair labour practice or in violation of the principles of natural justice or otherwise not legal or justified. In such cases, a tribunal was held competent, by way of relief to the concerned employee either to reinstate or to pay compensation. In earlier cases, the question whether one or other of the two reliefs should be granted was held to be a matter of discretion of the tribunal, for example, in the case of *United Commercial Bank Limited vs. U.P. Bank Employees Union & Others* (1952) II L.L.J. 577. The view then was that to lay down a general rule of reinstatement being the remedy in such cases would itself fetter the discretion of the tribunal which has to act in the interests of industrial harmony and peace and that it might well be that in some cases imposition of the service of a workman on an unwilling employer might not be conducive to such harmony and peace. Later on, however, the earlier flexibility appears to have been abandoned and it was ruled that although no hard and fast rule could be laid down and the tribunal would have to consider each case on its own merits and attempt to reconcile the conflicting interests of the employer and employee, the employee being entitled to security of service and protection against wrongful dismissal, the normal rule in such cases should be reinstatement, for example, in the case of *Punjab National Bank Ltd. v. their workmen* (1959) II L.L.J. 666, but the case of *Punjab National Bank* (supra), the rule was qualified to mean that in unusual or exceptional cases where it is not expedient to grant the normal relief of reinstatement, the proper relief would be compensation and that would meet the ends of justice. As exception to the general rule of reinstatement, there has been cases where reinstatement has not been considered as either desirable or expedient. In that context the Supreme Court observed:

"These were the cases where there had been *strained relations* between the employer and the employee, where the post held by the aggrieved employee had been one of *trust and confidence* or were, though dismissal or discharge was unsustainable owing to some infirmity in the impugned order, the employee was found to have been guilty of an *activity subversive of or prejudicial to the interests of the industry*. These cases are to be found in *Assam Oil Company, Ltd. v. its workmen* (1960-I LLJ 587), *Workmen of Charottar Gramodhar Sahakari Mandali, Ltd. v. Charottar Gramodhar Sahakari Mandali, Ltd.*, (Civil Appeal No. 382 of 1966, decided on 14 August, 1967), *Doomur Duling Tea Estate v. its workmen* (Civil Appeal No. 516 of 1966, decided on 26th October, 1967) and *Ruby General Insurance Company, Ltd. v. P. P. Chopra* (1970-I L.L.J. 63). These are, however, illustrative cases where an exception was made to the general rule. No hard and fast rule as to which circumstances would in a given case constitute an exception to the general rule can possibly be laid down as the tribunal in each case, keeping the objectives of industrial adjudication in mind, must in a spirit of fairness and justice confront the question whether the circumstances of the case require that an exception should be made and compensation would meet the ends of justice." (Underlined by me).

In the instant case, I am bearing in mind the discretion given by the Supreme Court that no hard and fast rule should be laid down. I am directing reinstatement of the workman for the present, because his case does not appear to fall within the exceptions contemplated by the Supreme Court, with liberty to the management to start a disciplinary action against the workman on the same cause of action, if desired, to follow the prescribed procedure and the rules of natural justice and then take such action against the workman as may be merited. I am

making this order because I believe the workman may otherwise be an undesirable employee regard being had to his past record of service. About that I do not, however, express any opinion. Nevertheless, his dismissal was high-handed. I, therefore, propose to give him an opportunity to defend himself. This disciplinary action must be started within three months of the publication of this award. If they do not do so, the order of reinstatement shall become final. I do not make any order for back wages, because I do not know whether the workman remained unemployed all through the period of his enforced unemployment.

This is my award.

Dated, December 15th, 1970.

(Sd.) B. N. BANERJEE,  
Presiding Officer.  
[File No. 23/85/70-LR.III.]

### ORDERS

New Delhi, the 15th December 1970

**S.O. 177.**—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Cantonment Board, Delhi Cantonment and their workmen represented by the Rashtriya Karamchari Sangh, Delhi Cantonment;

And, whereas the said employers and workmen have by a written agreement, in pursuance of the provisions of Sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration by the person mentioned therein, and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of the section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 16th November, 1970.

#### Agreement

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)

#### BETWEEN

#### NAME OF PARTIES:

*Representing Employers.*—Shri V. K. Budhraja, Cantonment Executive Officer, Delhi Cantt.

*Representing Workmen.*—Shri Sukhdev Sharma, General Secretary, Cantt. Board Rashtriya Karamchari Sangh, 2, Gopinath Building, Delhi Cantt.

It is hereby agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of Shri V. P. Gupta, Regional Labour Commissioner (C), Kanpur.

- (i) *Specific matters in dispute.*—"Whether the management of Cantonment Board, Delhi Cantt is justified in not changing the date of birth of Shri Ganesha, Sweeper, in their records from 30th June, 1910 to 9th February, 1928. If not to what relief is the workman entitled?
- (ii) *Details of parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.*—(a) The Cantonment Executive Officer, Cantt Board Delhi Cantt.....management.
- (b) General Secretary, Cantonment Board Rashtriya Karamchari Sangh, 2, Gopinath Building, Delhi Cantt.
- (iii) *Name of the Union, if any, representing the workmen in question.*—Cantonment Board Rashtriya Karamchari Sangh 2 Gopinath Building, Delhi Cantt.
- (iv) *Total number of workmen employed in the undertaking effected.*—470.
- (v) *Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute.*—One.

We further agree that the majority decisions of the arbitrator shall be binding on us.

The arbitrator shall make his award within a period of two months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Representing employer:

(Sd.) V. K. BUDHRAJA,  
Cantt. Executive Officer,  
Delhi Cantt.

Representing workmen:

(Sd.) SUKHDEV SHARMA,  
General Secretary, Cantt. Board,  
Rashtriya Karamchhari Sangh, 2,  
Gopinath Building, Delhi Cantt.

Witnesses:

1. (Sd.) V. P. BHARGAVA,  
Steno to Asstt. Labour Commissioner (C), Delhi.

2. (Sd.) LEKH RAM,  
L.D.C. Office of L.E.O. (C) Delhi-1.

[No. 41/9/70-LRI.]

(श्रः और रोजगार विभाग)

आवश

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1970

का० प्रा० 177—यतः छावनी बोर्ड, दिल्ली छावनी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों, जिनका प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय कर्मचारी संघ, दिल्ली छावनी करता है, के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को जो उसे 16 नवम्बर, 1970 को प्राप्त हुआ था, एतद्वारा प्रकाशित करती है ।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन निम्नलिखित के बीच

पक्षकारों के नाम :

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले :

श्री १० के० बुद्धराजा, छावनी कार्यपालक  
अधिकारी, दिल्ली छावनी ।

कर्मका ों का प्रतिनिधित्व करने वाले :

श्री सुखदेव शर्मा,  
महासचिव,  
छावनी बोर्ड राष्ट्रीय कर्मचारी संघ,  
2, गोपीनाथ बिल्डिंग,  
दिल्ली छावनी ।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित विवाद को एतद्वारा श्री बी० पी० गुप्त, प्रादेशिक श्रम आयुक्त (सी), कानपुर के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है ।

(i) विनिर्दिष्ट विवादप्रस्त विषय :

“क्या छावनी बोर्ड, दिल्ली छावनी के प्रबन्धतंत्र का अपने अभिलेख में श्री गणेश, झाड़कश के जन्म की तारीख को 30-6-1910 से 9-2-1928 में परिवर्तित न करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

(ii) विवाद के पक्षकारों का विवरण जिसमें अन्तर्जित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है ।

(क) छावनी कार्यपालक अधिकारी, छावनी बोर्ड, दिल्ली छावनी .....  
प्रबन्धतंत्र

(ख) महासचिव, छावनी बोर्ड राष्ट्रीय कर्मचारी संघ, 2 गोपीनाथ बिल्डिंग,  
दिल्ली छावनी ।

(iii) यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम :  
छावनी बोर्ड राष्ट्रीय कर्मचारी संघ, 2 गोपीनाथ बिल्डिंग, दिल्ली छावनी ।

(iv) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या ।

470

(v) विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या :

एक

हम यह करार भी करते हैं कि माध्यस्थ को बहुमत विनिश्चय हम पर बाबद्ध कर होंगे ।

माध्यस्थ अपना पंचाट दो मास की कालावधि के भीतर या इतने और समय के भीतर, जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाए देगा । यदि ऊपर वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम् के लिए निर्देश स्वतः रद्द हो जाएगा और हम नए माध्यस्थम् के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे :

नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले :

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले :

(ह०) बी० के० बुद्ध राजा,

छावनी कार्यपालक अधिकारी,  
दिल्ली छावनी ।

(ह०) सुखदेव शर्मा, महासचिव,  
छावनी बोर्ड राष्ट्रीय कर्मचारी संघ,  
2, गोपीनाथ बिल्डिंग,  
दिल्ली छावनी ।

सांख्यिकी ---

(ह०) वी० पी० भागवत,  
ग्रामालिपिक,  
सहायक श्रम आयुक्त (सी)  
दिल्ली

(ह०) लेख राम,  
निम्नश्रेणी लिपिक  
एल० ई० ओ० (सी)  
दिल्ली—1 का कार्यालय  
एस० एस० सहस्त्रनामन,

[संख्या 41/9/70-एल-प्रार I]

*New Delhi, the 24th December 1970*

**S.O. 178.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to Martin's Howrah-Amta and Howrah-Siakhala Light Railways Company Limited and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Calcutta constituted under section 7A of the said Act.

#### SCHEDULE

"Whether the management of the Martin's Howrah-Amta and Howrah-Siakhala Light Railways Company Limited, Calcutta was justified—

- (i) in not paying the annual bonus usually paid to their employees before Puja;
- (ii) in terminating the services of Shri Sukumar Chatterjee, Pointsman with effect from the 12th May, 1970 and that of Shri Provakar Mukherjee, Khalasi (Electric) with effect from the 5th March, 1970;
- (iii) in stopping the increment for 2 years with effect from the 10th June 1969 of Shri Ram Chandra Chatterjee, Train Lighter;
- (iv) in not supplying the uniforms, waterproof, umbrellas to the concerned workers as per service regulations for the year 1970?

If not, to what relief are the workmen entitled?"

[No. 2/37/70/LRIL]

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1970

का० आ० 178—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मार्टिन्स हावड़ा-आम्ता एंड हावड़ा-शिरवाला लाइट रेलवेज कम्पनी लिमिटेड से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये मिदशित करना बांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

### अनुसूची

“क्या मार्टिन्स हावड़ा-अमता और हावड़ा-शिवखला लाइट रेलवेज कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्धतंत्र का —

- (i) प्रायः पूजा से पूर्व उनके कर्मचारियों को संदस्त किये जाने वाले वार्षिक बोनस का संदाय न करना ;
- (ii) श्री सुकुमार चटर्जी, कांटेवाला की सेवाओं को 12 मई, 1970 से और श्री प्रोवाकर मुखर्जी, खलासी (विद्युत्) की सेवाओं को 5 मार्च, 1970 से समाप्त करना ;
- (iii) श्री रामचन्द्र चटर्जी, ट्रेन-लाइटर की वेतन-वृद्धि 10 जून, 1969 से 2 वर्ष के लिये रोकना ;
- (iv) संबंधित कर्मकारों को सेवा विनियमों के अनुसार 1970 के वर्ष के लिये वदियां, बरसाती, छुाते न देना ,

न्यायोचित था ?

यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?”

[सं० 2/37/70/एल० अर० 3]

**S.O. 179.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Management of the State Bank of India, and Shri A. R. Bhatt, a workman of the bank in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay constituted under Section 7A of the said Act.

### SCHEDULE

“Whether the action of the management of State Bank of India, Bhadra, Ahmedabad was justified in terminating the services of Shri A. R. Bhatt, Clerk-of-works, with effect from the 7th December, 1968? If not, to what relief is he entitled?”

[No. 23/8/69/LR.III.]

का० अा० 179.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि उससे उभावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र से संबंध नियोजकों और बैंक के एक कर्मकार श्री ए० अर० भट्ट के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना बांछनीय समझती है :



अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा-7 क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं 2, मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

### अनुसूची

क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया, भद्रा, अहमदाबाद के प्रबंधतंत्र की श्री ए० आर० भट्ट, क्लर्क आफ वर्कस की सेवाओं को 7 दिसम्बर, 1968 से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित थी? यदि नहीं तो वह किस अनुतोष का हकदार है?

[सं० 23/8/69-एल आर 3]

एस० एस० सहस्रनामन, अव्वर सचिव।

### CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd December 1970

**S.O. 130 :-** In the notification of the Government of India, Ministry of Labour Employment and Rehabilitation (Department of Labour & Employment) S.O. 3272, dated the 3rd October, 1970 published in Part II Section 3 sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary dated the 3rd October, 1970, the following corrections be made :—

Page No.	For	Read
1556 7th line	AINIEF	AINLIEP
1556 15th line	52; 53; 55; 56; 57; 58.	52, 53, 55, 56, 57, 58,
1557 33rd line	pay-scales	pay-scale
1557 37th line	pay-scales	pay-scale
1558 16th line		Insert the word 'arrived' between the words 'having' and 'at'.
1558 21st line	Reference	References
1558 30th line	References	References
1558 44th line		Insert comma between the words 'Stenographer' and 'that'
1559 In the Table under the column "Category"	Section Head	Section Heads
1559 16th line	(b) All other parties summoned to appear in the proceedings as parties	(a) all parties to the industrial dispute
1560 22nd line	assignees	assigns
1560 51st line	ALIEA	ALIEA
1561 59th line	Stenographers	stenographers'
1562 59th line		Add comma after the word and figures '15 May, 1970'
1563 60th line	It	it
1564 63rd line	application	Add full-stop after the word 'AINLIEP'
1564 17th line	signed	application
1564 42nd line	has	signed
1565 57th line	agreements	had
1565 9th line	additional	agreements
1565 11th line	reason	addition
1565 41st line	has	reason
1565 42nd line	contained	had
1565 46th line	has	contended
1565 50th line	Tribunal	had
1566 23rd line		Tribunals
1566 27th line		Add the word 'made' between the words 'were' and 'in'
1567 14th line	it'	it"
1567 16th line	or	of
1567 26th line	AIRDIEP	AINLIEP

Page No.	For	Read
1568 34th line	made	make
1569 34th line	beter	better
1570 24th line	to	the
43rd line	undertaken	undertaken
49th line	H.G.A.S.	H.G.A.s
1571 39th line (not 1517)	p.m.	p.m.
33rd line	Section heads	Section Heads
35th line		Insert comma between the words 'st' and 'fixation'.
52nd line	gains aid	gainsaid
1573 11th line	that	what

[No. 40/36/70-LR. I]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

## (Department of Labour and Employment)

## ORDER

New Delhi, the 28th December 1970

**S.O. 181.**—Whereas an industrial dispute exists between the management of Associated Cement Companies Limited, Jamul Cement Works Lime Stone Quarries, Jamul Cement Works, District Durg (M.P.) (hereinafter referred to as the said Company) and their workmen represented by the President and the General Secretary, Cement Labour Union, Care of Bhilai Steel Kamgar Sangh, Camp No. 2, Bazar, Bhilai-1, District Durg (M.P.) (hereinafter referred to as the Union).

And whereas the said company and the Union have, by a written agreement, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) agreed to refer the said dispute to arbitration of the persons mentioned therein and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government;

Now therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 11th December, 1970.

## AGREEMENT

(Under Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947)

## Between

## Names of the Parties:

**Representing Employer.**—(1) Mr. J. H. Utamsingh, Agent, Jamul Cement works Limestone Quarries, P.O. Jamul Cement Works, Distt. Durg (M.P.) S.E. Rly.

**Representing Workmen.**—(1) Mr. A. B. Farooqui, President, Cement Labour Union.

(2) Mr. Deosaran Dubey, General Secretary, Cement Labour Union, C/o Bhilai Steel Kamgar Sangh, Camp No. 2 Bazar, Bhilai-1 Dist. Durg (M.P.).

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri N. G. Shelat, Retired Justice of Gujarat High Court, presently residing at 22 Nyaya Saurabh Society, Behind University Hostel, Nem Nagar Road, Ahmedabad 9:

- (i) **Specific matter in dispute.**—"Whether the dismissal of Shri Ram Kumar Verma, Heavy Equipment Operator, from the Company's service with effect from 25th July 1967 is legal and justified. If not, to what relief the workman is entitled."
- (ii) **Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.**—(A) The Associated Cement Companies Limited, Jamul Cement Works Limestone Quarries, P.O. Jamul Cement Works, Dist: Durg (M.P.).

- (B) Workmen of the Jamul Cement Works Limestone Quarries as represented by the Cement Labour Union, P.O. Bhilai—1 Dist: Durg (M.P.).
- (iii) Name of the workman in case he himself is involved in the dispute or the name of the Union, if any, representing the workman or workmen in question.—Cement Labour Union, C/o Bhilai Steel Kamgar Sangh, Camp No. 2 Bazar, Bhilai—1, Dist: Durg (M.P.) S.E. Rly.
- (iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected.—140.
- (v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute.—1(One).

The Arbitrator shall make his Award within a period of six months from the date of publication of his agreement in the Official Gazette or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the Award is not made within the period aforementioned, the reference to the arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

**Representing workmen:**  
(Sd.) DEO SHARAN DUBEY,  
18/11/70.  
General Secretary,  
C/o Bhilai Steel Kamgar Sangh,  
Camp No. 2 Bazar, Bhilai—1,  
Distt. Durg (M.P.).

**Signature of the parties:**  
Representing employer  
for the Associated Cement Cos. Ltd.  
(Sd.) J. H. UTAMSINGH,  
Agent,  
Jamul Cement Works Limestone Quarries,  
P.O. Jamul Cement Works,  
Dist: Durg (M.P.).

**Witnesses:**  
1. (Sd.) S. L. GUPTA,  
2. (Sd.) T. SAMUEL.

**Witnesses:**  
1. (Sd.) R. R. SINGH.  
2. (Sd.) H. A. C. POPPEN.

I consent to act as Arbitrator.  
(Sd.) N. G. SHELAT.  
2-12-70.

[No. 12(39)/70-LRIV.].  
P. C. MISRA, Deputy Secy.

(अथ श्रीर रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1970

का० आ० 181—यतः एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, जामुल सीमेंट वर्क्स लाइमस्टोन स्टोन क्वैरीज, जामुल सीमेंट वर्क्स, जिला दुर्ग (मध्य प्रदेश) (इसके बाद उक्त कम्पनी से कहा गया है) के प्रबन्धतन्त्र और उनके कर्मचारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व अध्याक्ष और प्रधान सचिव, सीमेंट लेबर यूनियन, मार्फत भिलाई स्टील कामगार संघ, कैम्प नं० 2, बाजार, भिलाई-1, जिला दुर्ग मध्य प्रदेश (इसके बाद यूनियन के नाम से कहा गया है) करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः उक्त कम्पनी और यूनियन ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थत्व के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थत्व करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क को उप-धारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार को, जो उसे 11 दिसम्बर 1970 को मिला था, एतद्वारा प्रकाशित करती है !

### प्ररूप ण

(नियम 7 ढखें)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

### करार

पक्षकारों के नाम :

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने ढालः--

1. श्री जे० एष० उत्तमसिंह, एजेंट, जामुल सीमेंट वर्क्स लाहम-स्टोन क्वैरीज, डाकघर जामुल सीमेंट वर्क्स, जिला दुर्ग (मध्य प्रदेश) दक्षिण पूर्वी रेलवे ।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने ढालः--

1. श्री ए० आर० फरुकी, अध्यक्ष, सीमेंट लेबर यूनियन ।
2. श्री देवसरन दूब, प्रधान सचिव, सीमेंट लेबर यूनियन माफ्तं भिलाई स्टील कामगार संघ, कैम्प न० 2, बाजार, भिलाई-1 जिला दुर्ग (मध्य प्रदेश)

पक्षकारों क बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री एन० जी० रोलट, गुजरात उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, जो इस समय 22 न्याय सौरभ सोंसायटी, विश्वविद्यालय होस्टेल के पीछे, मीम नगर रोड, अहमदाबाद-9 में रहते हैं, के मध्यस्थम के लिए एतद्वारा निर्देशित करने का करार किया गया है ।

1. विनिर्दिष्ट विवाद प्रस्त विषयः--

“क्या श्री राम कुमार वर्मा, भारी उपस्कर आपरेटर की 25 जुलाई, 1967 से कम्पनी की सेवा के पदच्युति ढैध और न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?”

2. विवाद के पक्षकारों का विवरण  
जिनमें अंतर्बलित स्थापन या उपकरण का नाव  
और पता भी सम्मिलित हं :--

(क) दि एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड  
जामुल सीमेंट वर्क्स लाहम स्टोन क्वैरीज,  
जिला दुर्ग (मध्य प्रदेश) । (ख) जामुल सीमेंट  
वर्क्स लाहम स्टोन क्वैरीज के कर्मकार,  
जिनका प्रतिनिधित्व सीमेंट लेबर यूनियन,  
डाकघर भिलाई-1, जिला दुर्ग (मध्य प्रदेश)  
करती है ।

3. कर्मकार का नाव यदि वह स्वयं  
विवाद में अंतर्बलित हो या यदि कोई संघ प्रश्न-  
गत कर्मकार या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता  
हो तो उसका नाम :--

सीमेंट लेबर यूनियन, माफ्तं भिलाई स्टील कामगार  
संघ कैम्प नं० 2 बाजार, भिलाई-1, जिला  
दुर्ग (मध्य प्रदेश), दक्षिण-पूर्वी रेलवे ।

4. प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्म-  
कारों की कुल संख्या:—146

5. विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भावित:  
प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्रावकलित  
संख्या:—1 (एक)

माध्यस्थ श्रपना पंचाट इस करार के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से छः मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाये, वेगा । यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम के लिए निदेश स्तवः रद्द हो जायेगा और हम नये माध्यस्थम के लिए बातचीत करने को स्वतन्त्र होंगे ।

### पक्षकारों के हस्ताक्षर

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले:—

(ह०)— देव सरन दुबे, प्रधान सचिव, सीमेंट लेबर  
यूनियन, मापत भिलाई स्टील कामगार संघ,  
भिलाई-1, जिला दुर्ग (मध्य प्रदेश)

साक्षी:—

1. (ह०)

2. (ह०)

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले हुते  
एल्लोसियेटिड सोमट कम्पनीज लिमिटेड:—

(ह०) जे० एच० उत्तमसिंह एजेंट, जामुल  
सीमेंट वर्क्स लाइम स्टोन क्वैरीज, डाकघर  
जामुल सीमेंट वर्क्स, जिला दुर्ग (मध्य प्रदेश)

साक्षी:—

1. (ह०)

2. (ह०)

[संख्या 12(39)/70-एल० आर० 4]

पी० सी० मिश्र, उप सचिव

### (Department of Labour and Employment)

#### ORDER

New Delhi, the 30th December 1970

**S.O. 182.**—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to Messrs Padav Bazar Association, Bombay representing 27 members of the Association, Bombay and their workmen represented by the New National Dock Workers' Union, Bombay;

And whereas, the said employers and their workmen have, by a written agreement under sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government, under sub-section (3) of section 10A of the said Act, a copy of the said arbitration agreement;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement.

**AGREEMENT UNDER SECTION 10A OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947**

#### Names of Parties:

**Representing the Employers.**—1. Shri N. B. Sethna, President Padav Bazar Association, Hatim Manzil, Carnac Bunder, Bombay—1.

2. The employers as per annexure—A.

**Representing the workmen.**—3. The New National Dock Workers' Union, 38, Sagar Bihar, 89, P. D'Mello Road, Bombay-9.

It is hereby agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of Shri S. C. Seth of M/s. Eastern Bunkers Ltd., Bombay—1.

- (i) *Specific matter in Dispute.*—1. "Whether the demand made by the New National Dock Workers Union, 35, Sagar Bihari, 89, P. D'Mellow Road, Bombay-9 on the barge/padav employers at Bombay Port & Docks that they should implement the recommendations of the Central Wage Board for Port and Dock Workers as accepted by the Government of India in respect of their employees is justified? If so to what relief are the workmen entitled."
2. "Whether the demands made by the New National Dock Workers' Union, 35, Sagar Vihar, 89, P. D'Mellow Road, Bombay-9 on behalf of the Padav/barge employees in respect of (1) Grant of 30 days earned leave, 15 days casual leave and 15 days sick leave, (2) issue of dock entry pass irrespective of whether barge/padav employee is permanent or temporary, (3) 8 hours work per day and wages at double the normal rate of wages for work beyond 8 hours per day, (4) paid weekly holiday, and (5) all temporary employees who have put in 240 days or more should be made permanent, are justified? If so to what relief are the workmen entitled".
- (ii) *Details of the parties to the dispute including the name and addresses of the establishment or undertakings involved.*—(a) Shri N. B. Sethna, President, Padav Bazar Association, Hatim Manzil, Carnac Bunder, Bombay-1, as representing the employer members of the Association.
- (b) The General Secretary, New National Dock Workers' Union, 35, Sagar Vihar, 89, P. D'Mellow Road, Bombay-9.
- (iii) *Name of the Union, if any, representing the workers in question.*—The New National Dock Workers' Union, Bombay.
- (iv) *Total number of workmen employed in the undertaking affected.*—About 800.
- (v) *Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute.*—About 800.

We further agree that the decision of the arbitrator shall be binding on us.

The arbitrator shall make his award within a period of 90 (ninety) days or within such time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

*Witnesses*

1. (Sd) ABDUL AZIZ ABDULLATIF
2. (Sd) D.S. BAJPAI

*Signature of the Parties.*

1. (Sd) N.B. SETHANA
2. (Sd) K.M. RAO

I consent to act as Arbitrator in this industrial dispute.

Bombay, 19-11-70

(Sd) S.C. SETH

**ANNEXURE—A**

*Members who have authorised the Padav Bazar Association to sign the Arbitration Agreement on their behalf.*

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1 M/s. N. R. Nazir & Sons          | Stock Exchange Bldg., Hamam Street, Fort, Bombay—1.                  |
| 2 M/s. Noorbhai Gallabhai Khanbhai | 19, Karwar Street, Fort, Bombay—1                                    |
| 3 M/s. Kathiawar & Malabar         | Coasts Lighterage Co., Boat Hard Road, Dharukhana, Bombay—10.        |
| 4 M/s. B. K. Salawala              | Nav Jiwan Bldg., Near Marathi Mandir, Bombay Central, Bombay.        |
| 5 Smt. E.C. Gallabhai              | 19, Karwar Street, Fort, Bombay—1.                                   |
| 6 M/s. H.H. Ismail                 | Timber Merchant, Boat Hard Road, Dharukhana, Bombay—10.              |
| 7 M/s. N.A. Peerbhai               | Ebrahim Mansion, Dongri, Bombay.                                     |
| 8 M/s. Mahadeo Lahu Patel          | C/o Padav Bazar Association, Sai Niwas, P. D' Mellow Road, Bombay—1. |
| 9 M/s. Esco Hawa                   | C/o Padav Bazar Association, Sai Niwas, P. D' Mellow Road, Bombay—1. |
| 10 M/s. Rama Maruthi               | C/o Padav Bazar Association, Sai Niwas, P. D' Mellow Road, Bombay—1. |

11	M/s. S.K. More & Sons . . . . .	Amir Bldg., Opp. Noorbaugh, Bombay—9.
12	M/s. A.B. Patel . . . . .	No. 759, Parsi Colony Road, No. 7, Dadar, Bombay.
13	M/s. Ganpat Sadashiv . . . . .	C/o Padav Bazar Association, Sai Niwas, P. D. Mellow Road, Bombay—I.
14	M/s. Dalvi Brothers . . . . .	C/o Nav Bharat Timber Co., Boat Hard Road, Dharukhana, Bombay—10
15	M/s. Fairdeal Lighterage . . . . .	C/o Nav Bharat Timber Company, Boat Hard Dharukhana, Bombay—10.
16	M/s. The Indian Lighterage Co. . . . .	C/o Nav Bharat Timber Co., Boat Hard Road, Dharukhana, Bombay—10.
17	M/s. D. S. Bajpai . . . . .	Khatija Manzil, Hathibaug Lane, Mazgaon, Bombay—10.
18	M/s. Kaluram Pandurang . . . . .	C/o Padav Bazar Association, Sai Niwas P. D Mellow. Road, Bombay—I.
19	M/s. Namdeo Rajaram . . . . .	C/o Padav Bazar Association, Sai Niwas, P.D'Mellow Road, Bombay—I.
20	M/s. Dasrath Ganpat Patil . . . . .	Do.
21	M/s. T. V. Mayekar . . . . .	Do.
22	M/s. Narayan Gangaram . . . . .	Do.
23	Smt. Bombat . . . . .	Do.
24	M/s. N. M. Gandhi . . . . .	788, Parsi Colony, Dadar Bombay—14.
25	M/s. Potia Trading Co. . . . .	Quay Street, Dharukhana, Bombay—10.
26	M/s. Shah & Ferwadi . . . . .	C/o Nav Bharat Timber Co., Boat Hard Road, Dharukhana, Bombay—10.
27	M/s. Gangaram Shivram . . . . .	C/o Padav Bazar Association, Sai Niwas, P.D' Mellow Road, Bombay—I.

[No. 78/5/70-P&D]

(Sd) AZIT CHANDRA, Under Secy.

### (अभ और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1970

एस० ओ० 182:—यतः मैसर्स पडाव बाजार एसोसिएशन, मुम्बई, जो एसोसिएशन के 27 नियोजक सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों, जिनका प्रतिनिधित्व न्यू नेशनल डॉक वर्कर्स यूनियन, मुम्बई करती है, के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः उक्त नियोजकों और उनके कर्मचारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के अधीन लिखित करारद्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार को भेजी है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को, एतद्वारा प्रकाशित करती है ।

### औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन करार

#### बसकारों के नाम

1. श्री एन० बी० सेठना,  
अध्यक्ष, पडाव बाजार एसोसिएशन,  
हातिम मंजिल, कारनाक बन्दर,  
मुम्बई — 1
2. उपाध्यक्ष-क के अनुसार नियोजक

} नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले

- |  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| <p>3. दि न्यू नेशनल डॉक वर्कर्स<br/>यूनियन, 35, सागर बिहार,<br/>89, पी० डी० मैलो रोड,<br/>मुम्बई—9</p> | } | कर्मकार का प्रतिनिधित्व करने वाले |
|--|---|-----------------------------------|

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को एतद्वारा मेसर्स ईस्टर्न बकरर्स लिमिटेड, मुम्बई 1, के श्री एस० सी० सेठ के माध्यस्थत्व के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है ।

(i) विनिश्चित विवादप्रस्त विषय:—

1. “क्या न्यू नेशनल डॉक वर्कर्स यूनियन, 35, सागर बिहार, 89, पी० डी० मैलो रोड, मुम्बई—9 द्वारा मुम्बई पत्तन और डॉकों पर बैरेंज/पड़ाव नियोजकों से की गई यह मांग न्यायोचित है कि उन्हें केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की पत्तन और डॉक कर्मकारों के लिए की गई सिफारिशों को जिस रूप में वे भारत सरकार द्वारा उनके कर्मचारियों की बाबत प्रतिगृहित की गई हैं, कार्यान्वित करनी चाहिए ? यदि हां तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?”
2. क्या न्यू नेशनल डॉक वर्कर्स यूनियन, 35, सागर बिहार, 89, पी० डी० मैलो रोड, मुम्बई—9 की पड़ाव/बैरेंज कर्मचारियों की ओर से (1) 30 दिन की उपाजित छुट्टी, 15 दिन की आकस्मिक छुट्टी और 15 दिन की बिमारी की छुट्टी मंजूर करने; (2) इस बान का ध्यान किए बिना कि बैरेंज/पड़ाव कर्मचारी स्थायी है या अस्थायी डॉक प्रवेश-पत्र जारी करने; (3) प्रति दिन 8 घंटे काम और 8 घंटे प्रति दिन से अधिक काम के लिए मजदूरी की प्रतापान्ध दर से दुगुनी मजदूरी; (4) संदाय सहित साप्ताहिक अवकाश और (5) सभी अस्थायी कर्मचारियों को, जिन्होंने 240 दिन या अधिक सेवा करली है, स्थायी करने की बाबत मांगें न्यायोचित हैं यदि हां तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?”

(ii) विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अन्तर्बलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है

- (क) श्री एन० बी० सेठना, अध्यक्ष, पड़ाव बाजार एसोसिएशन, हातिम मंजिल, कारनाक बन्दर, मुम्बई—1 जो एसोसिएशन के नियोजक सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं ।
- (ख) महासचिव, न्यू नेशनल डॉक वर्कर्स यूनियन, 35, सागर बिहार, 89, पी० डी० मैलो रोड, मुम्बई—9 ।

संघ प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम—दि न्यू नेशनल डॉक वर्कर्स यूनियन मुम्बई —1

- (4) प्रभावित उपक्रम में नियोजत कर्मकारों की कुल संख्या—लगभग 800
- (5) विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या—लगभग 800

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्ध कर होगा ।

मध्यस्थ अपना पंचाट 90 (नब्बे) दिा की कालावधि के भीतर या इतने समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा । यदि ऊपर वर्णित कालावधि:



के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम् के लिए निर्देश स्वतः रद्द हो जाएगा और हम नए माध्यस्थम् के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे ।

साक्षी

पक्षकारों के हस्ताक्षर:—

- |         |                         |
|---------|-------------------------|
| 1. (ह०) | 1. (ह०) एन० बी० सेठना । |
| 2. (ह०) | 2. (ह०) (के० एम० राव ।  |

मैं इस औद्योगिक विवाद में माध्यस्थ के रूप में कार्य करने की सहमति देता हूँ ।

( ह० ) एस० सी० सेठ ।

#### उपाबंध—क

मुम्बई, 19-11-70

वे सदस्य जिन्होंने पडाव बाजार एसोसिएशन को उनकी ओर से माध्यस्थम् करार पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकार दिया है ।

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. मेसर्स एन० आर० नजीर एण्ड संस  | स्टाक एक्सचेंज बिल्डिंग, हमाम स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई—1             |
| 2. मेसर्स नूरभाई गल्लाभाई खानभाई | 19, करवर स्ट्रीट फोर्ट मुम्बई—1                                    |
| 3. मेसर्स काठियावाड एण्ड मालावार | कोस्ट्स लाइटरेज क०, बोट हार्ड रोड, धारुवाना, मुम्बई—10             |
| 4. मेसर्स बी० के० शालवाला        | नवजीवन बिल्डिंग, मराठी मन्दिर निकट, मुम्बई सैन्ट्रल, मुम्बई        |
| 5. श्रीमती ई०सी० गल्लाभाई        | 19, करवर स्ट्रीट, फोर्ट मुम्बई—1                                   |
| 6. मेसर्स एच० एच० इस्माइल        | टिम्बर मर्चेन्ट, बोट हार्ड रोड, धारुवाना, मुम्बई—10                |
| 7. मेसर्स एन०ए० पीरभाई           | इब्राहिम मेन्सन डोंगरी, मुम्बई                                     |
| 8. मेसर्स महादेव लाहू पटेल       | द्वारा/पडाव बाजार एसोसिएशन, साई निवास, पी० डी० मैलो रोड, मुम्बई—1  |
| 9. मेसर्स एसू हावा               | द्वारा/पडाव बाजार एसोसिएशन, साई निवास, पी० डी०, मैलो रोड, मुम्बई—1 |
| 10. मेसर्स राम मस्थी             | द्वारा/पडाव बाजार एसोसिएशन साई निवास, पी० डी० मैलो रोड, मुम्बई—1   |
| 11. मेसर्स एस० के० मूर एण्ड संस  | श्रीमर बिल्डिंग, नूरबाग के सामने, मुम्बई—9                         |
| 12. मेसर्स ए०बी० पटेल            | सं० 759, पारसी कालोनी रोड, सं० 7, दादर, मुम्बई                     |
| 13. मेसर्स गणपत सदाशिव           | द्वारा/पडाव बाजार एसोसिएशन, साई निवास, पी० डी० मैलो रोड, मुम्बई—1  |

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 14. मेसर्स दालवी ब्रदर्स            | द्वारा/नव भारत टिम्बर कम्पनी, बोट हाई रोड धारुखाना, मुम्बई—10                |
| 15. मेसर्स फेयरडील लाइटरेज          | द्वारा/पडाव बाजार एसोसिएशन, साई निवास, पी० डी० मैलो रोड, धारुखाना, मुम्बई—10 |
| 16. मेसर्स दि इंडियन लाइटरेज कंपनी  | द्वारा/पडाव बाजार एसोसिएशन, साई निवास, पी० डी० मैलो रोड, धारुखाना, मुम्बई—10 |
| 17. मेसर्स डी० एस० बाजपेई           | खतीजा मजिल, हाथी बाग लेन, मजरा, मुम्बई—10                                    |
| 18. मेसर्स कालूराम पांडुरंग         | द्वारा/पडाव बाजार एसोसिएशन, साई निवास, पी० डी० मैलो रोड, मुम्बई—1            |
| 19. मेसर्स नामदेव राजाराम           | द्वारा/पडाव बाजार एसोसिएशन, साई निवास, पी० डी० मैलो रोड, मुम्बई—1            |
| 20. मेसर्स वसरथ गणपत पाटिल          | यथोक्त   |
| 21. मेसर्स टी०बी० मायेकर            | यथोक्त   |
| 22. मेसर्स नारायण गंगाराम           | यथोक्त   |
| 23. श्रीमती बोम्बात                 | यथोक्त   |
| 24. मेसर्स एन०एम० गांधी             | 788, पारसी कालोनी, वादर, मुम्बई—14   |
| 25. मेसर्स पोर्टिया ट्रेडिंग कम्पनी | क्वे स्ट्रीट, धारुखाना, मुम्बई—10  |
| 26. मेसर्स शाह एण्ड फेरवाडी         | द्वारा/नवभारत टिम्बर कम्पनी, बोट हाई रोड, धारुखाना, मुम्बई—10                |
| 27. मेसर्स गंगाराम शिवराम           | द्वारा/पडाव बाजार एसोसिएशन साई निवास, पी० डी०, मैलो रोड, मुम्बई—1            |

[सं० 78/5/70-पी एण्ड डी]

अजित चन्द्र, अवर सचिव।

(Department of Labour and Employment)  
(Office of the Chief Labour Commissioner (Central))

#### ORDERS

New Delhi, the 18th December 1970

**S.O. 183.**—Whereas an application has been made under section 19(b) of the Payment of Bonus Act, 1965 by Messrs Bhulanbararee Coal Company Limited. (employer) in relation to their establishments mentioned in the Schedule below for extension of the period for the payment of bonus to their employees for the accounting year ending on 30th April, 1970.

And whereas being satisfied that there are sufficient reasons to extend the time I have, in exercise of the powers conferred on me by the proviso to clause (b) of Section 19 of the said Act read with the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. WB.20(42)/65 dated the 28th August, 1965, passed order on 18th December, 1970 extending the period for payment of the said bonus by the said employer by two months (i.e. up to 28th February, 1971) from the last date for payment of bonus under clause (b) of Section 19 of the Act.

Now this is published for information of the employer and all the employees of the said establishment.

THE SCHEDULE

Name and address of the employer(s).	Establishment(s).
The Bhulanbararee Coal Company Limited, 4, Clive Row, Calcutta.	Bhulanbararee Colliery, P.O. Patherdih (Dhanbad).

[No. BA-5(28)/70-LS.I.]

(श्रम और रोजगार विभाग)  
(सुस्थ श्रम आयुक्त (कन्द्रीय) का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1970

एस० नो० 183 :—यतः मेसर्स बुलन बरारी कोल कम्पनी (लि०) (नियोजक) ने नीचे की अनुसूची में वर्णित अपनी स्थापनों के संबंध में 30-4-70 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए अपने कर्मचारियों को बोनस के संदाय की कालावधि को बढ़ाने के लिए बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 19(ख) के अधीन आवेदन दिया है।

और, यतः यह समाधान हो जाने पर कि समय बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण है, मैंने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० डब्ल्यू बी-20(42)/65 तारीख 28 अगस्त, 1965 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 18-12-70 को उक्त नियोजक द्वारा उक्त बोनस के संदाय की कालावधि को अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ख) के अधीन बोनस के संदाय की अंतिम तारीख से 2 महीने (अर्थात् 28-2-1971 तक) बढ़ाने का आदेश दे दिया है।

अब इसे उक्त स्थापन के नियोजक और सभी कर्मचारियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

अनुसूची

नियोजक/नियोजकों का नाम और पता	स्थापन
बुलन बरारी कोल कं० (लि०) 4 क्लाइव रोड, कलकत्ता	बुलन बरारी कोइलरी, पी० नो० पत्थर ड़िह (धनबाद)

[सं० बी० ए० 5(28)/70-एल०एस०-1]

New Delhi, the 19th December 1970

S.O. 184.—Whereas an application has been made under section 19(b) of the Payment of Bonus Act, 1965 by Messrs Bhulanbararee Coal Company Limited, (employer) in relation to their establishments mentioned in the Schedule below for extension of the period for the payment of bonus to their employees for the accounting year ending on 31st March, 1970.

And whereas being satisfied that there are sufficient reasons to extend the time I have, in exercise of the powers conferred on me by the proviso to clause (b) of Section 19 of the said Act read with the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. WB.20(42)/65 dated the 28th August, 1965, passed order on 18th December, 1970 extending the period for payment of the said

said bonus by the said employer by two months (i.e. up to 31st January, 1971) from the last date for payment of bonus under clause (b) of Section 19 of the Act.

Now this is published for information of the employer and all the employees of the said establishment.

#### THE SCHEDULE

Name and address of the employer(s).	Establishment(s).
M/s. S. Kantilal and Company Private Limited, P.O. Box No. 114, Margao-GOA.	M/s. S. Kantilal and Company Pvt. Ltd., Gosalia Building, Margao-GOA.

[No. BA-6(22)/70-LS.I.]

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1970

**एस० प्रो० 184 :—**यतः मेसर्स एस कान्तिलाल एण्ड कम्पनी प्रा० (लि०) (निरोजक) ने नीचे की अनुसूची में वर्णित अपने स्थापनों के संबंध में 31-3-70 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए अपने कर्मचारियों को बोनस के संदाय की कालावधि को बढ़ाने के लिए बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 19(ख) के अधीन आवेदन दिया है।

और यतः यह समाधान हो जाने पर कि समय बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण है, मैंने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० डब्ल्यू बी-20(42)/65, तारीख 28 अगस्त, 1965 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा सुझे प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 18-12-70 को उक्त नियोजक द्वारा उक्त बोनस के संदाय की कालावधि को अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ख) के अधीन बोनस के संदाय अंतिम तारीख से 2 महीने (अर्थात् 31-1-1971 तक) बढ़ाने का आदेश दे दिया है।

अब इसे उक्त स्थापन के नियोजक और सभी कर्मचारियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

#### अनुसूची

नियोजक/नियोजकों का नाम और पता	स्थापन
मेसर्स एस० कान्ती लाल एण्ड कम्पनी प्रा० (लि०) पो० प्रो० बॉक्स न० 114, मार्गाव-गोआ	मेसर्स एस० कान्ती लाल एण्ड कम्पनी प्रा० (लि०)

[सं० बी० ए० 6(22)/70-एल०एस०-1]

New Delhi, the 21st December 1970

**S.O. 185.**—Whereas an application has been made under section 19(b) of the Payment of Bonus Act, 1965 by Messrs Shantilal Khushaldas and Brothers Private Limited, (employer) in relation to their establishments mentioned in the Schedule below for extension of the period for the payment of bonus to their employees for the accounting year ending on 31st March, 1970.

And whereas being satisfied that there are sufficient reasons to extend the time I have, in exercise of the powers conferred on me by the proviso to clause (b) of Section 19 of the said Act read with the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No.WB.20(42)/65 dated the 28th August, 1965, passed order on 18th December, 1970 extending the period for payment of the said bonus by the said employer by two months (i.e. up to 31st January, 1971) from the last date for payment of bonus under clause (b) of Section 19 of the Act.

Now this is published for information of the employer and all the employees of the said establishment.

THE SCHEDULE

Name and address of the employer(s).	Establishment(s).
M/s. Shantilal Khushaldas and Brothers Private Limited, P.B. No. 35, MARGAO, GOA.	M/s. Shantilal Khushaldas & Bros. Pvt. Ltd., Gosalia Building Margao-GOA.

[No. BA-6(23)/70-LS.I.]

O. VENKATACHALAM,  
Chief Labour Commissioner (Central).

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर 1970

**एस० प्रो० 185 :—**यतः मैसर्स कान्ती लाल खुशाल दास एण्ड ब्रदर्स (प्रा०) लि० (नियोजक) ने नीचे की अनुसूची में वर्णित अपने स्थापनों के संबंध में 31-3-1970 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए अपने कर्मचारियों को बोनस के संदाय की कालावधि को बढ़ाने के लिए बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 19(ख) के अधीन आवेदन दिया है।

श्रीर यतः यह समाधान हो जाने पर कि समय बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण है, मैंने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० डब्ल्यू बी-20(42)/65 तारीख 28 अगस्त, 1965 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 18-12-70 को उक्त नियोजक द्वारा उक्त बोनस के संदाय की कालावधि को धारा 19 के खण्ड (ख) के अधीन बोनस के संदाय को अंतिम तारीख से 2 महीने (अर्थात् 31-1-1971 तक) बढ़ाने का आदेश दे दिया है।

अब इसे उक्त स्थापन के नियोजक और सभी कर्मचारियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

अनुसूची

नियोजक/नियोजकों  
का नाम और पता

स्थापन

मैसर्स शान्ती लाल खुशाल दास एण्ड ब्रदर्स (प्रा०) लि०, पो०ब०न० 35, मार्गोआ, गोवा	मैसर्स शान्ती लाल खुशाल दास एण्ड ब्रदर्स (प्रा०) लि०, गोसालिया बिल्डिंग, मार्गोआ, गोवा
---	--

[सं० बी०ए० 6(23) 70-एल०एस०-1]

प्रो० वेंकटचलम,

मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)

**(Department of Rehabilitation)**  
**(Office of the Chief Settlement Commissioner)**

*New Delhi, the 24th December 1970*

**S.O. 186.**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints the Sub-Divisional Officer (Civil), Una and Naib Tehsildar (Sales), Una and Sub-Divisional Officer (Civil), Narpur and Naib-Tehsildar, (Sales), Narpur in Himachal Pradesh as Settlement Officers in their respective jurisdictions of (i) District Simla, Tehsils Una, Hamirpur and Dehra Gopipur of Kangra district and Mahasu, Bilaspur and Sirmur districts, and (ii) District Kulu, Lahaul and Spiti, Narpur Tehsil, Kangra and Kangra District and Chamba and Mandi Districts, for the purpose of performing in addition to their own duties as sub-Divisional Officers (Civil) and Naib Tehsildars (Sales) the functions assigned to Settlement Officer by or under the said Act in respect of (i) urban acquired evacuee properties and urban agricultural lands, and (ii) rural acquired evacuee properties including agricultural lands and shops, houses, cattle sheds and vacant sites in any rural area, forming part of the compensation pool.

[No. F.3(2)/LR/67.]

W. G. PATHAK,

Chief Settlement Commission and *Ex-officio* Jt. Secy.

(पुनर्वास विभाग)

(मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त का कार्यालय)

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1970

**क्र० आ० 186.**—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश में उप मण्डल अधिकारी (सिविल), ऊना तथा नायब तहसीलदार (बित्री), ऊना और उप मण्डल अधिकारी (सिविल), नूरपुर तथा नायब तहसीलदार (बित्री) नूरपुर को अपने कार्य-क्षेत्र (i) जिला शिमला, तहसील ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा जिले के देहरा, गोपीपुर और महासू, बिलासपुर तथा सिरमूर जिले और (ii) जिला कुल्लू, लाहौल, स्पिती, नूरपुर तहसील, कांगड़ा जिला कांगड़ा, तथा चम्बा और मण्डी जिले में उप मण्डल अधिकारी (सिविल) तथा नायब तहसीलदार (बित्री) के रूप में सौंपे गए अपने कार्यों के अलावा मुआवजा पूल की (i) शहरी अर्जित निष्क्रान्त सम्पत्तियाँ और शहरी कृषि भूमि, तथा तथा (ii) ग्रामीण अर्जित निष्क्रान्त सम्पत्तियों के, जिनमें किसी ग्रामीण क्षेत्र को कृषि भूमि, तथा वृकानें, मकान, पशुशालाएं तथा खाली स्थान भी शामिल ह, संबंध में उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत बन्दोबस्त अधिकारी को सौंपे गये कार्यों को करने के लिए बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 3(2)/एस० आर०/67]

वा० ग० पाठक,

[मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त तथा पदेन संयुक्त सचिव।

**(Department of Rehabilitation)**

**(Office of the Chief Settlement Commissioner)**

*New Delhi, the 26th September 1970*

**S.O. 187.**—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 55 of the Admm. of Evacuee Property Act, 1950, (Act XXXI of 1950), the Central Government, hereby directs that the powers exercisable by it under Section 54 of the said Act, shall be exercisable also by the Financial Commissioner (Taxation) and Secretary to the Govt. of Punjab, Rehabilitation Department and the Secretary to the Government of Haryana, Rehabilitation Department in respect to evacuee properties situate within the States of Punjab and Haryana respectively subject to the condition that such power shall not be exercised in relation to any property concerning which an order has been made by the officer in any other capacity.

[No. F. 5(27)/61-Prop—Vol. II]

W. G. PATHAK, Joint Secy.

(पुनर्वास विभाग)

(मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त का कार्यालय)

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1970

एस० ओ० 187.—निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रशासन अधिनियम, (1950 का अधिनियम XXXI) की धारा 55 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निवेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 54 के अधीन वह जिन शक्तियों का प्रयोग करती है उनका प्रयोग वित्तीय आयुक्त (कराधान) और सचिव पंजाब सरकार, पुनर्वास विभाग तथा सचिव, हरियाणा सरकार, पुनर्वास विभाग द्वारा भी क्रमशः पंजाब और हरियाणा राज्य में स्थित निष्क्रान्त सम्पत्तियों के संबंध में दिया जाएगा किन्तु शर्त यह होगी कि ऐसी शक्ति किसी ऐसी सम्पत्ति के संबंध में प्रयुक्त नहीं की जाएगी जिसके संबंध में उस अधिकारी ने किसी और हैसियत से कोई आदेश दिया हो।

[सं० फा० 5(27)/61-प्राप०खण्ड०II]

उद्भू० जी० पाठक, संयुक्त सचिव।

(Department of Rehabilitation)

(Office of the Chief Settlement Commissioner)

New Delhi, the 18th December 1970

S.O. 188.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 4 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (XXXI of 1950), the Central Government hereby appoints Shri Gulab L. Ajwani, Regional Settlement Commissioner, New Delhi as Custodian of Evacuee Property for the States of Punjab and Haryana for the purpose of discharging the duties imposed on Custodian by or under the said Act, in respect of the Composite Properties and Industrial undertakings with immediate effect.

[No. 5(2)/AGZ/63.

(पुनर्वास विभाग)

(मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त का कार्यालय)

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1970

एस० ओ० 188.—निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 6 उपधारा 1 का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा श्री गुलाब एल० अजवानी, आदेशिक बन्दोबस्त आयुक्त नई दिल्ली को उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अभिरक्षक को सौंपे गये कार्यों को करने के लिए तत्काल प्रभाव से मिश्रित निष्क्रान्त सम्पत्तियों के लिए पंजाब तथा हरियाणा राज्यों का निष्क्रान्त सम्पत्ति अभिरक्षक नियुक्त करती है।

[संख्या 5(2)/ए०जी०जेड०/63

S.O. 189.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 4 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (XXXI of 1950), the Central Government hereby appoints Shri Gulab L. Ajwani, Regional Settlement Commissioner, New Delhi as Custodian of Evacuee Property for the States of U. P., Bihar, Orissa, Rajasthan, Madhya Pradesh and the Union Territory of Himachal Pradesh for the purpose of discharging the duties imposed on Custodian by or under the said Act, with immediate effect.

[No. 5(2)/AGZ/63

एस० नो० 189.—निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 6 की उपधारा 1 का प्रयोग करते हुए प्रादेशिक केन्द्रीय सरकार उसके द्वारा श्री गुलाब एल० अजवानी, प्रादेशिक बन्दोबस्त आयुक्त, नई दिल्ली को उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अभिरक्षक को सौंपे गये कार्यों को करने के लिए तत्काल प्रभाव से निष्क्रान्त सम्पत्तियों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, मध्यप्रदेश राज्यों तथा केन्द्रशासित हिमाचल प्रदेश का निष्क्रान्त सम्पत्ति अभिरक्षक नियुक्त करती है।

[संख्या 5(2)/ए०जी०जेड०/63]

*New Delhi, the 22nd December 1970*

S.O. 190.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri W. G. Pathak, Joint Secretary in the Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation (Department of Rehabilitation) as Chief Settlement Commissioner for the purpose of performing the functions assigned to such Chief Settlement Commissioner by or under the said Act, with effect from the 14th August, 1970.

[No. 5(5)/Admn.II/70.]

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1970

एस० नो० 190.—विस्थापित व्यक्ति (मुआविजा तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) के भाग 3 के अनुभाग 1 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री डब्ल्यू० जी० पाठक संयुक्त सचिव, श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) को मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में 14-8-1970 से इस उद्देश्य से नियुक्त किया है ताकि वे उन कार्यों का पालन कर सकें जो कि मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त की उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गई हैं।

[संख्या 5/5/एडमिन II/70]

S.O. 191.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoints Shri W. G. Pathak, Joint Secretary in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) as Custodian General of Evacuee Property for the purpose of performing the functions assigned to such Custodian General by or under the said Act with effect from the 14th August, 1970.

[No. 5(5)/Admn.II/70.]

एस० नो० 191.—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रबन्ध अधिनियम, 1950 (1950 का 31) के भाग 5 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के श्री डब्ल्यू० जी० पाठक, संयुक्त सचिव, श्रम रोजगार, तथा पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) को निष्क्रान्त सम्पत्ति महाभिरक्षक के रूप में 14-8-70 से नियुक्त किया है। ताकि वे उन कार्यों का पालन कर सकें जो कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गई हैं।

[संख्या 5/5/एडमिन II/70]

S.O. 192.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Claims) Supplementary Act, 1954 (No. 12 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri W. G. Pathak, Joint Secretary in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) as Chief Settlement Commissioner for purpose of performing the functions assigned to such Chief Settlement Commissioner by or under the said Act with effect from the 14th August, 1970.

[No. 5(5)/Admn.II/70.]

JANKI NATH,  
Settlement Commissioner (C) & Ex-Officio, Under Secy.



एस० नो० 192.—विस्थापित व्यक्ति (मुआबिजा) अनुपूरक अधिनियम, 1954 (1954 के संख्या 12) के धारा 3 के अनुभाग 1 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग का करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री डब्ल्यू० जी० पाठक, संयुक्त सचिव, श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) को मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में 14-8-1970 से इस उद्देश्य से नियुक्ति की है। ताकि वे उन कार्यों का पालन कर सकें जो कि मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त को या उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गई हैं।

[संख्या 5(5)/एडमिन-II/70]

जानकी नाथ,

बन्दोबस्त आयुक्त (सी) तथा पदेन अव्वर सचिव।

## CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

INCOME-Tax

New Delhi, the 27th June 1970

S.O. 193.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes, hereby makes the following amendment in the Schedule appended to its Notification No. 45 (F. No. 261/8/70-ITJ), dated 31st March 1970, namely:—

Against Kolhapur Range, Kolhapur under column 2, the following shall be added:—

18 Collection Circle, Kolhapur.

Against Thana Range, Thana under column 2, the following shall be added:—

20. Collection Circle I, Thana.

21. Collection Circle II, Thana.

This Notification shall take effect from 22nd June, 1970.

### Explanatory Note

The amendment has become necessary on account of redesignating the existing charges, namely Recovery Circles in the Commissioners' Charge, as under:—

#### Existing Charge

- (1) Recovery Circle, Kolhapur
- (2) Recovery Circle I, Thana
- (3) Recovery Circle II, Thana

#### To be redesignated

- Collection Circle, Kolhapur.
- Collection Circle I, Thana.
- Collection Circle II, Thana.

(This note does not form part of the Notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 112 (F. No. 261/8/70-ITJ).]

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर

नई दिल्ली, 27 जून, 1970

एस० नो० 193.—आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपनी अधिसूचना सं० 45 (एफ० सं० 261/8/70-आई० टी०

जे०) तारीख 31-3-1970 से संलग्न अनुसूची में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

कोल्हापुर रेंज, कोल्हापुर के सामने, स्तम्भ 2 के नीचे, निम्नलिखित जोड़ा जायेगा :—  
18 संग्रहण सकिल, कोल्हापुर ।

थाना रेंज, थाना के सामने, स्तम्भ 2 के नीचे, निम्नलिखित जोड़ा जायेगा :—

20. संग्रहण सकिल 1, थाना

21. संग्रहण सकिल 2, थाना

यह अधिसूचना 22 जून, 1970 से प्रभावी होगी ।

#### स्पष्टीकारक टिप्पण

यह संशोधन विद्यमान भार साधनों, अर्थात् आयुक्तों के भारसाधन में वसूली सकिलों, के निम्नलिखित रूप से पुनः अभिहित किये जाने के कारण आवश्यक हो गया है :—

विद्यमान भारसाधन

निम्नलिखित रूप से पुनः अभिहित किया जायेगा

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| (1) वसूली सकिल, कोल्हापुर | संग्रहण सकिल, कोल्हापुर |
| (2) वसूली सकिल, 1, थाना   | संग्रहण सकिल 1, थाना    |
| (3) वसूली सकिल 11,        | संग्रहण सकिल 11, थाना   |

(यह टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है किन्तु इसका आशय केवल स्पष्टीकरण करना

[संख्या 112 (एफ० सं० 261/8/70—आई० टी० जे०)]

*New Delhi, the 4th August 1970*

S.O. 194.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment in the schedule appended to its Notification No. 61 (F. No. 261/12/70-ITJ), dated 30th April 1970.

In the schedule against the Bhubaneswar Range, Bhubaneswar, the following shall be added in column 3:—

(iii) Balasore Circle, Balasore.

This notification shall take effect from 4th August, 1970.

#### *Explanatory Note*

The amendment has become necessary on account of creation of I.T. Circle at Balasore and consequent reorganisation of Baripada Circle also.

(The above note does not form part of the notification, but is intended to be merely clarificatory).

[No. 136(F. No. 261/12/70-ITJ).]

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1970

एस० ओ० 194.—आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपनी अधिसूचना सं० 61 (फा०

सं० 261/12/70 आ० टी० जे०) तारीख 30-4-70 से उपाबद्ध अनुसूची में एतद्वारा निम्न-लिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

अनुसूची में भुवनेश्वर रेंज, भुवनेश्वर के सामने स्तम्भ-3 में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा :—  
iii वालासीर सर्किल, वालासीर

यह अधिसूचना 4 अगस्त, 1970 से प्रभावी होगी ।

[सं० 136 (फा० सं० 261/12/70-आई० टी० जे०)]

New Delhi, the 7th August, 1970

**S.O. 195.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all the previous notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column 2 of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column 3 thereof :—

SCHEDULE

Sl. No.	Ranges	Income-tax Circles, Wards & Districts.
1	2	3
1	Range-I, Agra	(i) A to D Ward, Agra. (ii) Special ward, Agra. (iii) I.T.O. (Collection), Agra. (iv) Circle-I, Agra excluding Circle-I (5) and Circle-I(6) Agra. (v) Firozabad.
2	Range-II, Agra.	(i) E to H and J-ward, Agra. (ii) I.T.O. (Administration), Agra. (iii) Special Survey Circle, Agra. (iv) Circle-I (5), Agra. (v) Circle-I (6), Agra. (vi) Circle-II (1), Agra. (vii) Circle-II (2), Agra. (viii) Etah. (ix) Mathura.
3	Range-III, Agra	(i) Agra Circle excluding the following wards :— (a) A to H ward, Agra. (b) I.T.O. (Admn.), Agra. (c) I.T.O. (Coll.), Agra. (d) J-ward, Agra. (ii) Circle-II, Agra excluding Circle-II (1) and Circle-II (2), Agra. (iii) Hathras. (iv) Mainpuri.
4	Dehradun	(i) Dehradun. (ii) E. D.-cum-I.T. Circle, Dehradun. (iii) Roorkee. (iv) Saharanpur.

1	2	3
5	Range-I, Kanpur	<ul style="list-style-type: none"><li>(i) Circle-II(I), Kanpur.</li><li>(ii) Circle-II (2), Kanpur.</li><li>(iii) Circle-II (3), Kanpur.</li><li>(iv) Circle-II (6), Kanpur.</li><li>(v) Circle-II (7), Kanpur.</li><li>(vi) Special Circle A-Ward, Kanpur.</li><li>(vii) Etawah.</li><li>(viii) Orai.</li></ul>
6	Range-II, Kanpur	<ul style="list-style-type: none"><li>(i) Circle II, Kanpur excluding :— Circle II(I), Circle II(2), Circle II(3), Circle II(6), and Circle II(7), Kanpur.</li><li>(ii) Special Circle, B-Ward, Kanpur.</li><li>(iii) Banda.</li><li>(iv) Special Survey Circle, Kanpur.</li><li>(v) Salary Circle, Kanpur.</li><li>(vi) Project Circle, Kanpur.</li></ul>
7	Range-III, Kanpur	<ul style="list-style-type: none"><li>(i) Circle I, Kanpur excluding :— Circle I(4), Circle I(5), Circle I(9), and Circle I(10) Kanpur.</li><li>(ii) Special Circle, C-Ward, Kanpur.</li><li>(iii) ED-Cum-IT Circle, Kanpur.</li><li>(iv) Fatehgarh.</li><li>(v) Unnao.</li></ul>
8	Range IV, Kanpur.	<ul style="list-style-type: none"><li>(i) Circle I(4), Kanpur.</li><li>(ii) Circle I(5), Kanpur.</li><li>(iii) Circle I(9), Kanpur.</li><li>(iv) Circle I(10), Kanpur.</li><li>(v) Companies Circle, Kanpur.</li><li>(vi) Jhansi.</li></ul>
9	Range-I, Meerut	<ul style="list-style-type: none"><li>(i) Meerut Circle excluding C &amp; G-Ward, Meerut.</li><li>(ii) Project Circle, Meerut</li><li>(iii) Special Circle, Meerut.</li><li>(iv) Special Survey Circle, Meerut.</li><li>(v) Ghaziabad.</li><li>(vi) Muzaffarnagar.</li><li>(vii) Hapur at Meerut.</li></ul>
10	Range-II, Meerut	<ul style="list-style-type: none"><li>(i) C &amp; G-wards, Meerut:</li><li>(ii) Aligarh.</li><li>(iii) Salary Circle, Meerut.</li></ul>
11	Range-III, Meerut	<ul style="list-style-type: none"><li>(i) Central Circles at Meerut.</li><li>(ii) Central Circles at Kanpur.</li></ul>

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of Incometax of the Range from whom that Incometax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall, from the date this notification shall take effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said circle, ward or district or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 7th August, 1970.

The amendments have become necessary on account of reorganisation AACs' jurisdiction and for assigning appellate jurisdiction over some newly created Circles in the Commissioner's charge.

(The above note does not form part of the notification, but is intended to be merely clarificatory).

[No. 137(F. No. 261/16/70-ITJ).]

नई दिल्ली, 7 अगस्त 1970

एस० प्रो० 195.—आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये और इस सम्बन्ध में सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं को अधिक्रान्त करते हुये केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि नीचे के स्तम्भ -2 विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) उसके स्तम्भ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आय-कर सकिलों, बोर्डों, और जिलों में आय कर या अधिकर के लिये निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे :—

## अनुसूची

क्रम	रेंज	आय-कर सकिल, वार्ड और जिलों
संख्या		
1. रेंज-1		(i) 'क' से 'घ' वार्ड, आगरा
आगरा		(ii) विशेष वार्ड, आगरा
		(iii) आय कर अधिकारी (संग्रहण), आगरा ।
		(iv) सकिल-1, (5) और सकिल 1(6) आगरा को अपवर्जित करते हुये सकिल 1, आगरा ।
		(v) फिरोजाबाद
2. रेंज-2		(i) (ड) से (ज) और (ब) वार्ड आगरा ।
आगरा ।		(ii) आय कर अधिकारी, (प्रशासन), आगरा ।
		(iii) विशेष सर्वेक्षण सकिल, आगरा ।
		(iv) सकिल 1(5) आगरा ।
		(v) सकिल 1(6), आगरा ।
		(vi) सकिल-II (1), आगरा ।
		(vii) सकिल-II (1), आगरा ।
		(viii) एटा ।
		(ix) मथुरा ।
3. रेंज-3, आगरा		(i) आगरा सकिल, निम्नलिखित वार्डों को अपवर्जित करते हुये—
		(क) क से ज, वार्ड, आगरा ।
		(ख) आयकर अधिकारी, (प्रशासन), आगरा ।
		(ग) आयकर अधिकारी (संग्रहण), आगरा ।
		(घ) ज—वार्ड, आगरा ।
		(ii) सकिल-II (1) और सकिल II (2), आगरा को अपवर्जित करते हुए सकिल-2, आगरा ।
		(iii) हाथरस ।
		(iv) मैनपुरी ।
4. देहरादून		(i) देहरादून ।
		(ii) सम्पदा शुल्क और आयकर सकिल, देहरादून ।
		(iii) रुड़की ।
		(iv) सहरनपुर ।

1

2

3

5. रेंज-I, कानपुर

- (i) सफिल-II (1), कानपुर ।
- (ii) सफिल-II (2), कानपुर ।
- (iii) सफिल-II (3), कानपुर ।
- (iv) सफिल-II (6), कानपुर ।
- (v) सफिल-II (7), कानपुर ।
- (vi) विशेष सफिल क—वार्ड, कानपुर ।
- (vii) इटावा ।
- (viii) उरई ।

6. रेंज-II, कानपुर ।

- (i) सफिल II (1), सफिल II (2), सफिल II (3), सफिल II (6) और सफिल II (7), कानपुर को अपवर्जित करते हुये सफिल II, कानपुर ।
- (ii) विशेष सफिल, ख—वार्ड, कानपुर ।
- (iii) बांदा ।
- (iv) विशेष सर्वेक्षण सफिल, कानपुर ।
- (v) सम्बलम सफिल, कानपुर ।
- (vi) प्रायोजना सफिल, कानपुर ।

7. रेंज-III, कानपुर

- (i) सफिल 1 (4), सफिल (1) (5), सफिल 1 (9), और सफिल 1 (10) कानपुर को अपवर्जित करते हुये सफिल-1, कानपुर ।
- (ii) विशेष सफिल, ग—वार्ड, कानपुर ।
- (iii) सम्पदा शुल्क और आय कर सफिल, कानपुर ।
- (iv) फतेहगढ़ ।
- (v) उन्नाव ।

8. रेंज-IV, कानपुर

- (i) सफिल 1 (4), कानपुर ।
- (ii) सफिल 1 (5), कानपुर ।
- (iii) सफिल 1 (9), कानपुर ।
- (iv) सफिल 1 (10), कानपुर ।
- (v) कम्पनी सफिल, कानपुर ।
- (vi) आसी ।

9. रेंज-I, मेरठ

- (i) ग और छ वार्ड मेरठ, को अपवर्जित करते हुये मेरठ सफिल ।
- (ii) प्रायोजना सफिल, मेरठ ।
- (iii) विशेष सफिल, मेरठ ।
- (iv) विशेष सर्वेक्षण सफिल, मेरठ ।
- (v) गाजियाबाद ।
- (vi) मुजफ्फरनगर ।
- (vii) मेरठ मे हापुड़ ।

1

2

3

10. रेंज-II, मेरठ (i) ग और छ वार्ड, मेरठ ।  
(ii) अलीगढ़ ।  
(iii) सम्बलम सिकिल, मेरठ ।
11. रेंज-III, मेरठ । (i) मेरठ में केन्द्रीय सिकिलें ।  
(ii) कानपुर में केन्द्रीय सिकिलें ।

जहाँ कोई आयकर सिकिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से दूसरी रेंज को अन्तरित हो गया है वहाँ उस आय कर सिकिल, वार्ड या जिले या उस के किसी भाग में निर्धारणों से उद्भूत अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित थीं, जिससे वह आय कर सिकिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सिकिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तरित कर दी जायेंगी और उन के सम्बन्ध में कार्यावाही उक्त सहायक आयुक्त (अपील) द्वारा की जायेगी ।

यह अधिसूचना 7 अगस्त, 1970 से प्रभावी होगी ।

[सं० 137 (फा० सं० 261/16/70-आई० टी० जे०)]

*New Delhi, the 9th August 1970*

**S.O. 196.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment in the Schedule appended to its Notification No. 111 (F. No. 261/2/70-ITJ), dated 22nd June, 1970, namely:

In the said schedule against Tiruchirapalli Range, Tiruchirapalli under Column 2, the following shall be substituted, namely:

**Tiruchirapalli Range.**

1. Tiruchirapalli Circle.
2. City Circle I (all Sections), Tiruchirapalli.
3. City Circle II (all Sections), Tiruchirapalli.
4. Companies Circle, Tiruchirapalli.
5. Pudukottai Circle (all Sections).
6. Karaikudi Circle (all Sections).
7. Ramanathapuram Circle.

This Notification shall take effect from the 1st August, 1970.

*Explanatory Note*

The amendment has become necessary on account of bifurcation of the existing City Circle I, Tiruchirapalli into two circles known as City Circle I and City Circle II, Tiruchirapalli and creation of a new Circle with headquarters at Ramanathapuram.

[The above note does not form a part of the notification but is intended to be merely clarificatory].

[No. 138 (F. No. 261/2/70-ITJ).]

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1970

एत० ओ० 196 :—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपनी अधिसूचना सं० 111 (फा० सं० 261/2/70 आई० टी० जे०) तारीख 22 जून 1970 से उपाबद्ध अनुसूची में एतद्-द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् उक्त अनुसूची में त्रिचिरापल्ली रेंज त्रिचिरापल्ली के सामने स्तम्भ-2 के नीचे निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

त्रिचिरापल्ली रेंज ।

1. त्रिचिरापल्ली सर्किल ।
2. नगर सर्किल-I (सभी विभाग) त्रिचिरापल्ली ।
3. नगर सर्किल-II (सभी विभाग) त्रिचिरापल्ली ।
4. कम्पनी सर्किल, (त्रिचिरापल्ली) ।
5. पुडूकोट्टई सर्किल (सभी विभाग) ।
6. करैकुडी सर्किल (सभी विभाग) ।
7. रामानाथापुरम सर्किल ।

यह अधिसूचना 1 अगस्त, 1970 से प्रभावी होगी ।

[सं० 138 (फा० सं० 261/2/70 आई० टी० जे०)]

**S. O. 197.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all previous notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes, hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax specified in Column (1), of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or supertax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column (2) thereof

#### SCHEDULE

Range (1)	Income-tax Circle, Wards & Districts (2)
1. Central Range I, Bombay	. All cases under the jurisdiction of Income-tax Officers, Sections I, II, IV, VIII, XII, XVIII, XIX and XX (Central) Bombay.
2. Central Range II, Bombay	. All cases under the jurisdiction of Income-tax Officers, Sections III, IX, XI, XIII, XVI & XXII (Central) Bombay.
3. Central Range III, Bombay	. All cases under the jurisdiction of Income-tax Officers, Sections VII, X, XV, XVII, XXI, & XXIII (Central) Bombay and Central Circle, Ahmedabad.
4. Central Range IV, Bombay	. All cases under the jurisdiction of Income-tax Officers, Sections V, VI & XIV (Central), Bombay and Central Circles II & V, Nagpur.
5. Central Range, Nagpur	. All cases under the jurisdiction of Income-tax Officers, Central Circles I, III & IV, Nagpur.



Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall, from the date this notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from the 5th August, 1970.

#### Explanatory Note

The amendment has become necessary on account of the creation of a new Range of A.A.C. known as A.A.C., Central Range IV, Bombay and redistribution of work amongst the A.A.Cs.

(The above note does not form a part of the notification, but is intended to be merely clarificatory).

[No. 139 (F. No. 261/14/70-ITJ).]

एस० ओ० 197 :—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस सम्बंध में सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं को अधिकांश करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद् द्वारा निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट सहायक आयकर प्रायुक्त (अपील) उसके स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सक्तियों बाडों और जिलों में आयकर या अधिकार के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे :—

#### अनुसूची

रेंज	आयकर सक्तिल, बाड और जिले
(1)	(2)
1. केन्द्रीय रेंज-1, मुम्बई 1	आयकर अधिकारी खण्ड 1, 2, 4, 7, 12, 18, 19 और 20 (केन्द्रीय), मुम्बई की अधिकारिता के अधीन सभी मामले ।
2. केन्द्रीय रेंज-2, मुम्बई ।	आयकर अधिकारी खण्ड 3, 9, 11, 13, 16 और 22 (केन्द्रीय) मुम्बई की अधिकारिता के अधीन सभी मामले ।
3. केन्द्रीय रेंज-3, मुम्बई ।	आय कर अधिकारी खण्ड 7, 10, 15, 17, 21 और 23 (केन्द्रीय), मुम्बई और केन्द्रीय सक्तिल अहमदाबाद की अधिकारिता के अधीन सभी मामले ।
4. केन्द्रीय रेंज-4, मुम्बई ।	आयकर अधिकारी खण्ड-5, 6 और 14 (केन्द्रीय ), मुम्बई और केन्द्रीय सक्तिलें 2 और 5 नागपुर की अधिकारिता के अधीन सभी मामले ।
5. केन्द्रीय रेंज, नागपुर ।	आयकर अधिकारी केन्द्रीय सक्तिलें 1, 3 और 4 नागपुर की अधिकारिता के अधीन सभी मामले ।

जहाँ कोई आयकर सर्किल वार्ड या जिला या उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से दूसरी रेंज को अन्तरित हो गया है। वहाँ उस आय कर सर्किल वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में निर्धारणों से उद्भूत आयों जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित थी जिससे वह आयकर सर्किल, या वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सर्किल वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तरित कर दिया गया है सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तरित कर दी जाएगी और उनके सम्बन्ध में कार्यवाही उसी के द्वारा की जाएगी।

यह अधिसूचना 5 अगस्त, 1970 से प्रभावी होगी।

[सं० 139 (फा० सं० 261/14/70 आई० टी० जे०)]

*New Delhi, the 18th August, 1970*

**S.O. 198.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income tax Act, 1961, (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in modification of Notification No. 155-F. No. 50/34/69-ITJ dated 21-11-1969, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column 1 of the schedule below, shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to income-tax or super-tax, or wealth tax or gift tax or expenditure tax, in the Income-tax Circles, wards and districts specified in the corresponding entry in column 2 thereof, excepting those that have been specifically allotted to the Appellate Controller of Estate Duty, Hyderabad by notification No. 83(261/17/70-ITJ) dated the 20th May, 1970.

#### SCHEDULE

Ranges	Income-tax Circle, ward and District.
Vijayawada Range	1. Vijayawada Circle excluding A-ward, Vijayawada Circle. 2. Rajahmundry. 3. Palacole. 4. Tanuku. 5. Eluru.
Guntur Range	1. Guntur. 2. Bapatla. 3. Tenali. 4. Nellore. 5. Mica Circle, Nellore. 6. Machilipatam. 7. Gudivada. 8. A-Ward, Vijayawada.

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range from whom the Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall, from the date this Notification shall take effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 1st August, 1970.

*Explanatory Note*

The amendments have become necessary on account of the re-distribution of the jurisdiction of the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax, Vijayawada and Guntur in the charge of Andhra Pradesh.

(This note does not form a part of the Notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 140 (F. No. 261/17/70-ITJ(1).]

नई दिल्ली, 18 अगस्त 1970

एन० ओ० 198-आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं० 155 फा० सं० 50/34/69-आई टी जें तारीख 21-11-1969 का उपान्तरण करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेंज के सहायक आयकर आयुक्त (अपील) उन सभी व्यक्तियों के और आयों के सम्बन्ध में अपने कृत्यों का पालन करेंगे जो उसके स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टी में विनिर्दिष्ट आयकर सकिलों, वार्डों और जिलों में आयकर या अधिकर या धनकर या दानकर या व्ययकर के लिए निर्धारित हुए हैं सिवाय उनके जो कि अधिसूचना सं० 73 (261/17/80-आई टी जें) तारीख 20 मई, 1970 द्वारा सम्मोदा शुल्क नियन्त्रक (अपील) हैदराबाद को विनिर्दिष्ट है।

**अनुसूची**

रेंज	आय कर सकिल, वार्ड और जिला
विजयवाड़ा रेंज	<ol style="list-style-type: none"> <li>विजयवाड़ा सकिल के क्वार्टर को अपवर्जित करते हुए विजयवाड़ा सकिल ।</li> <li>राज मुन्वरी ।</li> <li>पाला कोल ।</li> <li>तनूक ।</li> <li>एलरु ।</li> </ol>
गुन्टूर रेंज	<ol style="list-style-type: none"> <li>गुन्टूर</li> <li>बापाटला ।</li> <li>तेनाली ।</li> <li>नैलोर ।</li> <li>अभ्रक सकिल, नैलोर ।</li> <li>मछलीपट्टन ।</li> <li>गुडीवाड़ा ।</li> <li>क---वार्ड, विजयवाड़ा ।</li> </ol>

जहां कोई आय कर सकिल वार्ड या जिला या उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से दूसरे रेंज में अन्तर्गत हो गया है वहां उस आय कर सकिल, वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में निर्धारणों से उद्भूत अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख ठीक पहले उस रेंज के सहायक आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित थी जिससे वह आयकर सकिल वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत किया गया है, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सकिल वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील)

को अन्तर्गत कर दी जायेगी और उनके सम्बन्ध में कार्यवाही उस सहायक आयुक्त (अपील) द्वारा की जायेगी ।

यह अधिसूचना 1 अगस्त 1970 से प्रभावी होगी ।

[सं० 140 (फा० सं० 261/17/70-आई० टी० जे०)]

**S.O. 199.**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment in the Schedule appended to its Notification No. 60 (F. No. 261/9/70-ITJ), dated 28th April, 1970, namely:—

In the said Schedule against Gauhati Range, Gauhati, the following shall substituted under column 2:—

1. Gauhati Circle.
2. Nalbari Circle.

This notification shall take effect from 18th August, 1970.

#### *Explanatory Note*

The amendment has become necessary on account of the creation of a new Income-tax circle at Nalbari.

(The above note does not form part of the notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 141 (F. No. 261/9/70-ITJ.)]

एस० ओ० 199:—आय कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा अपनी अधिसूचना सं० 60 (फा० सं० 261/9/70-आई० टी० जे०) तारीख 28 अप्रैल 1970 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में गोहाटी रेंज, गोहाटी के सामने स्तम्भ 2 के नीचे निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

1. गोहाटी सर्किल ।
2. नलबाड़ी सर्किल ।

यह अधिसूचना 18 अगस्त 1970 से प्रभावी होगी ।

[सं० 141 (फा० सं० 261/9/70-आई० टी० जे०)]

*New Delhi, the 28th October 1970*

**S.O. 200.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment in the Schedule appended to its Notification No. 34 (F. No. 261/8/70-ITJ) dated 25th March, 1970 and No. 45 (File No. 261/8/70-ITJ) dated 31st March, 1970, viz.

“Against ‘Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Amravati, Range, Amravati under Column No. 2, the following shall be substituted:

1. A-Ward, Amravati.
2. C-Ward, Amravati.
3. E-Ward, Amravati.

4. A-Ward, Wardha.
5. B-Ward, Wardha.
6. A-Ward, Chandrapur.
7. B-Ward, Chandrapur.

This notification takes effect from 25th October, 1970.

*Explanatory Note*

The amendment has become necessary on account of abolition of the charges of the Income-tax Officers C-Ward, Wardha and D-Ward, Wardha and on account of creation of two new charges of Income-tax Officers, A-Ward, Chandrapur and B-Ward, Chandrapur in the Commissioner's charge.

(This note does not form a part of the Notification, but is intended to be merely clarificatory).

[No. 178(261/8/70-ITJ.)]

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर 1970

ए० प्रो० 200—आय कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त अपने को समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा अपनी अधिसूचना सं० 34 (फाइल सं० 261/8/70—आ० टी० जे०) तारीख 25-3-1970 और सं० 45 (फा० सं० 261/8/70—आई० टी० जे०) तारीख 31-3-1970 से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

स्तम्भ सं० 2 के नीचे सहायक आयकर आयुक्त (अपील) अमरावती, रेंज अमरावती के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

1. क-वार्ड, अमरावती
2. ग-वार्ड, अमरावती
3. ग-वार्ड, अमरावती
4. क-वार्ड, बाधा
5. ख-वार्ड, बाधा
6. क-वार्ड, चन्द्रपुर
7. ख-वार्ड, चन्द्रपुर

**स्पष्टीकरण टिप्पण**

यह संशोधन आयुक्त के भारसाधन में आय कर अधिकारी ग—वार्ड, बाधा और घ—वार्ड, बाधा के भारसाधनों के उत्पादन के कारण और आय कर अधिकारी क—वार्ड चन्द्रपुर और ख—वार्ड चन्द्रपुर के दो नये भारसाधनों के बन जाने के कारण आवश्यक हो गया है।

यह टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है किन्तु केवल स्पष्टीकरण के लिये आशयित है।

[सं० 178 (261/8/70—आई० टी० जे०)]

New Delhi, the 20th November 1970

**S.O. 201.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the Schedule appended to its Notification No. 56 (F. No. 261/13/70-ITJ) dated the 23rd April, 1970, namely:

1. Against B-Range, Bombay under column 2 the following shall be deleted.  
Film Circle.
2. Against C-Range, Bombay under column 2 the following shall be deleted:  
A-IV Ward.

Against C-Range, Bombay under column 2 the following shall be added:  
Film Circle, Salaries Branch I and Bombay Refund Circle.

3. Against R-Range, Bombay, under column 2 the following shall be deleted:  
Salaries Branch I and Bombay Refund Circle.

Against R-Range, Bombay under column 2 the following shall be added:  
A-IV Ward.

4. Against N-Range, Bombay under column 2 the following shall be added:  
X-Ward.

5. Against S-Range, Bombay under column 2 the following shall be deleted:  
X-Ward.

This notification shall take effect from 1st December, 1970.

#### Explanatory Note

The amendment has become necessary on account of the creation of a new Range of A.A.C. known as A.A.C., Central Range IV, Bombay and redistribution of work amongst the A.A.Cs.

(The above note doesnot form a part of the notification, but is intended to be merely clarificatory).

[No. 182 F. No. 261/13/70-ITJ.]

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1970

एस० ओ० 201.—आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) [की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त अपने को समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा अपनी अधिसूचना सं० 56 (फा० सं० 261/13/70—आई० टी० जे०) तारीख 23 अप्रैल, 1970 से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. ख—रेंज, मुम्बई के सामने स्तम्भ 2 में निम्नलिखित लुप्त किया जायेगा  
फिल्म सर्किल ।

2. ग—रेंज, मुम्बई के सामने स्तम्भ 2 में निम्नलिखित लुप्त किया जायेगा  
क—IV वार्ड ।

ग—रेंज, मुम्बई के सामने स्तम्भ 2 में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा :—  
फिल्म सर्किल, वेतन शाखा I मुम्बई वापसी सर्किल ।

3. द—रेंज, मुम्बई के सामने स्तम्भ 2 में निम्नलिखित लुप्त किया जायेगा :—  
वेतन शाखा I और मुम्बई वापसी सर्किल ।

द—रेंज, मुम्बई के सामने स्तम्भ 2 में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा :—  
क—IV वार्ड ।

4. ङ—रेंज, मुम्बई के सामने स्तम्भ 2 में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा :—  
भ—वार्ड

5. ध—रेंज, मुम्बई के सामने स्तम्भ 2 में निम्नलिखित लुप्त किया जायेगा :—  
भ—वार्ड

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1970 से प्रभावी होगी ।

#### स्पष्टीकरण टिप्पण

यह संशोधन सहायक आयुक्तों (अपील) के बीच कार्य का पुनर्व्यवस्थित होने के कारण आवश्यक हो गया है ।

(उक्त टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है किन्तु केवल स्पष्टीकरण के लिये आशयित है) ।

[फो 182 (फो सं 261/13/70—आई० टी० जे०)]

**S.O. 202.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all the previous notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Range specified in column 1 of the Schedule below, shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column 2 thereof :

SCHEDULE

Range:	Income-tax Circles, Wards and Districts.
1	2
Poona Range-I, Poona . . . . .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. B-Ward, Poona.</li> <li>2. D-Ward, Poona.</li> <li>3. Addl. D-Ward, Poona.</li> <li>4. G-Ward, Poona.</li> <li>5. Addl. G-Ward, Poona.</li> <li>6. C-Ward, Poona.</li> <li>7. Addl. C-Ward, Poona.</li> <li>8. Wealth-tax Circle, Poona.</li> <li>9. Special Investigation Circle, Poona.</li> <li>10. K-Ward, Poona.</li> <li>11. Collection-I, Poona.</li> <li>12. Collection-II, Poona.</li> <li>13. L-Ward, Poona.</li> <li>14. M-Ward, Poona.</li> </ol>
Poona Range-II, Poona . . . . .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A-Ward, Poona.</li> <li>2. Addl. A-Ward, Poona.</li> <li>3. Central Circle, Poona.</li> <li>4. Companies Circle, Poona.</li> <li>5. Addl. Companies Circle, Poona.</li> <li>6. E-Ward, Poona.</li> <li>7. Addl. E-Ward, Poona.</li> <li>8. F-Ward, Poona.</li> <li>9. Addl. F-Ward, Poona.</li> <li>10. H-Ward, Poona.</li> <li>11. J-Ward, Poona.</li> <li>12. Addl. J-Ward, Poona.</li> </ol>
Kolhapur Range, Kolhapur . . . . .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A-Ward, Kolhapur.</li> <li>2. B-Ward, Kolhapur.</li> <li>3. C-Ward, Kolhapur.</li> <li>4. D-Ward, Kolhapur.</li> <li>5. E-Ward, Kolhapur.</li> <li>6. F-Ward, Kolhapur.</li> <li>7. G-Ward, Kolhapur.</li> <li>8. H-Ward, Kolhapur.</li> <li>9. Collection Circle, Kolhapur.</li> <li>10. Ratragiri.</li> <li>11. A-Ward, Satara.</li> <li>12. B-Ward, Satara.</li> <li>13. C-Ward, Satara.</li> <li>14. A-Ward, Sangli.</li> <li>15. D-Ward, Sangli.</li> <li>16. C-Ward, Sangli.</li> <li>17. D-Ward, Sangli.</li> </ol>

1	2
Nasik Range, Nasik.	1. A-Ward, Nasik. 2. B-Ward, Nasik. 3. C-Ward, Nasik. 4. D-Ward, Nasik. 5. E-Ward, Nasik. 6. F-Ward, Nasik. 7. Collection Circle, Nasik. 8. A-Ward, Malegaon. 9. B-Ward, Malegaon. 10. A-Ward, Dhulia. 11. B-Ward, Dhulia. 12. C-Ward, Dhulia. 13. A-Ward, Jalgaon. 14. B-Ward, Jalgaon. 15. C-Ward, Jalgaon. 16. D-Ward, Jalgaon.
Sholapur Range, Sholapur	1. A-Ward, Sholapur. 2. B-Ward, Sholapur. 3. C-Ward, Sholapur. 4. D-Ward, Sholapur. 5. E-Ward, Sholapur. 6. Income-tax Circle, Barsi. 7. A-Ward, Ahmednagar. 8. B-Ward, Ahmednagar. 9. C-Ward, Ahmednagar.
Thana Range, Thana.	1. A-Ward, Thana. 2. Addl. A-Ward, Thana. 3. B-Ward, Thana. 4. C-Ward, Thana. 5. D-Ward, Thana. 6. E-Ward, Thana. 7. F-Ward, Thana. 8. G-Ward, Thana. 9. H-Ward, Thana. 10. J-Ward, Thana. 11. Collection Circle-I, Thana. 12. Collection Circle-II, Thana. 13. Special Survey Circle, Thana. 14. Addl. Special Survey Circle, Thana. 15. Recovery Circle-III, Thana. 16. Palghar. 17. A-Ward, Panvel. 18. B-Ward, Panvel. 19. C-Ward, Panvel. 20. Special Survey Circle, Poona. 21. Addl. Special Survey Circle, Poona. 22. Salaries and Refunds Circle, Poona. 23. G.H.Q., Income-tax Circle, Poona.

When an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range from whom that Income-Tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall, from the date this notification shall take effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

The notification shall take effect from 1-12-1970.

*Explanatory Note.*

The amendments have become necessary on account of re-allocation of work amongst the Appellate Assistant Commissioners in the Commissioner's charge.

(This note does not form a part of the notification, but is intended to be merely clarificatory).



**एस० नो० 202**—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त अपने को समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों और इस सम्बन्ध में सभी पूर्ववर्ती उपांतरों को अधिकांत करते हुये, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आय कर आयुक्त (अपील) उन सभी व्यक्तियों और आय कर के सम्बन्ध में अपने कृत्यों का पालन करेंगे जो स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आय कर सर्किलों, वार्डों और जिलों में आय कर या अधिक कर के लिये निर्धारित हुये हैं।

### अनुसूची

रेंज

आयकर सर्किल, वार्ड और जिले

#### 1. पूना रेंज—I, पूना

1. ख—वार्ड, पूना।
2. घ—वार्ड, पूना।
3. अतिरिक्त घ—वार्ड, पूना।
4. छ—वार्ड, पूना।
5. अतिरिक्त छ—वार्ड पूना।
6. ग—वार्ड, पूना।
7. अतिरिक्त ग—वार्ड, पूना।
8. धन-कर सर्किल, पूना।
9. विशेष अन्वेषण सर्किल, पूना।
10. ट—वार्ड, पूना।
11. संग्रहण—I, पूना।
12. संग्रहण—II, पूना।
13. ठ—वार्ड, पूना।
14. ड—वार्ड, पूना।

#### पूना रेंज—II, पूना

1. क—वार्ड, पूना।
2. अतिरिक्त क—वार्ड, पूना।
3. केन्द्रीय सर्किल, पूना।
4. कम्पनी सर्किल, पूना।
5. अतिरिक्त कम्पनी सर्किल, पूना।
6. ड—वार्ड, पूना।
7. अतिरिक्त ड—वार्ड, पूना।
8. च—वार्ड, पूना।
9. अतिरिक्त च—वार्ड, पूना।
10. ज—वार्ड, पूना।
11. झ—वार्ड, पूना।
12. अतिरिक्त झ—वार्ड, पूना।

1

2

कोल्हापुर रेंज, कोल्हापुर

1. क-वार्ड, कोल्हापुर ।
2. ख-वार्ड, कोल्हापुर ।
3. ग-वार्ड, कोल्हापुर ।
4. घ-वार्ड, कोल्हापुर ।
5. ङ-वार्ड, कोल्हापुर ।
6. च-वार्ड, कोल्हापुर ।
7. छ-वार्ड, कोल्हापुर ।
8. ज-वार्ड, कोल्हापुर ।
9. संग्रहण सर्किल, कोल्हापुर ।
10. रतनगिरि ।
11. क-वार्ड, सतारा ।
12. ख-वार्ड, सतारा ।
13. ग-वार्ड, सतारा ।
14. क-वार्ड, सांगली ।
15. ख-वार्ड, सांगली ।
16. ग-वार्ड, सांगली ।
17. घ-वार्ड, सांगली ।

नासिक रेंज, नासिक

1. क-वार्ड, नासिक ।
2. ख-वार्ड, नासिक ।
3. ग-वार्ड, नासिक ।
4. घ-रेंज वार्ड, नासिक ।
5. ङ-वार्ड, नासिक ।
6. च-वार्ड, नासिक ।
7. संग्रहण सर्किल, नासिक ।
8. क-वार्ड, मेलगांव ।
9. ख-वार्ड, मेलगांव ।
10. ग-वार्ड, धूलिया ।
11. ख-वार्ड, धूलिया ।
12. ग-वार्ड, धूलिया ।
13. क-वार्ड, जलगांव ।
14. ख-वार्ड, जलगांव ।
15. ग-वार्ड, जलगांव ।
16. घ-वार्ड, जलगांव ।

सोलापुर रेंज, सोलापुर

1. क-वार्ड, सोलापुर ।
2. ख-वार्ड, सोलापुर ।
3. ग-वार्ड, सोलापुर ।
4. घ-वार्ड, सोलापुर ।

1

2

थानारेंज, थाना

5. ड-वार्ड, सोलापुर ।
6. आयकर सिकिल, बर्सी ।
7. क-वार्ड, अहमदनगर ।
8. ख-वार्ड, अहमदनगर ।
9. ग-वार्ड, अहमदनगर ।
1. क-वार्ड, थाना ।
2. अतिरिक्त क-वार्ड, थाना ।
3. ख-वार्ड, थाना ।
4. ग-वार्ड, थाना ।
5. घ-वार्ड, थाना ।
6. ङ-वार्ड, थाना ।
7. च-वार्ड, थाना ।
8. छ-वार्ड, थाना ।
9. ज-वार्ड, थाना ।
10. ञ-वार्ड, थाना ।
11. संग्रहण सिकिल-I, थाना ।
12. संग्रहण सिकिल-II, थाना ।
13. विशेष सर्वे सिकिल, थाना ।
14. अतिरिक्त विशेष सर्वे सिकिल, थाना ।
15. वसूली सिकिल-III, थाना ।
16. पालघर ।
17. क-वार्ड, पनवेल ।
18. ख-वार्ड, पनवेल ।
19. ग-वार्ड, पनवेल ।
20. विशेष सर्वे, पनवेल ।
21. अतिरिक्त विशेष सर्वे सिकिल, पूना ।
22. वेतन एवं रिफण्ड सिकिल, पूना ।
23. जी० एच० क्यू०, आय-कर सिकिल, पूना ।

जहाँ इस अधिसूचना द्वारा कोई आय-कर सिकिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरे रेंज में अन्तरित हो गया है वहाँ उस आय-कर सिकिल, वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में निष्पारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के सहायक आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित थी जिससे वह आय-कर सिकिल वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सिकिल वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तरित कर दी जायेंगी और उनके सम्बन्ध में कार्यवाही उस सहायक आयुक्त (अपील) द्वारा की जाएगी ।

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1970 से प्रभावी होगी ।

## स्पर्शोत्तरण टिप्पण

ये संशोधन आयुक्त के भार साधन में सहायक आयुक्त (अपील) के बीच कार्य का पुन-अविन्दन होने के कारण आवश्यक हो गये हैं ।

(यह टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है किन्तु केवल स्पष्टीकरण के लिये प्राणयित है ।)

[सं० 183 (261/8/70—आई० टी० जे०)]

*New Delhi, the 23rd November, 1970*

**S.O. 203.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1951) and all other powers enabling it in that behalf and in modification of Notification No. 155 (F.No. 50/34/69-ITJ) dated 21st Nov. 1969 and No. 140 (F. No. 261/17/70-ITJ) dated 1st August, 1970, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column 1 of the schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or super-tax or wealth-tax or Gift tax or Expenditure tax, in the Income-tax circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column 2 thereof, excepting those that have been specifically allotted to the Appellate Controller of Estate Duty, Hyderabad by Notification No. 83 (261/17/70-ITJ) dated the 20th May, 1970.

## SCHEDULE

Ranges	Income-tax Circle, Ward & District
1. A-Range, Hyderabad	1. Circle-I, Hyderabad. 2. Ward -IA, Hyderabad Circle, Hyderabad. 3. Ward-I B, Hyderabad Circle, Hyderabad. 4. Ward I-C, Hyderabad Circle, Hyderabad. 5. Ward I-D, Hyderabad Circle, Hyderabad. 6. Ward I-E, Hyderabad Circle, Hyderabad. 7. Circle-I (Old) Hyderabad. 8. A-Ward, Hyderabad. 9. I.T. Cum-W.T. Circle I, Hyderabad. 10. Salary Circle, Hyderabad. 11. Special Circle, Hyderabad. 12. Karimnagar. 13. Khammam. 14. Nizamabad.
2. B-Range, Hyderabad	1. Circle-II, Hyderabad. 2. Warangal. 3. Ward-II-A, Hyderabad Circle, Hyderabad. 4. Ward-II-B, Hyderabad Circle, Hyderabad. 5. Ward-II,BB, Hyderabad Circle, Hyderabad. 6. Ward-II-C, Hyderabad Circle, Hyderabad. 7. Ward-II-D, Hyderabad Circle, Hyderabad. 8. Ward-II-DD, Hyderabad Circle, Hyderabad. 9. Ward-II-E, Hyderabad Circle, Hyderabad. 10. Ward-II-EE, Hyderabad Circle, Hyderabad. 11. Circle II (Old) Hyderabad. 12. B-Ward, Hyderabad. 13. I.T. Cum-W.T. Circle-II, Hyderabad. 14. Special Survey Circle (Old), Hyderabad. 15. Special Survey Circle-I, Hyderabad. 16. Special Survey Circle-II, Hyderabad. 17. Survey Circle I, Hyderabad. 18. Survey Circle-II, Hyderabad. 19. Survey Circle, Hyderabad. 20. Sangareddy.

1

2

- |  |  |
|--|--|
| 3. C-Range, Hyderabad                  | 1. Circle-III, Hyderabad.<br>2. Company Ward of Secunderabad Circle, Hyderabad.<br>3. Company Circle, Hyderabad.<br>4. Company Circle (Old), Hyderabad.<br>5. Ward III-A, Secunderabad Circle, Hyderabad.<br>6. Ward III-B, Secunderabad Circle, Hyderabad.<br>7. Ward III-C, Secunderabad Circle, Hyderabad.<br>8. Ward III-D, Secunderabad Circle, Hyderabad.<br>9. Ward III-E, Secunderabad Circle, Hyderabad.<br>10. Circle III (Old), Hyderabad.<br>11. C Ward, Hyderabad.<br>12. I.T. Cum--W.T. Circle-III, Hyderabad.<br>13. Central Circle, Hyderabad.<br>14. Central Circle (Old) Hyderabad.<br>15. Mahaboobnagar.<br>16. Kothagudem.<br>17. Nirmal.<br>18. Recovery Circle, Hyderabad.<br>19. Project Circle, Hyderabad.<br>20. M.P. P. Circle, Hyderabad. |
| 4. Visakhapatnam Range, Visakhapatnam. | 1. Visakhapatnam.<br>2. Vizianagaram.<br>3. Srikakulam.<br>4. Bobbili.<br>5. Anakapalli.<br>6. Circle-I, Kakinada.<br>7. Circle-II, Kakinada.<br>8. Ramachandrapuram (Old).<br>9. Kakinada (Old).<br>10. Amalapuram.<br>11. Rajahmundry.<br>12. Palacole.  |
| 5. Vijayawada Range, Vijayawada        | 1. Vijayawada Circle, excluding A-Ward, Vijayawada Circle.<br>2. Tanuku.<br>3. Eluru.<br>4. Machilipatam.<br>5. Gudivada.  |
| 6. Guntur Range, Guntur.               | 1. Guntur.<br>2. Bapatla.<br>3. Tenali.<br>4. Nellore.<br>5. Mica Circle, Nellore.<br>6. A-Ward, Vijayawada.<br>7. Kurnool.  |
| 7. Anantapur Range, Anantapur          | 1. Anantapur.<br>2. Hindupur.<br>3. Adoni.<br>4. Cuddapah.<br>5. Proddutur.<br>6. Chittoor.<br>7. Tirupathi.<br>8. Nandyal.  |

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range from whom the Income-tax Circle Ward or District or part thereof is transferred shall, from the date this notification shall take effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 1st December, 1970.

*Explanatory Note*

The amendments have become necessary on account of the re-allocation of jurisdiction of the Appellate Assistant Commissioners in the charges of Andhra Pradesh I & II.

(This note does not form a part of the Notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 185 F. No. (261/17/70-ITJ)]

नई दिल्ली, 23, नवम्बर, 1970

**एस० ओ० 203.—**प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त अपने को समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं० 155 (फा० सं० 50/34/69—आई०टी०जे०) तारीख 21-11-1969 और सं० 140 (फा० सं० 261/17/70—आई०टी०जे०) तारीख 1 अगस्त, 1970 के उपांतरण में, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आमुक्त (अपील) उन सभी व्यक्तियों और आयकर के संबंध में सिवाय उनके जो विनिर्दिष्ट सहायक सम्पदा शुल्क नियंत्रक हैदराबाद की अधिसूचना सं० 83 (261/17/70—आई०टी०जे०) तारीख 20 मई, 1970 द्वारा आबंटित किए गए हैं, अपने कृत्यों का पालन करेंगे जो स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सफिलों, वार्डों और जिलों में आयकर या अधिकर या धन या धनकर या व्ययकर के लिए निर्धारित हुए हैं।

**अनुसूची****रेंज****आयकर सफिल, वार्ड और जिले**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. क—रेंज, हैदराबाद  | 1. सफिल—1, हैदराबाद।                    |
|                      | 2. वार्ड 1—क, हैदराबाद सफिल, हैदराबाद।  |
|                      | 3. वार्ड 1—ख, हैदराबाद सफिल, हैदराबाद।  |
|                      | 4. वार्ड 1—ग, हैदराबाद सफिल, हैदराबाद।  |
|                      | 5. वार्ड 1—घ, हैदराबाद सफिल, हैदराबाद।  |
|                      | 6. वार्ड 1—ङ, हैदराबाद सफिल, हैदराबाद।  |
|                      | 7. सफिल—1 (पुराना) हैदराबाद।            |
|                      | 8. क—वार्ड, हैदराबाद।                   |
|                      | 9. आयकर एंश—धनकर सफिल—1, हैदराबाद।      |
|                      | 10. बेतन सफिल, हैदराबाद।                |
|                      | 11. विशेष सफिल, हैदराबाद।               |
|                      | 12. करीम नगर।                           |
|                      | 13. खम्माम।                             |
|                      | 14. निजामाबाद।                          |
| 2. ख—रेंज, हैदराबाद। | 1. सफिल—II हैदराबाद।                    |
|                      | 2. वारंगल I                             |
|                      | 3. वार्ड II—क, हैदराबाद सफिल, हैदराबाद। |
|                      | 4. वार्ड II—ख, हैदराबाद सफिल, हैदराबाद। |

5. वार्ड II-ख, हैदराबाद सिकिल, हैदराबाद ।
6. वार्ड II-ग, हैदराबाद सिकिल, हैदराबाद ।
7. वार्ड II-घ, हैदराबाद सिकिल, हैदराबाद ।
8. वार्ड II-घव, हैदराबाद सिकिल, हैदराबाद ।
9. वार्ड II-ङ हैदराबाद सिकिल, हैदराबाद ।
10. वार्ड II-ड ड, हैदराबाद सिकिल, हैदराबाद ।
11. सिकिल II-(पुराना) हैदराबाद ।
12. ख-वार्ड, हैदराबाद ।
13. आयकर एवं-धनकर सिकिल-II, हैदराबाद ।
14. विशेष सर्वेक्षण सिकिल, (पुराना), हैदराबाद ।
15. विशेष सर्वेक्षण सिकिल-I, हैदराबाद ।
16. विशेष सर्वेक्षण सिकिल-II, हैदराबाद ।
17. सर्वेक्षण सिकिल I, हैदराबाद ।
18. सर्वेक्षण सिकिल-II हैदराबाद ।
19. सर्वेक्षण सिकिल, हैदराबाद ।
20. संगरेड्डी ।

3. ग-रेंज, हैदराबाद ।

1. सिकिल III, हैदराबाद ।
2. सिकन्दराबाद सिकिल का कम्पनी वार्ड, हैदराबाद ।
3. कम्पनी सिकिल, हैदराबाद ।
4. कम्पनी सिकिल (पुराना), हैदराबाद ।
5. वार्ड III-क, सिकन्दराबाद सिकिल, हैदराबाद ।
6. वार्ड III-ख, सिकन्दराबाद सिकिल, हैदराबाद ।
7. वार्ड III-ग, सिकन्दराबाद सिकिल, हैदराबाद ।
8. वार्ड III-घ, सिकन्दराबाद सिकिल, हैदराबाद ।
9. वार्ड III-ड०, सिकन्दराबाद सिकिल, हैदराबाद ।
10. सिकिल III(पुराना), हैदराबाद ।
11. ग, वार्ड-हैदराबाद ।
12. आयकर एवं-धनकर सिकिल-III, हैदराबाद ।
13. केन्द्रीय सिकिल, हैदराबाद ।
14. केन्द्रीय सिकिल (पुराना), हैदराबाद ।
15. महबूबनगर ।
16. काठगोदाम ।
17. निर्मल ।
18. बसुली सिकिल, हैदराबाद ।
19. परियोजना सिकिल, हैदराबाद ।
20. एम० पो० सी० सिकिल, हैदराबाद ।

1	2
4. विशाखापट्टणम् रेंज विशाखापट्टणम्	1. विशाखापट्टणम् । 2. विजयनगरम् । 3. श्रोककुलम् । 4. बोम्बिलो । 5. अनाकापल्ली । 6. सर्किल—I, काकीनाडा । 7. सर्किल—II, काकीनाडा । 8. रामाचन्द्रापुरम् (पुराना) । 9. काकीनाडा (पुराना) । 10. अमलपुरम् । 11. राजमुन्दरी । 12. पेनाकोल
5. विजयवाड़ा रेंज विजयवाड़ा	विजयवाड़ा सर्किल, क-वार्ड विजयवाड़ा सर्किल को अपवर्जित करके । 2. तानकू । 3. एलरू । 4. मछनोपट्टम । 5. गुडोवाड़ा ।
6. गुन्तूर रेंज, गुन्तूर	1. गुन्तूर । 2. बस्ताला । 3. तेनाली । 4. नेलौर । 5. माइहा सर्किल, नेलौर । 6. क-वार्ड, विजयवाड़ा । 7. कुरुनूल ।
7. अनन्तपुर रेंज, अनन्तपुर	1. अनन्तपुर । 2. हिन्दुपुर । 3. अदोनी । 4. कुड्डाथा । 5. चित्तौर । 6. तिष्ठति । 7. नन्दयाल ।

जहाँ इस अधिसूचना द्वारा कोई आयकर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरे रेंज में अन्तर्गत हो गया हो वहाँ उस आयकर सर्किल, वार्ड या जिला या उसके किसी भाग में निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के सहायक आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित थी जिससे वह आयकर सर्किल,



वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तर्गत कर दी जायेंगी और उनके सम्बन्ध में कार्यवाही उस सहायक आयुक्त (अपील) द्वारा की जाएगी।

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1970 से प्रभावी होगी।

#### स्पष्टीकरण टिप्पण

यह संशोधन आन्ध्र प्रदेश के सहायक आयुक्त (अपील) के भार साधन में अधिकारिता का पुनर्निर्माण होने के कारण आवश्यक हो गया है।

(यह टिप्पण अधिसूचना का अंग नहीं है किन्तु केवल स्पष्टीकरण के लिये आशयित है)।

[सं० 185(फा० सं० 261/17/70-आई० टी० जे०)]

*New Delhi, the 26th November 1970*

**S.O. 204.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the Schedule appended to its notification No. 66(F. No. 261/3/70-ITJ) dated 10th May, 1970.

In the said Schedule against Bikaner Range, Bikaner under Column 2 the following shall be added namely:—

“4—Income-tax Wards and Circles at Hanumangarh”.

This Notification shall take effect from 2nd December, 1970.

#### Explanatory Note

The amendment has become necessary on account of creation of new Wards of Income-tax known as A-Ward and B-Ward, Hanumangarh.

(The above note does not form part of the Notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 191 (F. No. 261/3/70-ITJ.)]

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1970

**एस० नो० 204—** आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा अपनी अधिसूचना सं 66(फा० सं० 261/3/70-आई० टी० जे०) तारीख 10-5-70 से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है:—

उक्त अनुसूची में बीकानेर रेंज, बीकानेर के सामने स्तम्भ 2 में निम्नलिखित जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्:—

“4—हनुमानगढ़ में आयकर वार्ड और सर्किल”

यह अधिसूचना 2-12-1970 से प्रवृत्त होगी।

#### स्पष्टीकरण टिप्पण

यह संशोधन आयकर के नये वार्ड, जो क-वार्ड और ख-वार्ड हनुमानगढ़ के नाम से जाने जाते हैं, के बन जाने के कारण आवश्यक हो गया है।

(उपरोक्त टिप्पण अधिसूचना का अंग नहीं है किन्तु केवल स्पष्टीकरण के लिये आशयित है।)

[सं० 191 (फा० सं० 261/3/70-आई० टी० जे०)]

**S.O. 205.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in super-session of all the previous notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes, hereby directs that the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Ranges specified in Column 1 of the Schedule below, shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to income-tax or super-tax in the income-tax Circles, Wards and District specified in the corresponding entry in Column 2 thereof :—

#### SCHEDULE

Ranges	Income-tax Circles, Wards and Districts
'C' Range, New Delhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Central Circles-I, II, III, VI, VII and XI, New Delhi.</li> <li>2. Spl. Inv. Circles-A, B &amp; C, New Delhi.</li> <li>3. Central Circle-III, IV &amp; V, Kanpur.</li> </ol>
Range-III, Meerut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Central Circles-I, II, III and IV, Meerut.</li> </ol>

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall, from the date this notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 2-12-1970.

#### Explanatory Note

The amendment has become necessary on account of reallocation of work amongst the Appellate Assistant Commissioners.

(This note does not form a part of the notification, but is intended to be merely clarificatory).

[No. 192 F. No. 261/4/70-ITJ].

Y. SINGH, Under Secy.

**एस० ओ० 205.**—प्राय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये और इस बाबत सभी पूर्वतन अधिसूचनाओं को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयुक्त (अपील) उन सभी व्यक्तियों के और उस आय के सम्बन्ध में अपने कृत्यों का पालन करेंगे जो उस अनुसूची के स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्राय कर सिकिलों, वार्डों और जिलों में प्राय कर या अधिकार के लिये निर्धारित हुये हैं :—

#### अनुसूची

रेंज	आयकर सिकिल, वार्ड और जिले
'ग' रेंज नई दिल्ली	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. केन्द्रीय सिकिल—I, II, III, VI और VII, XI नई दिल्ली</li> <li>2. केन्द्रीय अन्वेषण सिकिल—क, ख और ग नई दिल्ली ।</li> <li>3. केन्द्रीय सिकिल—III, IV और V कानपुर ।</li> </ol>
रेंज—III मेरठ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I, II, IIIIV, मेरठ ।</li> </ol>

जहाँ इस अधिसूचना द्वारा कोई आय कर सकिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरे रेंज में अन्तरित हो गया हो वहाँ उसे आय कर सकिल, वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें, जो इस अधिसूचना की ता' ख से ठीक पहले उस रेंज के सहायक आयुक्त (अपीली) के समक्ष लम्बित थी, जिससे वह आय कर सकिल, वार्ड या जिला उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सकिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपीली) को अन्तरित कर दी जायेगी और उनके सम्बन्ध में कार्यवाही उस सहायक आयुक्त द्वारा की जायेगी ।

यह अधिसूचना 2 दिसम्बर, 1970 से प्रभावी होगी ।

### स्पष्टीकरण

यह संशोधन अपीली सहायक आयुक्तों के बीच कार्य का पुनर्वितरण के कारण आवश्यक हो गया है ।

(उपरोक्त टिप्पण अधिसूचना का अंग नहीं है किन्तु केवल स्पष्टीकरण के लिये आशयित है )

[[सं 192 (फा० सं० 261/4/70-आई०टी०जे०]

योगेन्द्र सिंह, अवसर सचिव ।

### ESTATE DUTY

*New Delhi, the 15th December, 1970*

**S.O. 295**—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (2) of Section 4 of the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) and in modification of the notification No. 14/F.No.2155/68-E.D. dated the 29th April, 1958 published as S.O. 1641 in Part II, Section 3(ii) of the Gazette of India dated the 11th May, 1968, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that every Income-Tax Officer appointed to be an Assistant Controller and posted to any of the Estate Duty-cum-Incometax Circles mentioned in Column 2 of the Schedule below shall perform his functions as Assistant Controller in the said circle to the exclusion of all other Assistant Controllers in respect of the estates of all deceased persons, who immediately, before their death, were being or would have been assessed to income tax, had they derived any taxable income in any Incometax Circle the headquarters of which lies within the revenue districts shown as corresponding entries in column 3 of the said Schedule against each of the Estate Duty-cum-Incometax Circles.

### SCHEDULE

Serial No.	Name of the Circle	Jurisdiction in terms of Revenue Districts
1	2	3
1	Estate Duty cum Incometax Circle, Hyderabad.	Revenue districts of Hyderabad, Nalgonda, Karimnagar, Adilabad, Nizamabad, Medak, Warangal, Mahabubnagar, Kurnool, Anantapur, Cuddapah, Khammam and revenue taluks of Markalur, Giddalur of the newly formed Ongole District of the Andhra Pradesh State.
2	Estate Duty cum Incometax Circle, Kakinada.	Revenue Districts of West Godavari, East Godavari, Visakhapatnam, Srikakulam, of the Andhra Pradesh State and the territory of Yanam in the Union territory of Pondicherry.

1

2

3

- 3 Estate Duty cum Income-tax Revenue Districts of Chittoor, Nellore, Guntur, Krishna, Circle, Guntur, and revenue taluks of Kandukur, Podili, Kanigiri, Darsi, Ongole, Addanki & Chirala of the newly formed Ongole District of the Andhra Pradesh State.

2. This Notification shall deemed to have come into force with effect from 2-2-1970.

*Explanatory Note*

(This note does not form a part of the Notification but is intended to be merely clarificatory)

This notification has become necessary on account of creation of new District known as 'Ongole District' comprising taluks which hitherto formed part of Kurnool District, Nellore District and Guntur District, by promulgation of Ordinance No. 1/70 by the Governor of Andhra Pradesh with effect from 2-2-1970.

[No. 20]

**सम्पदा शुल्क**

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1970

एत० क्र० 206—सम्पदा शुल्क अधिनियम 1953 (1953 का 34) की धारा 4 की उपधारा (2) के दूसरे उपबन्ध और 11-5-1968 को भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3(ii) में कानूनी आदेश सं० 1641 के रूप में प्रकाशित अधिसूचना सं० 14/एफ० न० 21/55/68-ई० डी०, दिनांक 29 अप्रैल, 1968 में संशोधन द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मण्डल यह निर्देश देता है कि निम्नलिखित अधिसूची के कालम 2 में उल्लिखित किसी भी सम्पदा शुल्क सह-आयकर अधिकारी कथित सफिल में सहायक नियंत्रक के रूप में नियुक्त प्रत्येक आयकर अधिकारी कथित सफिल में सहायक नियंत्रक के रूप में काम करेगा, लेकिन उन सभी मृत व्यक्तियों से संबंधित अन्य सभी सहायक नियंत्रकों के काम से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होगा, जिनका मृत्यु से तुरन्त पहले आयकर जांचा जा रहा था या जांचा जाने वाला था, चाहे उन्होंने किसी भी आयकर सफिल में आयकर-योग्य धन पैदा किया हो और जिसका मुख्यालय उन राजस्व जिलों के अन्तर्गत आता हो, जो प्रत्येक सम्पदा शुल्क-सह-आयकर सफिलों के सामने कथित अनुसूची के कालम 3 में दिखाए गए हैं।

**अनुसूची**

क्रम सं० सफिल का नाम

राजस्व जिलों के रूप में अधिकार क्षेत्र

1. सम्पदा-शुल्क-सह आयकर सफिल, हैदराबाद। हैदराबाद, नालगोंडा, करीमनगर, अदीलाबाद, निजामाबाद, मेदक, वारंगल, महबूबनगर, कुर्नूल, अनंतपुर, कुड्डापाह, छम्माम के राजस्व जिले और आन्ध्र प्रदेश में नवनिर्मित ओंगोल जिले के बरकापुर व गिड्डालूर राजस्व तालुक।

1

2

3

2. सम्पदा-शुल्क-सह-आयकर सर्किल, काकी-नाड आंध्रप्रदेश राज्य के दक्षिणी गोदावरी, पूर्वी, गोदावरी, विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम, राजस्व जिले और केंद्रशासित प्रदेश पार्श्व-वेरी का यानम क्षेत्र ।
3. सम्पदा शुल्क सह आयकर सर्किल, गुण्टूर चित्तूर, नेल्लोर, गुण्टूर, कुणम राजस्व जिले और आंध्र प्रदेश राज्य में नवनिर्मित श्री गोल जिले के कन्डूर, पोडीसी, कनीगिरि, दारसी, श्रीगोल, अड्डजनकी और चिराला राजस्व तालुक ।

यह अधिसूचना 2-2-1970 से प्रमल में समझी जायगी ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

(यह टिप्पणी अधिसूचना का अंग नहीं है, बल्कि सिर्फ स्पष्टीकरण के लिए है ।)

2-2-1970 से आंध्रप्रदेश के राज्यपाल के अध्यादेश सं० 1/70 की उद्घोषणा के अंत-गति कुर्नूल, नेल्लोर और गुण्टूर जिलों के कुछ तालुकों से 'श्रीगोल जिला' के नाम से निर्मित यह नए जिले के कारण इस अधिसूचना की आवश्यकता पड़ी ।

[सं० 20]

**S. O. 207.**—In exercise of the powers conferred by the second provisototsub-section (2) of Section 4 of the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) and in modification of its notification No. 20 dated the 15th December, 1970 the Central Board of Direct Taxes hereby directs that every Income-Tax Officer appointed to be an Assistant Controller and posted to any of the Estate Duty cum Incometax Circles mentioned in Column 2 of the Schedule below shall perform his functions as Assistant Controller in the said circle to the exclusion of all other Assistant Controllers in respect of the estates of all deceased persons, who immediately before their death, were being or would have been assessed of incometax, had they derived any taxable income in any Incometax Circle, the headquarters of which lies within the revenue districts shown as corresponding entries in column 3 of the said Schedule against each of the Estate Duty cum Income tax Circles.

#### SCHEDULE

Serial No.	Name of the Circle	Jurisdiction in terms of Revenue Districts
1	2	3
1	Estate Duty cum Incometax Circle, Hyderabad.	Revenue Districts of Hyderabad, Nalgonda, Karimnagar, Adilabad, Nizamabad, Medak, Warangal, Mahabubnagar, Kurnool, Anantapur, Cuddapah and Khammam of the Andhra Pradesh State.
2	Estate Duty cum Incometax Circle, Kakinada.	Revenue Districts of West Godavari, East Godavari, Visakhapatnam, Srikakulam of the Andhra Pradesh State and the territory of Yanam in the Union territory of Pondicherry.

1

2

3

3. Estate Duty cum Incometax Revenue Districts of Chittoor, Nellore, Guntur, Krishna and Ongole of the Andhra Pradesh State.

2. This Notification shall come into force on 15-12-1970.

[No. 21]

(BALBIR SINGH, Secy.)

एत० श्री० 207.—सम्पदा शुल्क अधिनियम 1953 (1953 का 34) की धारा 4 की उपधारा (2) के तूसरे उपबन्ध और दिनांक 15-12-70 की अधिसूचना सं० 20 में संशोधन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मण्डल यह निर्देश देता है कि निम्नलिखित अधिसूची के कालम 2 में उल्लिखित किसी भी सम्पदा शुल्क-सह-आयकर सकिल में सहायक नियंत्रक के रूप में काम करेगा, लेकिन उन सभी मृत व्यक्तियों से संबंधित अन्य सभी सहायक नियंत्रकों के काम से उनका कोई संबंध नहीं होगा, जिनका मृत्यु से तब पहले आयकर जांचा जा रहा था या जांचा जाने वाला था, चाहे उन्होंने किसी भी आयकर सकिल में आयकर योग्य घात रैदा किया हो और जिसका मुख्यालय उन राजस्व जिलों के अन्तर्गत आता हो, जो प्रत्येक सम्पदा शुल्क सह-आयकर सकिलों के सामने कथित अनुसूची के कालम 3 में लिखाए गए हैं।

### अनुसूची

क्रम सं०	सकिल का नाम	राजस्व जिलों के रूप में अधिकार-क्षेत्र
1	2	3
1.	सम्पदा शुल्क सह-आयकर सकिल, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश राज्य के हैदराबाद, नासराबाद, बरीमनगर, अदलाबाद, निजामाबाद, मेदक, दारुगल, महबूबनगर, कुर्नूल, अनन्तपुर, कुड्डापा और छम्माम के राजस्व जिले।
2.	सम्पदा शुल्क-सह आयकर सकिल, काकीनाडा	आन्ध्र प्रदेश राज्य के पश्चिमी गंतादरी, पूर्वी गोदावरी, विशाखपत्तनम्, श्रीकाकुलम्, राजस्व जिले और केन्द्रशासित राज्य पाण्डीचेरी का यानम क्षेत्र।
3.	सम्पदा शुल्क, सह-आयकर सकिल, गुण्टूर	आन्ध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर, नेल्लौर, गुण्टूर, कृष्णम और ओंगोल के राजस्व जिले।

2. यह अधिसूचना 15-12-1970 से अमल में आयेगी।

[सं० 21]

बलबीर सिंह, सचिव।

(office of the Collector of Central Excise, Hyderabad)  
CUSTOMS

Hyderabad, the 28th December 1970

S.O. 208.—In exercise of the powers conferred by sub-section 34 of Section 2 of the Customs Act, 1962, the Collector of Central Excise, Hyderabad, having been appointed as the Collector of Customs within the jurisdiction of the Hyderabad Central Excise Collectorate and, in furtherance to this office Notification (Customs) No. 2/70 dated 17-12-70, in so far as it relates to the nomination of Proper Officers, hereby authorise the officers mentioned in Column 2 of the Schedule annexed hereto, to function as "Proper officers" for purpose of enforcement of the provisions of various Sections of the Customs (Amendment) Act, 1969, noted against them under Col. 3 of the Schedule. They shall function as "Proper officers" in the areas specified in column 4 of the same Schedule.

Sl. No.	Designation of Officers authorised to function as Proper Officers	Section of the Customs (Amendment) Act, 1969.	Areas within which to function as Proper Officers
---------	---	---	---

1	2	3	4
1	Super Intendent of Central Excise (Technical) I.D.O. Hyderabad I.	II-C	Areas in their respective jurisdictions NOT COVERED BY M.O.Rs. manned by a Superintendent of Central Excise OR Areas in respect of Isolated Ranges in their jurisdiction.
2	Superintendent of Central Excise (Technical) I.D.O. Hyderabad II.	II-J and II-K	
3	Superintendent of Central Excise (Technical) I.D.O. Guntur		
4	Superintendents of Central Excise (Technical) I.D.O. Vijayawada.		
5	Superintendents of Central Excise incharge of Circles.	II-C, II-J, and II-K	Areas in their respective jurisdictions NOT COVERED BY M. O. Rs. manned by a Superintendent of Central Excise OR areas in respect of Isolated Ranges in their jurisdiction but excluding area of Kakinada Port & Visakhapatnam Ports limits.
6	Superintendent Central Excise incharge of M.O.Rs.	II-C, II-J, and II-K	Areas in their respective M.O.Rs as the case may be but excluding the areas mentioned in items 1 to 5 above.

Issued from file C. No. VIII/1/5/69 CUS (T).

[No. 3/70]  
M. L. ROUTH,  
Collector.

